कल्पमेधा

कोई शाम असीमित इंटरनेट पर बिताना ऐसा ही है, जैसे आप दो घंटे से कुरकुरे खा रहे हों और आपकी भूख खत्म हो गई हो, लेकिन आपको पोषण मिला ही नहीं।

– क्लिफोर्ड स्टाल

सद्भाव की फिक्र

पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश की राजनीति में लोगों के बीच नफरत फैलाने वाले बयानों या भड़काऊ भाषणों के जरिए सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिशें चिंता का कारण बनती रही हैं। ऐसे अनेक मौके सामने आए, जिनमें किसी नेता पर राजनीतिक स्वार्थ साधने या फायदा उठाने की मंशा से ऐसी बयानबाजियां करने या नारे लगाने के आरोप लगे, जिससे सामाजिक सद्भाव बिगड़ने की आशंका पैदा हुई। मगर ऐसे नेताओं को जहां कानून के कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए था, वहां उनके प्रति पुलिस या शासन-तंत्र ने एक तरह से नरम रवैया अपनाया। शायद इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर बढ़ते नफरती भाषणों की समस्या से निपटने के लिए दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी। मगर इस मसले पर सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि वर्तमान कानून का ढांचा लोगों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने, धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या सार्वजनिक शांति को भंग करने वाली हरकतों से सक्षम तरीके से निपटता है। इसमें भारतीय दंड संहिता और अन्य संबंधित कानूनों के प्रावधान शामिल हैं।

जाहिर है, मौजूदा कानूनी प्रावधानों के संदर्भ में अदालत ने एक तरह से स्थिति स्पष्ट कर दी है। मगर इससे इतर नफरती भाषणों के जरिए अगर लोगों के बीच विद्वेष फैलाने की कोशिश की जाती है, तो इसकी नए सिरे से व्याख्या करने और उसे कानूनी दायरे में लाने की जरूरत है। इस संदर्भ में अदालत ने स्पष्ट किया कि अपराध की व्याख्या या उसे परिभाषित करना और सजा तय करना पूरी तरह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऐसे में अदालत केवल सुधारों की जरूरत की ओर विधायिका और कार्यपालिका का ध्यान खींच सकती है। अदालत की यह टिप्पणी अहम है कि नफरती भाषणों के संदर्भ में याचिकाकर्ताओं की शिकायत कानून के अभाव में नहीं, बल्कि उसके लागू होने में कमी से पैदा होती है। ऐसी शिकायतें आम रही हैं कि कानूनी प्रावधान होने के बावजूद कई मामलों में पुलिस या तो आरोपों की अनदेखी करती है या फिर कमजोर धाराओं के तहत मामला दर्ज करती है। नतीजतन, जिन गतिविधियों की वजह से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी, उसके विरुद्ध कानून लाचार नजर आता है।

दरअसल, हाल के वर्षों में कुछ नेताओं ने न केवल लोगों की भावनाएं भड़काने वाले भाषण दिए, बल्कि इस बात का खयाल रखना भी जरूरी नहीं समझा कि इससे देश में अलग-अलग समुदायों के बीच सद्भाव को नुकसान पहुंच सकता है और विषम हालात भी पैदा हो सकते हैं। मगर ऐसे आपत्तिजनक भाषण देने वाले लोगों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने को लेकर सरकारों के भीतर ईमानदार इच्छाशक्ति का अभाव दिखता रहा है। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि इस तरह की प्रवृत्ति की अनदेखी करने या सुविधाजनक तरीके से कुछ नेताओं के नफरती भाषणों के प्रति आंखें मूंद लेने का नुकसान आखिरकार आम जनता और देश को उठाना पड़ेगा। शीर्ष अदालत ने भी इसी संदर्भ में कहा कि नफरती भाषण और अफवाह फैलाने से जुड़े मुद्दे सीधे तौर पर भाईचारे, गरिमा और संवैधानिक व्यवस्था के संरक्षण से जुड़े हैं। कायदे से कुछ संवेदनशील स्थितियों के बावजूद अगर मौजूदा कानूनी प्रावधानों का दायरा सीमित है, तो यह केंद्र और राज्य सरकारों पर निर्भर है कि वे बदलते परिदृश्यों तथा चुनौतियों के मद्देनजर आगे किसी ठोस कानूनी उपाय की जरूरत पर विचार करें।

गहराती चुनौती

पश्चिम एशिया में युद्ध और उससे उपजे तनाव के कारण न केवल इसमें शामिल पक्षों के रणनीतिक मोर्चे पर, बल्कि इसके असर की वजह से दुनिया भर में आर्थिक मोर्चे पर उथल-पुथल मची हुई है। तेल और गैस की कीमतों में उछाल से ज्यादातर देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। ईंधन के लिए मध्यपूर्व के देशों पर निर्भरता के कारण आयात पर बढ़ रहे खर्च को संभालना इस समय कई देशों के लिए बड़ी चुनौती है। सबसे बड़ा संकट यह है कि ईरान और अमेरिका के बीच गतिरोध के कारण वैश्विक अस्थिरता और इससे उपजी समस्या जटिल होती जा रही है। नतीजा यह कि इसका असर कई देशों पर पड़ा है। अनिश्चितता की वजह से एक ओर शेयर बाजार में अक्सर भारी गिरावट देखी जा रही है और उतार-चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, वहीं सोने-चांदी के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे निवेशक आशंका में डूबे हैं और वे सुरक्षित निवेश के विकल्पों की ओर देख रहे हैं। जहां तक भारत का सवाल है, तो यहां की अर्थव्यवस्था पर फिलहाल कोई बड़ा असर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में देश में तेल और गैस की किल्लत के समांतर औद्योगिक उत्पादन में कमी चिंता का विषय है। विकास की रफ्तार पर इसका कितना असर पड़ेगा, इसका आकलन शायद बाद में आए, लेकिन आम आदमी के लिए मुश्किलें गहराने की ही आशंका है।

अनिश्चितता भरे इस माहौल के बीच तेल आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान का प्रभाव दिखाई दे रहा है। फिलहाल वैश्विक आर्थिक परिदृश्य नाजुक स्थिति में है। अलग-अलग स्तर पर जारी भू-राजनीतिक संघर्ष का असर कितने स्तर पर पड़ेगा, अभी इसका स्पष्ट अनुमान नहीं लगाया जा सकता। हालांकि इतना तय है कि पहले ही महंगाई और क्रयशक्ति में कमी से परेशान आम लोगों पर दबाव बढ़ेगा। जिन देशों का वित्तीय ढांचा मजबूत है और ऊर्जा के विकल्प मौजूद हैं, वहां शायद स्थिति नियंत्रण में रहे, लेकिन जो देश इस मामले में बाहर से आपूर्ति पर निर्भर हैं, उनके लिए चुनौतियां गहरी होंगी। जरूरत इस बात की है कि वैश्विक पैमाने पर आर्थिक मोर्चे पर हो रहे व्यापक नुकसानों के मद्देनजर युद्ध और तनाव जैसे हालात को खत्म करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सहित अन्य स्तर पर ठोस पहल हो।

बिगड़ते जलवायु संतुलन की तहें

वायुमंडल में कार्बन की मात्रा अत्यधिक होने पर जलवायु असंतुलन से बचाने के लिए धरती अपनी कोख में जहरीले कार्बन जमा कर लेती है। मिट्टी द्वारा कार्बन सोखे जाने की प्रक्रिया जलवायु संतुलन बनाए रखने में अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

चेतनादित्य आलोक

दुनिया भर के पर्यावरण वैज्ञानिकों के समक्ष इस समय एक बड़ी चुनौती है। यह चुनौती है धरती की कोख में कार्बन का भंडार कम होने की। यानी मिट्टी में कार्बन की मात्रा कम जमा हो रही है। सामान्यतः यह किसी को जान कर अटपटा लग सकता है, लेकिन सच यही है कि हमारी धरती वायुमंडल में कार्बन की मात्रा अत्यधिक होने के कारण जलवायु असंतुलन पैदा होने अथवा बढ़ने से बचाने के लिए अपनी कोख में जहरीले कार्बन जमा कर लेती है। ऐसा इसलिए कि जलवायु परिवर्तन के दुष्परिणामों से मनुष्यों और जीव-जंतुओं का बचाव हो सके। गौरतलब है कि मिट्टी में जमा होने वाले कार्बन की मात्रा वायुमंडल द्वारा सोखे जाने वाले कार्बन की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक होती है। कार्बन सोखने के मामले में वायुमंडल की अपेक्षा धरती की क्षमता तीन गुना अधिक होती है।

इस प्रकार देखा जाए, तो मिट्टी द्वारा कार्बन सोखे जाने की यह प्रक्रिया जलवायु संतुलन बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। खास बात यह भी है कि कार्बन अधिक से अधिक संग्रहीत करने में मिट्टी अकेले ही भूमिका नहीं निभाती, बल्कि इसमें अनेक सूक्ष्म जीवों की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो मिट्टी में घुल-मिल कर रहते हैं। इसलिए हम सभी लोग धरती और सूक्ष्म जीवों के ऋणी हैं। हमें इनका आभार मानना चाहिए, क्योंकि ये रात-दिन परिश्रम कर वायुमंडल में कार्बन कम करने का कार्य करते हैं, ताकि हमारे फेफड़ों की सेहत अच्छी बनी रहे। भारतीय संस्कृति में तो सदा से ही सभी जीवों और तत्त्वों के प्रति कृतज्ञ बने रहने और उनके साथ सम्मान, सहयोग, सहभागिता और सहायता के माध्यम से आगे बढ़ने की बात कही जाती रही है।

हमारी संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धांत 'जियो और जीने दो' का तात्पर्य ही यही है कि हम एक-दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए आपसी तालमेल के साथ जीवनयापन करें। उदाहरण के लिए मिट्टी के बिना उसमें घुल-मिल कर रहने वाले सूक्ष्म जीवों का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। वहीं, मिट्टी और सूक्ष्म जीवों के बिना मनुष्य आदि प्राणियों के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तात्पर्य यह कि सृष्टि के सभी प्राणी एक-दूसरे पर आश्रित हैं। पृथ्वी पर प्रायः सभी प्राणियों के लिए सुखमय जीवन जीने की अभिलाषा का मुख्य आधार ही परस्पर सभी जीवों और तत्त्वों के अस्तित्व को स्वीकार करना तथा उनके साथ पारस्परिकता के साथ जीना है। यही हमारे संस्कार हैं। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंध में उल्लेखित 'जीवो जीवस्य जीवनम्' इसी बात का प्रमाण है। इसे ही आधुनिक समाज में 'सहजीवन' एवं 'सह-अस्तित्व' के रूप में जाना जाता है। सामान्यतः पारस्परिक निर्भरता वाले जीवों को एक-दूसरे के साथ होने से लाभ मिलता है। शैवाल और कवक पारस्परिक 'सह-अस्तित्व' के अच्छे उदाहरण हैं। 'सहजीवन' अन्य संस्कृतियों एवं विकसित समाजों के लिए भले ही एक नया शब्द और सिद्धांत प्रतीत होता हो, लेकिन हमारी वैदिक संस्कृति का प्रधान तत्त्व ही यही है, जो अनेक अवसरों पर विविध रूपों में पल्लवित-पुष्पित होता रहा है। 'सहजीवन' का परिपोषक 'जियो और जीने दो' केवल एक सिद्धांत नहीं, बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन है।

मनुष्य की जिजीविषा से जुड़ा भारतीय मनीषा का यह कल्याणकारी दर्शन अनेक प्राचीन धार्मिक गंथों में समाहित है। जिन संस्कृतियों एवं समाजों की इस दर्शन में आस्था नहीं, वे अक्सर युद्धरत रहते हैं। अजरबैजान और आर्मेनिया का युद्ध, सूडान और म्यामां में गृहयुद्ध, चीन-ताइवान का संघर्ष, हैती में गिरोहों का आतंक, फिलीस्तीन-इजराइल और हमास युद्ध, रूस-यूक्रेन युद्ध तथा अमेरिका-इजराइल का ईरान से युद्ध इसके उदाहरण हैं। अब तक इन युद्धों और संघर्षों में बड़ी संख्या में निर्दोष लोग मारे जा चुके हैं और घायल हुए। जो बचे भी हैं, उनका जीवन शायद अब पहले की तरह कभी नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार, धरती की कोख में कार्बन का भंडार कम होने का प्रमुख कारण भी यही है कि मनुष्य ने 'जियो और जीने दो' वाले प्राचीन भारतीय जीवन दर्शन को नकार दिया। कल्पना की जा सकती है कि यदि हम मिट्टी और इसमें पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के प्रति संवेदनशील होते और अन्न की पैदावार बढ़ाने के लिए उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध उपयोग न कर मिट्टी एवं सूक्ष्म जीवों की सुरक्षा के लिए समुचित कदम उठाए होते, तो आज यह स्थिति पैदा नहीं होती।

> अब जबकि मिट्टी में कार्बन की घटती मात्रा के कारण दुनिया भर में जलवायु संतुलन बिगड़ने लगा है, तब वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने इस पर गहन शोध किया। उनका मानना है कि जलवायु में मिट्टी तथा सूक्ष्मजीवों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल, हम जिस धरती पर चलते हैं, वह केवल धूल से बनी मिट्टी भर नहीं हदै, बल्कि यह ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा 'कार्बन बैंक' है। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि मिट्टी में हवा (वायुमंडल) की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक कार्बन का संरक्षण होता है। यह कार्बन यदि मिट्टी में ही सुरक्षित रहे, तो इससे हमारा जलवायु-तंत्र संतुलित रहता है।

इसी प्रकार, हम जल और जलीय जीव-जंतुओं के अस्तित्व की परवाह नहीं करते। नदियों-तालाबों में कूड़ा-कचरा और गंदगी डाल कर उसे प्रदूषित करते रहते हैं। इसी संवेदनहीन व्यवहार का नतीजा है कि आज देश में कई जलाशय अपना अस्तित्व खो चुके हैं। आसमान में उड़ने वाले परिंदों के लिए भी हमारी संवेदना नहीं जागती।

अब जबकि मिट्टी में कार्बन की घटती मात्रा के कारण दुनिया भर में जलवायु संतुलन बिगड़ने लगा है, तब वैज्ञानिकों का ध्यान इस ओर गया और उन्होंने इस पर गहन शोध किया। अब उनका मानना है कि जलवायु में मिट्टी तथा सूक्ष्मजीवों की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। दरअसल, हम जिस धरती पर चलते हैं, वह केवल धूल से बनी मिट्टी भर नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड का एक बहुत बड़ा 'कार्बन बैंक' है। पर्यावरण वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि मिट्टी में हवा (वायुमंडल) की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक कार्बन का संरक्षण होता है। यह कार्बन यदि मिट्टी में ही सुरक्षित रहे, तो इससे हमारा जलवायु-तंत्र संतुलित रहता है। वहीं, यदि मिट्टी में संरक्षित कार्बन, कार्बन डाइआक्साइड बन कर हवा में घुल-मिल जाए, तो पृथ्वी के तापमान में तेजी से वृद्धि होगी। विज्ञान पत्रिका 'नेचर क्लाइमेट चेंज' में प्रकाशित शोध का प्रमुख निष्कर्ष यह है कि मिट्टी में कार्बन को संरक्षित रखने में पानी की बहुत बड़ी भूमिका होती है।

इस अध्ययन के अनुसार, जब मिट्टी गर्म होकर सूख गई, तब उसमें संचित कुल कार्बन का लगभग 12.2 फीसद हिस्सा मिट्टी से गायब हो गया। अमेरिका में जमीन के 48 अलग-अलग टुकड़ों को वैज्ञानिकों ने अपनी प्रयोगशाला बना कर 12 वर्षों तक शोध करने के बाद पाया कि जब मिट्टी गीली थी, तब उसमें मौजूद कार्बन की मात्रा में लगभग 6.7 फीसद की वृद्धि हुई। तात्पर्य यह कि मिट्टी में जल की मात्रा जितनी अधिक होती है, उसमें कार्बन को सोख कर अपने भीतर संरक्षित करने की क्षमता उतनी ही बढ़ जाती है। हालांकि, यह बदलाव पौधों के कारण नहीं, बल्कि मिट्टी में पाए जाने वाले सूक्ष्मजीवों के कारण आया। वैज्ञानिकों ने शोध के बाद माना कि गर्म और सूखे मौसम में सूक्ष्मजीव तनावग्रस्त रहते हैं। ऐसे में, जीवित रहने के लिए वे कार्बन का अधिक उपयोग करते हैं और फिर उसे कार्बन डाइआक्साइड के रूप में हवा में छोड़ देते हैं। वहीं, जब मिट्टी गीली होती है, तो सूक्ष्मजीव कार्बन का कम से कम उपयोग करते हैं, जो उनके विकास के लिए आवश्यक होता है। इससे वायुमंडल में कार्बन कम हो जाता है और उसकी अधिक मात्रा मिट्टी में ही संरक्षित रहती है। साथ ही, सूक्ष्मजीवों का पोषण भी बेहतर होता है। कार्बन का मिट्टी में सुरक्षित रहना सचमुच बेहद जरूरी है।

विवेक की शक्ति

महिमा सामंत

हमारे समाज में बचपन से ही हमें यह सिखाया जाता है कि दूसरों की बात मानना, सबको खुश रखना और किसी को मना न करना अच्छे संस्कार हैं। यह बात सही भी है, क्योंकि सहृदयता और सहयोग मनुष्य को बेहतर बनाते हैं। मगर कई बार यही आदत हमें ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है, जहां हम अपनी इच्छाओं, अपने समय और अपनी मानसिक शांति को नजरअंदाज करने लगते हैं। ऐसे में जीवन हमें एक महत्त्वपूर्ण पाठ सिखाता है- कभी-कभी 'ना' कहना भी उतना ही जरूरी है जितना 'हां' कहना। 'ना' कहना असभ्यता नहीं है, बल्कि यह अपने जीवन की सीमाओं और प्राथमिकताओं को समझने का संकेत है। जब हम हर किसी की बात मानते रहते हैं, तो धीरे-धीरे हमारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जाता है। हम ऐसे काम भी करने लगते हैं, जो हमें थका देते हैं या जिनसे हमें कोई संतोष नहीं मिलता। मसलन, कई बार हमें किसी शादी या समारोह में जाने का मन नहीं होता, क्योंकि हम पहले से थके हुए होते हैं या हमारे पास कोई जरूरी काम होता है। फिर भी हम केवल इसलिए चले जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे। परिणाम यह होता है कि हम न तो वहां पूरी खुशी से रह पाते हैं और न ही अपने जरूरी काम पूरे कर पाते हैं।

इसी तरह कार्यस्थल पर भी अक्सर ऐसा होता है। मान लिया जाए कि किसी सहकर्मी को अपना काम जल्दी खत्म करना है, इसलिए वह अपना कुछ काम हमें दे देता है। हम मना नहीं कर पाते और 'ठीक है, मैं कर देता हूं' कह देते हैं। धीरे-धीरे यह आदत बन जाती है और लोग यह मान लेते हैं कि हम हर बार तैयार रहेंगे। अंत में इसका असर हमारे समय, प्रदर्शन और हमारी ऊर्जा पर पड़ता है। विद्यार्थियों के जीवन में भी यह स्थिति आम है। कई विद्यार्थी केवल दोस्तों के दबाव में आकर अनावश्यक गतिविधियों में समय बिता देते हैं- कभी घंटों मोबाइल पर बात करना, कभी बिना जरूरत बाहर घूमने जाना। वे मना नहीं कर पाते और बाद में पढ़ाई का दबाव बढ़ जाता है। इन छोटी-छोटी परिस्थितियों में अगर हम विनम्रता के साथ 'ना' कहना सीख लें, तो जीवन कहीं अधिक संतुलित हो सकता है। ऐसा करना स्वार्थ नहीं है। यह स्व-सम्मान और आत्म-जागरूकता का प्रतीक है। जब हम अपनी सीमाओं को पहचानते हैं और उन्हें स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं, तो लोग भी धीरे-धीरे उसका सम्मान करना सीखते हैं।

हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ऐसे प्रसंग मिलते हैं जो 'ना' कहने के महत्त्व को समझाते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह का जीवन इसका एक मार्मिक उदाहरण है। उन्होंने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य और सिंहासन के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा ली। यह प्रतिज्ञा त्याग का अद्भुत प्रतीक थी, लेकिन कई बार वही प्रतिज्ञा उनके लिए बंधन भी बन गई। द्रौपदी के अपमान के समय वे अन्याय का खुलकर विरोध नहीं कर सके। यह प्रसंग हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि कभी-कभी गलत परिस्थिति में मौन रहना या मना नहीं करना भी अन्याय को बढ़ावा दे सकता है। स्वाभिमान के साथ कहा गया 'ना' केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं, बल्कि इतिहास की दिशा भी बदल सकता है। इसी प्रकार राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन भी एक गहरी प्रेरणा देता है। राजमहल में उन्हें सभी सुख-सुविधाएं प्राप्त थीं, फिर भी उन्होंने भोग-विलास के जीवन को 'ना' कहकर सत्य और ज्ञान की खोज का मार्ग चुना। वही सिद्धार्थ आगे चलकर गौतम बुद्ध बने और उनके विचारों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया।

इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि 'ना' कहना केवल अस्वीकार करना नहीं है। यह अपने विवेक, आत्मसम्मान और जीवन की प्राथमिकताओं को पहचानने का संकेत है। जब हम हर अनुरोध को स्वीकार करते रहते हैं, तो धीरे-धीरे हम अपने लिए समय ही नहीं निकाल पाते। मगर जब हम सोच-समझकर निर्णय लेते हैं, तब हमारा जीवन अधिक संतुलित और सार्थक बनता है।

हालांकि 'ना' कहने का तरीका बहुत मायने रखता है। इसे कठोरता या तिरस्कार के साथ नहीं कहने से अधिकतम सीमा तक बचना चाहिए। अगर हम शांत और विनम्र भाषा में कहें कि 'माफ कीजिए, इस समय मैं यह काम नहीं कर पाऊंगा' या 'अभी मेरे लिए यह संभव नहीं है', तो सामने वाले को बुरा नहीं लगता और हमारी बात भी स्पष्ट हो जाती है। सच तो यह है कि जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए हमें यह समझना होगा कि हर अनुरोध को स्वीकार करना आवश्यक नहीं है। जब हम हर चीज के लिए 'हां' कहते हैं, तो धीरे-धीरे हम खुद को खोने लगते हैं, लेकिन जब हम सही समय पर 'ना' कहते हैं, तो अपने जीवन की दिशा को बेहतर ढंग से तय कर पाते हैं।

मना करने के लिए 'ना' शब्द छोटा है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। यह हमें सिखाता है कि दूसरों की अपेक्षाओं के बीच भी अपनी खुशी, अपने समय और अपनी प्राथमिकताओं को महत्त्व देना जरूरी है। जीवन में सच्चा संतुलन तब आता है, जब हम यह समझ पाते हैं कि कहां हमें आगे बढ़कर 'हां' कहना चाहिए और कहां साहस के साथ 'ना' कहना चाहिए। कभी-कभी एक छोटा-सा 'ना' ही हमें अनावश्यक बोझ से बचा कर उस रास्ते पर ले जाता है, जहां हम अधिक शांत, अधिक संतुलित और अधिक संतुष्ट जीवन जी सकते हैं।

दुनिया मेरे आगे

> मना करने के लिए 'नहीं' शब्द छोटा है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत बड़ी है। यह हमें सिखाता है कि दूसरों की अपेक्षाओं के बीच भी अपनी खुशी, प्राथमिकताओं और अपने समय को महत्त्व देना जरूरी है। जीवन में सच्चा संतुलन तब आता है, जब हम यह समझ पाते हैं कि कहां हमें आगे बढ़कर 'हां' कहना चाहिए और कहां साहस के साथ 'नहीं' कहना चाहिए।

अस्थिरता के मोर्चे

ईरान-अमेरिका विवाद अब केवल दो देशों का मुद्दा नहीं रहा, बल्कि यह वैश्विक व्यवस्था की परीक्षा है। यदि समय रहते कूटनीतिक समाधान नहीं तलाशा गया, तो परमाणु हथियारों की होड़ एशिया को एक ऐसे विनाशकारी मोड़ पर ले जाएगी, जिसका प्रभाव पूरी दुनिया को झेलना होगा। अमेरिका की बदली हुई प्राथमिकताएं और ईरान की कठोर मुद्रा इन सबने पश्चिम एशिया को एक बार फिर अस्थिरता की ओर धकेल दिया है। पहले जहां अमेरिका ईरान में सत्ता परिवर्तन और उसके मिसाइल कार्यक्रम पर नियंत्रण को प्राथमिकता देता दिखता था, वहीं अब उसका ध्यान ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने पर केंद्रित हो गया है। इजराइल के साथ संयुक्त कार्रवाई में ईरान के शीर्ष नेतृत्व पर हुए हमलों के बावजूद वहां सत्ता परिवर्तन नहीं हो पाया। इससे अमेरिका को यह समझ आया कि आंतरिक बदलाव थोपना आसान नहीं है। इसलिए उसने अपनी प्राथमिकताओं को सीमित कर लिया है। भारत के लिए अपनी सामरिक स्वायत्तता का उपयोग करते हुए शांति दूत बनने का यही सही समय है। अमेरिका द्वारा लगाई गई आर्थिक नाकेबंदी के बावजूद ईरान को वार्ता की मेज पर लाने में सफलता नहीं मिली है।

– युगल किशोर राही, छपरा

चुनाव की कसौटी

पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव सभी जगह चर्चा का विषय बना रहा। किसकी होगी जीत, यह चर्चा कई दिनों से चल रही है। वर्ष 2011 में मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद से ममता बनर्जी अभी तक अपनी कुर्सी पर कायम हैं। ममता बनर्जी 34 वर्ष तक राज करने वाली वामपंथी सरकार को धराशायी कर सत्ता में आई थीं। वे लगातार अपराजेय रही हैं। वर्ष 2016 और 2021 के विधानसभा चुनाव में भी ममता ने विपक्षी दलों को बुरी तरह पटकनी दी और अपना वर्चस्व कायम रखा। मगर इस बार स्थिति कुछ अलग है। भाजपा ने इस बार पासा पलटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी रण में उतरे हुए थे। इस बार बंगाल चुनाव मानो महाभारत जैसा बन गया। अब आखिर किसे चुना होगा मतदाताओं ने, यह नतीजे आने पर पता चलेगा। यह चुनाव सही मायने में अग्निपरीक्षा है।

– अनित कुमार राय टिंकू, धनबाद

अनियोजित विकास

विकास की राह में सीमेंट-कांक्रीट की सड़कें कई समस्याएं भी पैदा कर रही हैं। कभी केबल, तो कभी पानी के पाइप और कभी बिजली के खंभे और कभी कुछ और कामों के लिए सड़कों की खुदाई होती है। हालांकि ये सड़कें मजबूत होती हैं। मगर बार-बार निर्माण कार्यों के लिए इसे खोदना महंगा ही नहीं पड़ता, बल्कि मरम्मत के बाद इसका स्वरूप ही बिगड़ जाता है। इस तरह आधी सड़क सीमेंट और आधी सड़क गिट्टी-डामर की बना दी जाती है। यह वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बन जाती है। दूसरी ओर सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण संबंधी है। ये सड़कें भूजल संग्रह को भी कम कर देती हैं, जिससे जल स्तर का गिरना स्वाभाविक है। अगर शहरों की सड़कें सीमेंट-कांक्रीट के बजाय गिट्टी-डामर की बनाई जाएं, तो पेड़-पौधे भी हरे-भरे रहेंगे। शहरों को सीमेंट-कांक्रीट की सड़कों से मुक्ति मिलनी चाहिए। बेहतर होगा कि केवल राष्ट्रीय राजमार्गों को ही सीमेंट-कंक्रीट से बनाया जाए।

– शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

कुदरती पोषण

अध्ययन इस बात की पुष्टि करते हैं कि बेहतर पोषण की कमी के कारण लोगों के स्वास्थ्य पर पर असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, इसके लिए जीवनशैली की भी बड़ी भूमिका है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जीवन की इस भागदौड़ में आज हर व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करता दिख रहा है। इस आपाधापी में वह भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट ले रहा है जो शरीर में आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। मगर दिनचर्या में कुछ मांसपेशियां टूटती भी रहती हैं, जिसकी भरपाई का कार्य केवल कार्बोहाइड्रेट से नहीं हो सकता है। इसके लिए पोषक तत्त्वों की आवश्यकता होती है और वह हरी पत्तियों में उपलब्ध है। अनाज से व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट को तो संतुलित कर सकता है, लेकिन मांसपेशियों को कमजोर होने से कैसे बचा पाएंगे? जबकि हरी पत्तियों का सेवन पोषण को बढ़ाने का कुदरती तरीका है।

– विकास पंडित, बड़वानी

लोकमानस

loksatta@expressindia.com

नव्या अपरिहार्य मांडणीची सुरुवात

'एमबीएस x एमबीझेड' हे संपादकीय (३० एप्रिल) वाचले. तेल निर्यात करणाऱ्या देशांच्या संघटनेतून बाहेर पडण्याचा यूएईचा निर्णय महत्त्वाच्या वेळेस तेल कार्टेलला नक्कीच कमकुवत करेल. सौदी नेतृत्वाखालील संस्थेचा भाग राहून आता काही उपयोग नाही हे लक्षात आल्यानेच हा निर्णय झाल्याचे दिसते. त्याचबरोबर संयुक्त अरब अमिरात आणि सौदी अरेबिया हे ओपेकमधील सर्वांत मोठे उत्पादक असलेले देश आणि त्यांचे नेते यांच्यात सध्या सुरू असलेल्या शीतयुद्धाचीही ही लक्षणे दिसतात. हा निर्णय अचानक झाल्याचे दिसत असले तरी, त्याचे संकेत काही काळापासून मिळत होते. यूएई आणि सौदी अरेबिया यांच्यात तेल धोरणांमधील मतभिन्नता वाढतच चालली होती. याशिवाय, यूएई बाहेर पडल्यामुळे ओपेकच्या भविष्यात बदलत्या बाजारपेठेच्या परिस्थितीला लवकर प्रतिसाद देण्याच्या क्षमतेत घट होण्याचीही शक्यता आहे. ओपेकच्या एकूण तेल उत्पादनाच्या १२ टक्के उत्पादनावर याचा प्रभाव पडले. नोव्हेंबर २०२० मध्ये ओपेक प्लसच्या शिखर परिषदेतच सौदी अरेबियाशी मतभेद स्पष्ट झाले होते. तेव्हाच यूएईने संभाव्य विभाजनाचे संकेत दिले होते. नंतर हा तणाव २०२१ च्या जुलैमध्ये झालेल्या ओपेक प्लस देशांच्या बैठकीत स्पष्टपणे दिसून आला. खरे तर हे दोन्ही गल्फ राष्ट्रांच्या वेगवेगळ्या परिस्थितीचे प्रतिबिंब आहे. सौदी नेतृत्वाखालील संघटनेचा भाग राहण्याचा आता काही उपयोग नाही हे यूएईच्या वारंवार लक्षात येत होते. अमेरिका सर्वप्रथम आपल्या स्वार्थावर लक्ष केंद्रित करीत आहे. तोच कित्ता यूएईने गिरवला आहे. ओपेकमधून बाहेर पडून आपला स्वार्थ साधण्यास प्राधान्य देणे हाच हेतू दिसून येतो. यातून यूएई आणि इतर प्रादेशिक देश अनिश्चित युद्धोत्तर परिस्थितीचा विचार करण्यास सुरुवात करताना दिसतात. नवी मांडणी अपरिहार्य आहे.

■ **प्रा. डॉ. गिरीश नाईक,** कोल्हापूर

स्वावलंबनातून तेल व्यापारवृद्धी !

'एमबीएस x एमबीझेड' हा अग्रलेख (३० एप्रिल) वाचला. इराण, अमेरिका इस्रायल युद्ध झळांचा जागतिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थेला चांगलाच फटका बसला आहे. या पार्श्वभूमीवर संयुक्त अरब अमिरातीने (यूएई) ओपेकमधून बाहेर पडण्याच्या घेतलेल्या व्यवहार्य निर्णयातून ते तेल विक्रीसाठी स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकतील. त्याच वेळी बाजारातील स्थिर दराला अस्थिर करण्याचे सोयीस्कर नियोजनही करता येईल. चीन आणि अमेरिकेसारख्या देशांना आपली बाजारपेठ सुदृढ करता येण्याची शक्यता वाढली आहे. जगभरात स्पर्धा सुरू असल्याने जो तो देश आपल्याच बाजूने सकारात्मक निर्णय घेऊ शकतो आणि तो तसा निर्णय घेण्यास मोकळा आहे. त्याचेच प्रतिबिंब म्हणजे यूएई ओपेकसारख्या तेल विक्रेत्यांच्या टोळीतून बाहेर पडला.

अरब गटातील अतिश्रीमंत धनाढ्य असलेल्या एमबीएस आणि एमबीझेड यांच्यातील वैमनस्य अखेर चव्हाट्यावर आले आणि त्यातूनच आर्थिक नाकेबंदी करण्याचे संकट उभे राहिले होते. परिणामी, यूएईने ओपेकमधून बाहेर पडून, आपले अर्थकारण जपले आहे. त्यात वावगे असे काही नसावे. तसे तर युद्धातून उद्भवणाऱ्या आर्थिक झळांनी जगभरातील सर्वच देश महाभयंकर आर्थिक चक्रव्यूहात अडकून पडले आहेत. होर्मुझ बंदरातील अडवणूक आणि तेलाच्या दरांमधील चढउतार यांतून, अवश्यकतेनुसार कमीअधिक तेल निर्यातीचे धोरण राबविण्यास यूएई स्वतंत्र झाला असला तरी महागाई, गॅस टंचाई, पेट्रोल-डिझेल यांची सुलभ दरातील निर्यात आणि तेजी मंदीच्या हेलकाव्यांनुसार दरनिश्चिती यावर व्यवहार्य निर्णय घेणे आणि स्वावलंबनातून तेल व्यापारवृद्धीसाठी समतोल निर्णय अपेक्षित असेल. तरच, ओपेकमधून बाहेर पडूनही जगातील सर्वच देश यूएईकडे एक मित्र देश म्हणून पाहतील.

■ **डॉ. नूतनकुमार पाटणी,** चिकलठाणा (छत्रपती संभाजीनगर)

दोन विकास प्रारूपांमधील संघर्ष

'एमबीएस x एमबीझेड' हा अग्रलेख वाचला. संयुक्त यूएईचा ओपेकमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय हा केवळ एका संघटनेचा अंतर्गत विषय नसून, तो एका मोठ्या जागतिक स्थित्यंतराचा आरंभ आहे. खनिज तेलासारख्या नैसर्गिक संसाधनावर केवळ भौगोलिक उपलब्धतेमुळे नियंत्रण मिळवून जगाला वेठीस धरण्याच्या वृत्तीला आता तडे जाऊ लागले आहेत. अमिरातीसारख्या महत्त्वाच्या देशाने ओपेकबाहेर पडणे हे सामूहिक हितापेक्षा आता वैयक्तिक आर्थिक प्रगती आणि सार्वभौमत्व अधिक महत्त्वाचे ठरू लागल्याचे प्रतीक आहे. एका बाजूला सौदीची आक्रमक विस्तारवादी भूमिका आणि दुसरीकडे अमिरातीची पोक्त व आधुनिक आर्थिक दृष्टी, यांतील विसंगती ही केवळ दोन नेत्यांमधील नसून दोन भिन्न विकास प्रारूपांमधील संघर्ष आहे, असे वाटते.

■ **प्रवीण डोईबळे,** अंबरनाथ (ठाणे)

हे लोकशाहीचे अपहरण

'बिनविरोध निवडीचे 'गुजरात मॉडेल'' हा 'अन्वयार्थ' सदरातील लेख (लोकसत्ता-३० एप्रिल) वाचला. विकासाचे मॉडेल म्हणून 'गुजरात मॉडेल'चा देशभर खोटा गवगवा (प्रपोगंडा) केला गेला, त्यातून भाजपला केंद्रातील सत्ताप्राप्ती सोपी झाली. परंतु हळूहळू या मॉडेलमधील फोलपणा व छुपा हेतू जनतेच्या लक्षात येऊ लागला. प्रशासकीय यंत्रणांचा प्रचंड गैरवापर करून, आर्थिक आमिषे दाखवून वा धाकदपटशाने विरोधकांनाच येनकेनप्रकारेण निवडणूक रिंगणातून हद्दपार करणे, संपवणे हेच ते मॉडेल आहे. पुढे काँग्रेसमुक्त भारत ही घोषणादेखील दिली गेली. लोकशाहीत विरोधकच संपविण्याची ही भूमिका लोकशाहीच संपविण्याची असून ती हुकूमशाहीकडे नेणारी आहे. विविध राज्यांतील निवडणुकांपूर्वी 'एसआयआर' मनमानी पद्धतीने राबविण्यात येऊन लाखो मतदारांची नावे वगळली जाणे, हाही याच मॉडेलचा सोयीस्कर विस्तार. जागतिक लोकशाही व माध्यमस्वातंत्र्य निर्देशांकातील घसरण या बिनविरोध निवडीच्याच निदर्शक आहेत. खरे तर बिनविरोध निवडीचे मॉडेल हे लोकशाहीच्या अपहरणाचे मॉडेल आहे. शिवाय देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील चुकीच्या धोरणांमुळे, खोट्या आश्वासनांमुळे विकासाचे विद्रूप स्वरूप उघड होऊन त्याचे परिणाम मात्र सामान्य माणसाला भोगावे लागताहेत.

■ **राजेंद्र फेगडे,** नाशिक

बिनविरोध की लोकशाहीविरोध ?

'बिनविरोध निवडीचे 'गुजरात मॉडेल'' हा ३० एप्रिलचा 'अन्वयार्थ' वाचला. गुजरातमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत वाढत्या बिनविरोध निवडींचा ट्रेंड दिसतो. महाराष्ट्रातसुद्धा असे बिनविरोध प्रकार घडले, पण हे वरकरणी एकमताचे, स्थैर्याचे चित्र वाटले तरी लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांशी ते विसंगत आहे. लोकशाहीची खरी ताकद स्पर्धेत, पर्यायांत आणि मतदारांच्या सक्रिय सहभागात असते. जेथे स्पर्धाच उरत नाही, तेथे लोकशाहीचा आत्माच नाहीसा होतो. त्यामुळे या प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि स्वायत्तता संशयाच्या भोवऱ्यात सापडते. यासाठी निवडणूक व लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींचा पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. बिनविरोध निवड ही जर नैसर्गिक सहमतीतून होत असेल तर ती स्वीकारार्ह; पण दबावातून होत असेल तर ती लोकशाहीसाठी इशारा आहे. बिनविरोध ही लोकशाहीची मजबुती नाही, ती तिच्या गळचेपीची सुरुवात आहे. हे मॉडेल जर वाढले, तर उद्या निवडणुका केवळ औपचारिकता उरतील आणि लोकशाही केवळ अभ्यासक्रमात नावापुरती राहील.

■ **डॉ. सुनील भारोडकर,** बुलढाणा

वृक्ष लागवड हा आकड्यांचा खेळ नव्हे

महाराष्ट्र सरकारने ३०० कोटी वृक्ष लागवडीचे उद्दिष्ट जाहीर करणे ही स्वागतार्ह बाब असली, तरी त्याच वेळी वृक्षतोडीसाठी परवानगी प्रक्रिया पंधरा दिवसांत पूर्ण करण्याचा निर्णय गंभीर प्रश्न उपस्थित करतो (लोकसत्ता- ३० एप्रिल). यामधील विरोधाभास स्पष्टपणे जाणवतो. आरे परिसरातील झाडांवर रातोरात करवत चालवली जाते, तर दुसरीकडे वाघांच्या भ्रमण मार्गात खाण प्रकल्पांना परवानगी दिली जाते. मुंबईतील मेट्रो प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग, प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्ग आणि इतर पायाभूत सुविधांच्या नावाखाली हजारो झाडे नष्ट झाली आहेत. नाशिकमधील कुंभमेळ्यासाठी तपोवन परिसरातील वृक्षतोडही चिंतेचा विषय आहे. विकासकामे आवश्यक असली तरी त्यासोबत पर्यावरणीय संतुलन राखण्याची जबाबदारी प्रशासनाने स्वीकारली पाहिजे, रस्त्यांच्या काँक्रीटीकरणासोबत दुतर्फा वृक्ष लागवड, हिरवळीचे पट्टे आणि हरित चौक उभारण्याची सक्ती केली गेली, तर विकास अधिक संवेदनशील ठरू शकतो. वृक्ष लागवड ही केवळ आकड्यांचा खेळ नसून ती दीर्घकालीन सामाजिक जबाबदारी आहे.

■ **अनिल साखरे,** कोपरी (ठाणे)

स्मरणाचा आग्रह, चिकित्सेची भीती

ज्या समाजाकडे वर्तमानातील प्रश्नांना सामोरे जाण्याची बौद्धिक ताकद उरत नाही, तो समाज भूतकाळातील प्रतीकांवर नियंत्रण मिळवण्यात ऊर्जा खर्च करू लागतो. शिवाजी महाराजांचे खरे स्मरण त्यांच्या नावाच्या उच्चारात नाही, तर न्याय, स्वाभिमान आणि दूरदृष्टी ही मूल्ये वर्तमानात जगवण्यात आहे. पण आज त्याउलटच घडताना दिसते. 'शिवाजी कोण होता?' या पुस्तकावरून उद्भवलेला वाद हे त्याचेच उदाहरण...

प्रबोधन पोळ
सहयोगी प्राध्यापक, मणिपाल अभिमत विद्यापीठ, कर्नाटक
prabodhanpol@gmail.com

अलीकडे आमदार संजय गायकवाड यांनी गोविंद पानसरे यांच्या 'शिवाजी कोण होता?' या पुस्तकाचे प्रकाशक प्रशांत आंबी यांना फोनवरून शिवीगाळ केल्याची व धमकी दिल्याची ऑडिओ क्लिप समोर आली आहे. समाजमाध्यमांवर व्हायरल झालेल्या या क्लिपमध्ये पुस्तकाच्या शीर्षकात छत्रपती शिवाजी महाराज असा सन्मानसूचक उल्लेख का नाही, यावरून ते आक्रमक भाषेत संताप व्यक्त करत असल्याचे ऐकू येते. १९८८ मध्ये प्रथम प्रकाशित झालेले हे पुस्तक शिवाजी महाराजांच्या इतिहासाची बदलत्या काळातील प्रासंगिकता काय आहे, यावर महत्त्वपूर्ण भाष्य करते. पण गायकवाड यांच्या प्रतिक्रियेतून या पुस्तकाचा आशय समजून घेण्याऐवजी त्याचा उलटा अर्थ लावला गेला, आणि महाराष्ट्रात गेल्या दोन दशकांत अधिक तीव्र होत गेलेल्या एका जुन्याच वादाला नवी धार मिळाली.

हा केवळ एका आमदाराचा वादग्रस्त संवाद नाही. या घटनेतून महाराष्ट्रातील इतिहास, अस्मिता आणि ढासळत चाललेले सार्वजनिक भान यांचे व्यापक संकट समोर येते. इथे प्रश्न केवळ सन्मानसूचक शब्दांचा नाही. खरा मुद्दा असा आहे की इतिहासावर कोणाचा ताबा राहणार, भूतकाळाचा अर्थ कोण ठरवणार आणि आदरभावना कशी व्यक्त करायची हे कोण ठरवणार. इतिहासाचा संपूर्ण गाभा, त्यातील संघर्ष, मूल्ये आणि गुंतागुंत बाजूला सारून केवळ सन्मानसूचक शब्दांनाच इतिहासाचा केंद्रबिंदू बनवले जात असेल, तर समजून घेण्याऐवजी उच्चारालाच महत्त्व उरते. अशा वेळी इतिहास हा विचाराचा विषय न राहता, शिस्तीचा, आदेशाचा आणि भीतीचा विषय बनतो.

म्हणूनच महाराष्ट्रात भूतकाळाविषयी मुक्त आणि चिकित्सक चर्चा करणे दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. इतिहासाचे स्मरण आता विचारासाठीचे अवकाश न राहता, अभिमान, राग, ध्वज, नारे आणि दंडक यांचे राजकारण ठरले आहे. अशा वातावरणात इतिहास समजून घेण्यापेक्षा त्याचे प्रदर्शन करणे महत्त्वाचे मानले जाते. प्रदर्शनाची ही संस्कृती सुरू झाली की विचार मागे पडतो, भीती सार्वजनिक संस्कृतीचा भाग होते, आणि प्रश्न विचारणारा माणूस शत्रू ठरतो. हाच सध्याच्या संकटाचा गाभा आहे.

पानसरे यांनी त्यांच्या पुस्तकात शिवाजी महाराजांची प्रतिमा सांप्रदायिक आणि संकुचित इतिहासकथनांपासून वेगळी करून आधुनिक संदर्भात मांडण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांच्या मते, शिवाजी महाराजांनी आपल्या काळातील अन्यायकारी सत्तांविरुद्ध संघर्ष केला; शेतकरी, स्त्रिया, सामान्य जनता आणि विविध धर्मीय प्रजेला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. म्हणूनच 'शिवाजी कोण होता?' हा प्रश्न केवळ चरित्रविषयक नाही, तर ऐतिहासिक आणि सामाजिक अर्थाने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. पण हे सारे समजून घेण्याऐवजी संपूर्ण वाद केवळ सन्मानसूचक शब्दांभोवतीच फिरत राहतो. ही आपल्या समाजाची मोठी शोकांतिका आहे की, भूतकाळाशी विधायक, निर्भय आणि चिकित्सक संवाद साधण्याऐवजी आपण त्याच्याभोवती भीती, संशय आणि बंदीची वलये उभी केली आहेत.

गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत महाराष्ट्रात अशा प्रकारे उफाळून आलेले वाद आपल्या गडद होत चाललेल्या वैचारिक संकटाचे बोलके प्रतिबिंब आहे. हा आग्रह अनेकदा इतिहासाच्या गुंतागुंतीला सपाट करून टाकतो. शिवाजी महाराजांचे योगदान अत्यंत मोठे आहे, याबद्दल दुमत नाही. मात्र त्या योगदानाचा अर्थ फक्त भाषिक शिस्तीपुरता मर्यादित करून टाकणे किंवा त्यांच्या नावाचा वापर सामाजिक जमावाला उभे करण्यासाठी करणे, हे त्यांच्या महत्तम कार्याचे अवमूल्यनच ठरते. महामानवांचे स्मरण हे प्रश्न विचारण्यासाठी असावे; प्रश्नांना बंद करण्यासाठी नव्हे. जेव्हा असे वाद उसळतात, तेव्हा तो केवळ शिष्टाचाराचा मुद्दा नसतो; तो इथल्या समाजातील खोल अस्वस्थतेचे लक्षण असते.

ही अस्वस्थता केवळ एका समाजगटापुरती मर्यादित नाही. अनेक जातीसमूहांमध्ये इतिहासाविषयीच्या स्पर्धा वाढताना दिसतात. शेतकरी आणि ग्रामीण समाजावर आज आर्थिक संकट, बेरोजगारी, अनिश्चितता आणि सामाजिक संक्रमण यांचा मोठा दबाव आहे. अशा परिस्थितीत इतिहासातील प्रतीके अधिक आक्रमकपणे वापरली जात आहेत. पण प्रतीकांचे हे राजकारण प्रत्यक्ष समस्यांकडे दुर्लक्ष करण्याचे आवरण ठरते. सन्मानसूचकतेवर बोलणे सोपे आहे; परंतु शिक्षण, नोकरी, जमिनीची असुरक्षितता, शेतीची घसरण आणि तरुणांच्या भवितव्याचा प्रश्न सोडवणे कठीण आहे. म्हणूनच सन्मानसूचकतेचा वाद अनेकदा व्यापक सामाजिक संकटांपासून लक्ष विचलित करणारा ठरतो.

दुर्दैवाने, महाराष्ट्रात इतिहासाची चिकित्सा कमकुवत होत चालली आहे. गेल्या दीडशे वर्षांत इथे उगम पावलेल्या सामाजिक चळवळींनी आणि पुरोगामी विचारवंतांनी इतिहासाकडे चिकित्सक नजरेने पाहण्याची दृष्टी घडवली होती. पण आज भूतकाळाला शौर्याच्या एकाच चौकटीत बंद केले जात आहे. चिकित्सेची जागा भावनिक घोषणांनी, श्रद्धेच्या विशिष्ट चौकटीच्या सक्तीने आणि अपमानाच्या राजकारणाने घेतली आहे. त्यामुळे इतिहासाचे वाचन कमी आणि त्याचे नियंत्रण अधिक सुरू आहे, हे प्रकर्षाने दिसते.

इतिहासाला जर फक्त श्रद्धेचा विषय बनवले, तर विचार मरतो. आणि विचार मेला की लोकशाही कमकुवत होते. त्यामुळे अशा प्रकारचा वाद केवळ शिष्टाचाराचा किंवा भाषिक संहितेचा प्रश्न नसून स्मृतीवर नियंत्रण मिळवण्याचा सत्ताव्यवहारही आहे. महाराष्ट्राला शिवाजी महाराजांचे स्मरण हवेच; पण ते स्मरण प्रश्न विचारणारे, विवेक जपणारे आणि सामाजिक वास्तवाशी भिडणारे हवे. सन्मानाची भाषा महत्त्वाची आहे; पण सन्मानाच्या नावाखाली चिकित्सेवर, विचारावर आणि व्यापक चर्चाविश्वावर घाला घालणे, हे सार्वजनिक जीवन अधिकच गरीब करते.

महाराष्ट्राची समृद्धी आज मुख्यतः भौतिक साधनसंपत्तीपुरती उरली आहे आणि तीही हळूहळू क्षीण होत चालली आहे. परंतु समाजासमोर उभी राहत असलेली संकटे पाहिली, तर महाराष्ट्र वैचारिक, सांस्कृतिक आणि सामाजिक अर्थाने आधीच दरिद्री होत चालल्याचे दिसते. ही अवस्था आपल्या सामूहिक दारिद्र्याची, अधोगतीची आणि सार्वजनिक जीवनातील क्षयाची गंभीर निशाणी आहे.

या पार्श्वभूमीवर इतिहासाभोवती उभे केले जाणारे असले वाद अधिकच अर्थपूर्ण ठरतात. ज्या समाजाकडे वर्तमानातील प्रश्नांना सामोरे जाण्याची बौद्धिक ताकद उरत नाही, तो समाज भूतकाळातील प्रतीकांवर नियंत्रण मिळवण्यात ऊर्जा खर्च करू लागतो. शिवाजी महाराजांचे खरे स्मरण त्यांच्या नावाच्या उच्चारात नाही, तर न्याय, स्वाभिमान आणि दूरदृष्टी ही मूल्ये वर्तमानात जगवण्यात आहे. पण आज त्याउलटच घडताना दिसते. महाराष्ट्रात वैचारिक देवाण-घेवाण आणि इतिहासाला विशिष्ट संकुचित जातीय आणि प्रतीकात्मक चौकटीत बांधून ठेवणे हीच जणू नवी नीती झाली आहे; आणि हे चित्र लवकर बदलेल, अशी आशा ठेवणेही दिवसेंदिवस कठीण होत चालले आहे. तोपर्यंत इतिहासाच्या जयघोषात वर्तमानातील अपयश झाकण्याचा हा खेळ सुरूच राहील, हेच अधिक संभवनीय वाटते.

कुतूहल

धुकं का पडतं ?

थंडीच्या दिवसांत, हव्याशा वाटणाऱ्या रात्रीच्या गुलाबी थंडीबरोबर नकोसं वाटणारं सकाळचं धुकंसुद्धा आपल्या वाट्याला येतं. या धुक्यामुळे आपल्या डोळ्यांना काही फुटांवरचंसुद्धा दिसेनासं होतं. दृश्यमानता कमी झाल्याने अपघातांची शक्यता वाढते. विमानं आणि रेल्वेगाड्या रद्द होतात. माणसाच्या आरोग्यावर धुक्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

खरं तर धुकं म्हणजे जमिनीलगत असलेला ढगच असतो. धुक्यात हवेत तरंगणारे पाण्याचे सूक्ष्म थेंब असतात. धुकं हे प्रामुख्याने थंड हवामानात, विशेषतः हिवाळ्यात सकाळी पडतं. कारण हिवाळ्यात रात्री तापमान कमी झाल्याने रात्री आणि पहाटे हवा आणि जमीन थंड होते.

धुकं पडण्यासाठी हवेतली आर्द्रता साधारण ९५ टक्के किंवा त्याहून अधिक असावी लागते. हवेत असलेली ही आर्द्रता म्हणजेच पाण्याचं बाष्प हे जेव्हा या थंड वातावरणाच्या संपर्कात येतं, तेव्हा हवेचं तापमान अचानक कमी होतं. अशा वेळी हवेची बाष्प साठवून ठेवण्याची क्षमता संपते आणि हवेत असलेल्या या बाष्पाचं थंडीमुळे पाण्याच्या सूक्ष्म थेंबांमध्ये रूपांतर होतं. हे पाण्याचे थेंब हवेत तरंगत राहतात आणि त्यामुळे धुकं तयार होतं.

अजून एका परिस्थितीत धुकं तयार होतं. जेव्हा उष्ण आणि दमट हवा अचानक थंड जमिनीवरून किंवा थंड पाण्याच्या प्रवाहावरून वाहते, तेव्हाही त्या उष्ण हवेतील बाष्प थंड होऊन त्याचं धुक्यात रूपांतर होतं. अशा प्रकारचं धुकं हे आपल्याला समुद्रकिनारी पाहायला मिळतं.

जमिनीच्या पृष्ठभागाजवळील हवा जास्त थंड होते. त्यामुळे हे बाष्पकण तिथेच साचतात. तिथल्या धुळीतल्या कणांवर हे थेंब जमा होतात आणि हवेत तरंगतात. यामुळे वातावरण धूसर दिसतं. ही धूसरता जमिनीच्या जवळ म्हणजे साधारण १ ते २ मीटर्स उंचीपर्यंत असते, म्हणून आपण धुकं 'पडलंय' असं म्हणतो.

हवेत जेवढे जास्त धूलिकण किंवा धुराचे कण असतील, तेवढं धुकं जास्त दाट होतं. कारण असे कण हे 'केंद्रक' म्हणून काम करतात आणि त्यांच्यावर पाण्याचे थेंब जमा होतात.

जेव्हा हवेत प्रदूषण जास्त असतं, तेव्हा हे प्रदूषक नैसर्गिक धुक्यात मिसळतात. या मिश्रणाला धुरकं किंवा 'स्मॉग' म्हणतात. याला धुराचा किंवा रसायनांचा उग्र वास येतो. अशा धुरक्यामुळे फुप्फुसांचे विकार, डोळ्यांची जळजळ आणि श्वसनाचे त्रास होतात.

सूर्य उगवल्यानंतर मात्र हे धुकं विरतं. सकाळी सूर्यप्रकाशामुळे हवा गरम होते आणि पाण्याचे हे सूक्ष्म थेंब पुन्हा वाफेत बदलतात, त्यामुळे धुकं हळूहळू नाहीसं होतं. हिवाळ्यात सकाळी सूर्यप्रकाश कमी असतो. त्यामुळे धुकं बराच वेळ टिकून राहतं.

– मकरंद भोंसले
मराठी विज्ञान परिषद
ईमेल : office@mavipa.org
संकेतस्थळ : www.mavipa.org

व्यक्तिवेध

मानवाच्या उत्क्रांतीत आणि त्याच्या गुणावगुणांत जनुकीय अनुक्रम अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. हा अनुक्रम निश्चित करण्याच्या क्रांतिकारक प्रयोगाचे सह-नेतृत्व करणारे जीवशास्त्रज्ञ जॉन क्रेग व्हेंटर यांचे नुकतेच निधन झाले. हृदयरोगापासून अल्झायमर्सपर्यंत अनेक गंभीर विकारांची कारणे निश्चित करणे आणि त्यावरील उपचार शोधून काढण्याचा मार्ग त्यांच्या या प्रयोगामुळे सुकर झाला. प्रयोगाला 'जीवनग्रंथ' अशा शब्दांत गौरविण्यात आले, पण विज्ञानात अंतिम सत्य काहीच नसते, याचे भान असणाऱ्या व्हेंटर यांनी एवढ्या मोलाच्या योगदानाचेही वर्णन, 'आम्हाला काही प्रमाणात यश मिळाले आहे. परंतु, मानवी जिनोमचा अनुक्रम जाणून घेण्यात अद्यापही अपेक्षित प्रगती साध्य झालेली नाही. हा या जीवनग्रंथाचा पहिला खर्डा आहे,' अशा नम्र शब्दांत केले.

जॉन क्रेग व्हेंटर

सॉल्ट लेक सिटी येथे जन्मलेल्या व्हेंटर यांनी विद्यार्थीदशेतील सर्वाधिक काळ बोटीतून विहरण्यात किंवा सर्फिंग बोर्डवरून लाटांवर स्वार होण्यात घालवला. साहजिकच प्रगतिपुस्तकात नेहमीच 'क' आणि 'ड' श्रेणी मिळत असे. आपले असे वर्तन 'अटेन्शन डेफिसिट हायपर ॲक्टिव्हिटी डिसऑर्डर'चा (एडीएचडी) भाग होते, असे निरीक्षण त्यांनी मोठेपणी व्यक्त केले. स्वतःच्याच डीएनएचा अभ्यास करून 'एडीएचडी'ला कारणीभूत ठरणारे जनुकांचे प्रकार शोधून काढले.

व्हेंटर यांना वैद्यकशास्त्राविषयी स्वारस्य निर्माण झाले ते व्हिएतनाम युद्धामुळे. त्यांना इच्छेविरोधात नौदलात 'मेडिकल कॉर्प्समन' म्हणून सेवा बजावणे भाग पडले. युद्धातील क्रौर्याचे त्यांच्या मनावर एवढे विपरीत परिणाम झाले की त्यांनी आत्महत्येचा प्रयत्न केला. मात्र यातूनच त्यांची वैद्यकशास्त्राविषयीची ओढ वाढली. ते शास्त्रज्ञ म्हणून घडले सॅन दिएगोमध्ये. १९७० च्या दशकात त्यांनी बायोकेमिस्ट्रीमध्ये पदवी आणि फिजिओलॉजी व फार्माकोलॉजीमध्ये डॉक्टरेट मिळवली. जिनोमिक्सच्या क्षेत्रातील आघाडीच्या कंपन्यांचे नेतृत्व केले आणि नोबेल पारितोषिक विजेते हॅमिल्टन स्मिथ यांच्यासह अनेक मातबरांबरोबर संशोधन केले.

पुढे त्यांनी 'सेलेरा जिनोमिक्स' या कंपनीची स्थापना केली. १९९८ मध्ये त्यांनी 'होल-जिनोम शॉटगन सिक्वेन्सिंग' नावाच्या एका वेगवान नवीन तंत्राचा वापर करून मानवी जीनोमचा अनुक्रम निश्चित (जिनोम सीक्वेन्सिंग) करण्याचा एक खासगी प्रयत्न सुरू केला. त्याच वेळी 'ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट'मध्येही याच स्वरूपाचे प्रयोग सुरू होते. दोन वर्षांनी व्हेंटर आणि 'ह्युमन जिनोम प्रोजेक्ट'ने जाहीर केले की त्यांनी संयुक्तपणे जिनोमचा पहिला मसुदा तयार केला आहे- 'जीवनग्रंथ' म्हणून नावाजलेला प्रयोग तो हाच.

मार्च २००४मध्ये त्यांनी एक सागरी जीनोम संकलन प्रकल्प हाती घेतला. सागरी सूक्ष्मजीवांमधील आनुवंशिक वैविध्यांचे मूल्यांकन करून निसर्गाच्या मूलभूत प्रक्रियांमधील त्यांची भूमिका समजून घेणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश होता. ४ मार्च २००४ रोजी या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली. यात व्हेंटर यांनी त्यांच्या खासगी मालकीच्या नौकेतून कॅनडातील हॅलिफॅक्स येथून प्रवास सुरू केला आणि जगप्रदक्षिणा करून जानेवारी २००६ मध्ये ते अमेरिकेत परतले. त्याच वर्षी त्यांनी 'जे. क्रेग व्हेंटर इन्स्टिट्यूट' या ना नफा तत्त्वावरील संस्थेची स्थापना केली. ही संस्था संश्लेषित जीवशास्त्रात (सिंथेटिक बायोलॉजी) संशोधन करते.

बुधवारी (२९ एप्रिल) ७९ व्या वर्षी त्यांचे कर्करोगामुळे निधन झाले. सत्तरीत विमान उड्डाणाचे प्रशिक्षण घेणाऱ्या व्हेंटर यांनी कधीही वयाला शिक्षण, प्रशिक्षण, संशोधनात अडथळा मानले नाही. अखेरच्या टप्प्यापर्यंत ते कार्यरत होते.

राजवाडे विचारविश्व

मोहिमाबाद : पुण्याचे अन्वर्थक नाव

पानिपतच्या युद्धातील मराठ्यांच्या पराभवाची चिकित्सा अस्सल ऐतिहासिक साधनांच्या आधारे करण्याचा जो अभिनव उपक्रम वि. का. राजवाडे यांनी साधनग्रंथाच्या पहिल्या खंडाच्या त्या प्रस्तावनेच्या निमित्ताने सुरू केला होता, तो अधिक साधनांच्या अभावी प्रामाणिकपणे आवरता घेत असतानाही त्यांनी जाता जाता अबदालीबद्दल नोंदवलेला अभिप्राय त्रोटक असला, तरी महत्त्वाचा होता. त्यांनी लिहिले '१४ जानेवारी १७६१च्या युद्धात अबदालीने कोणते डावपेच केले, ते अस्सल पुराव्यांच्या अभावामुळे निर्देशिता येत नाहीत. परंतु अबदालीने आपण होऊन अमुक एक डावपेच केला व तो सदाशिवरावाला भोवला, असे क्वचितच उदाहरण सापडेल. अबदालीने अमुक एक डाव योजला व त्यामुळे सदाशिवराव फसला, असा प्रकार मुळीच झाला नाही. मराठ्यांच्या लष्करात दुही झाली, ती अबदालीच्या पथ्यावर पडली. त्या दुहीचा त्याने चांगला फायदा करून घेतला. मराठे आपल्यापेक्षा जोरदार आहेत, हे अबदाली जाणून होता. तेव्हा मराठे उपासमारीने अर्धमेले होऊन जाईस्तोपर्यंत त्यांच्याशी युद्ध करावयाचे नाही, हा जो 'फेबियन' डावपेच, तो अबदालीने चांगला उपयोजिला, यात शंका नाही.'

अबदालीच्या डावपेचांबाबत राजवाड्यांनी वापरलेले 'फेबियन' हे विशेषण त्यांचा इतिहासाचा, विशेषतः युद्धशास्त्राचा व्यासंग दर्शवणारे होते.

हा शब्द एका रोमन सेनापतीशी जोडला गेलेला आहे. क्विंटस फेबियस मॅक्झिमस नावाच्या त्या सेनापतीने हॅनिबॉल या विख्यात योद्ध्याला हरवण्यासाठी वापरलेल्या वेळकाढू व संधिसाधू धोरणाला 'फेबियन' म्हटले जाते. अबदालीच्या धोरणाला अगदी चपखल बसणारे ते विशेषण राजवाड्यांनी वापरले खरे; पण 'शत्रूच्या युक्ती (वा शक्ती)पेक्षा मराठे मोहीम हरले, ते गोविंदपंताच्या कुचराईमुळे, हा सिद्धांत मात्र सर्वत्र मान्य व्हावा, असा दिसतो', हा त्यांचा निष्कर्ष अधोरेखित करायला त्यांनी मागेपुढे पाहिले नाही.

पराभवाची साधनांच्या आधारे चालवलेली चिकित्सा जरी राजवाड्यांनी आटोपती घेतली, तरी त्यांची प्रस्तावना मात्र तेथेच थांबली नाही. या निमित्ताने त्यांच्या अभ्यासादरम्यान लक्षात आलेल्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरचे साक्षेपी विवेचन त्यांनी पुढे चालूच ठेवले आणि काही रंजक ऐतिहासिक माहितीसुद्धा संकलित स्वरूपात वाचकांसमोर ठेवली. आज दि. १ मे आहे. आजच्या महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या ऐतिहासिक राजधानीविषयीची राजवाड्यांनी पुरवलेली काहीशी वेगळी माहिती जाणून घेऊया.

इतिहासाचे भूगोलाशी असणारे जवळचे नाते या ज्येष्ठ संशोधकांनी किती बारकाईने अभ्यासले होते, हे दाखवून देणारी ती नोंद अशीः

'सतराव्या व अठराव्या शतकांत महाराष्ट्रातील लोकांच्या अंगी स्थितीपेक्षा गतीचेच विशेष प्राबल्य होते. पावसाळ्याचे चार महिने खेरीज करून बाकीचे आठ महिने मराठे पुण्याहून दाही दिशांना पसरत असत. अठराव्या शतकात मराठ्यांच्या गतीचे मुख्य केंद्र पुणे शहर होते. मुसलमानांच्या कारकीर्दीतही पुण्याचे ठिकाण मोहिमांची सुरुवात करण्यास सोयीचे समजले जात असे व त्याच्या या सोयीस्कर स्थानावरून त्यांनी त्याला 'मोहिमाबाद' असे अन्वर्थक नाव दिले होते. सातारा व सासवड ही स्थळे सोडून पेशव्यांनी आपले ठाणे पुण्यास दिले, त्याचेही मुख्य कारण हेच. हिंदुस्थानात, कोकणात, गुजराथेत, श्रीरंगपट्टणास व निजामाच्या राज्यात जाण्यास पुण्याच्या मैदानातून अनेक रस्ते फुटतात...' आणि मग राजवाड्यांनी मुख्य १८ मार्गांचा व मुक्कामांचा तपशीलही जोडला. त्यातले काही निवडक येथे केवळ माहितीसाठी...

- पुणे ते नाशिक : पुणे- भांबरी- भोसरी- मोसे- चाकण- खेड- पेठ- लिंगदेव- भोगूर- गोवर्धन- त्र्यंबिक- नाशिक.
- पुणे ते वसई, ठाणे, पनवेल : पुणे- पुनावळे- तळेगाव- नाणे- माहू- कुसूरघाट-भिरुपुरी वैजनाथ- नसरापूर- दहिवली- बदलापूर- कल्याण- वसई- परशीत- ठाणे-तळेगाव- वडगाव- कार्ले- बोरघाट- खालापूर- चौक- पनवेल- मुंबई.
- पुणे ते रायगड : पुणे- खडकवासले- खामगाव- पादघ्राचा घाट- येल्याची पेठ-बोचाघोळी- रायगड.
- पुणे ते श्रीरंगपट्टण : पुणे- पंढरपूर- आसंगी- कवतगी- गळतगे- बागलकोट- बदामी कुरुतकोटी- लक्ष्मेश्वर- सावनूरबंकापूर
- पुणे ते दिल्ली : पुणे- औरंगाबाद- अजंठा- बऱ्हाणपूर- हांडिया- सीहूर- सीरोंज- नरवर- ग्वाल्हेर- ढवळपूर- आग्रा- मथुरा- दिल्ली...
- पुणे ते नागपूर : पुणे- औरंगाबाद- दाभाडी- जाफराबाद- बाळापूर- अलजपूर- नागपूर.
- पुणे ते भागानगर : पुणे- सुपे- बारामती- तुळजापूर- कल्याण- बेदर- भालकी- उदगीर- गोवळकोंडा- भागानगर

पुण्याहून फुटणाऱ्या मोठमोठ्या मार्गांपैकी काहींचा हा ठोकळ तपशील आहे'

– आनंद हर्डीकर
anand47.hardikar@gmail.com

विकासग्रस्तांची विदारक वाताहत

आणखी दोन दशकभरात महासत्तापदाचे स्वप्न पाहणारा हा देश प्रत्यक्षात 'राहणीमान निर्देशांका'त दिवसेंदिवस घसरू लागलेला आहे हे वास्तव आपण पाहणार की नाही?

केवळ कंत्राटांतील मलिद्यावर डोळा ठेवून कामे काढणारे राजकारणी, शहर नियोजन कशाशी खातात याची काडीचीही जाण नसलेले सत्ताधीश आणि या अशा राज्यकर्त्यांमुळे आपल्या कर्तव्यांबाबत कमालीचे बेफिकीर अधिकारी एकत्र आले की काय होते त्याचे भयानक दर्शन म्हणजे सध्याचा महाराष्ट्र. या राज्याच्या राजधानी मुंबईतून बाहेर पडण्याच्या मार्गावर बुधवारी रात्री तब्बल पाच तास वाहतूक ठप्प होती हे एकच एक कारण या निष्कर्षामागे नाही. अलीकडे पुणे-मुंबई घाटातील अपघातानंतर अशीच स्थिती उद्भवलेली होती. मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांतून शहरात येणे आणि रात्री घरी परतणे हे अतिमागास आफ्रिका खंडातील वा सत्ताधीशांस प्रिय गोपट्ट्यातील राज्याइतकेच हलाखीचे. मुंबईहून उपराजधानी नागपूरला जोडणाऱ्या समृद्धी महामार्ग निर्मितीचे सरकारला कोण कौतुक. पण मुंबईतून या समृद्धी महामार्गाच्या तोंडापर्यंत पोहोचणे हेच मोठे दिव्य. ते पार केल्यानंतर मग कथित समृद्धी महामार्गाचा वाळवंटी प्रवास. मुंबईत मेट्रोचे जाळे उभारणीचे श्रेय घेताना २० मिनिटांच्या मेट्रो प्रवासाआधी आणि नंतर अर्धा-अर्धा तास प्रतीक्षा करावी लागते त्याचे काय, याचे उत्तर नाही. एकीकडे जुन्याजाणत्या विश्वसनीय अशा 'बेस्ट' बस सेवेची हेळसांड करायची आणि नव्या कंत्राटी उद्योगांचा पाठपुरावा करायचा हा या सत्ताधीशांचा विकास (?). आता नवे काय तर 'पॉड टॅक्सी'. जुन्या 'स्काय वॉक'चा खुराक संपला. ते मोडूनही खाल्ले. आता नवे पूल. पुण्यात आणि आसपासच्या रस्त्यांवर खास शहर बस सेवेसाठी उभारलेल्या विशेष मार्गिकेच्या कलेवरांवरून दुचाक्यांपासून ते मालगाड्यांपर्यंत सर्व गाड्या सर्रास जातात. तो प्रकल्प असाच बोंबलला. त्याचा आणि अशा अन्य प्रकल्पांचा खर्च पाण्यात. आणि विचार फक्त जनतेच्या पैशातून नवनवी कंत्राटे कशी देता येतील आणि त्यात किती हात मारता येईल, याचा. या असल्या बेजबाबदार सत्ताकारणामुळे आपण विकसित सोडा, पण काही अंशी बऱ्या अवस्थेतून भिकारावस्थेकडे जोमाने मार्गक्रम करत आहोत याची जाणीव राज्यकर्त्यांस नसेल; पण आपणास तरी आहे?

याचे प्रामाणिक उत्तर अतिविकासाच्या वजनाखाली गुदमरून चाललेली शहरे आणि किमान विकासाअभावी सुकत चाललेली खेडी या दोन्हींपैकी एकाचा तरी अनुभव घेणे नशिबी आलेल्याने द्यावे. जेमतेम १५ मिनिटांच्या अंतरासाठी पाच-सहा तासांच्या कोंडीत जेव्हा अडकावे लागते तेव्हा अन्न-पाण्याच्या अभावामुळे मुलाबाळांचे होणारे हाल आणि बायाबापड्यांची स्वच्छतागृहाअभावी होणारी कुचंबणा याची जाणीव आपल्या विकासपुरुषांस असणे शक्य नाही. या विकासपुरुष आणि विकासपुरंध्र्यांचे सरकारी गाड्यांचे काफिले अशा वाहतूक कोंडीतही निर्लज्जपणे सर्व नियम तोडून उलट दिशेने सुखाने मार्गक्रमण करू शकतात. हा सत्तेचा माज मिरवणे बंद करण्यासाठी वाहनांवरील लाल दिवे आम्ही कसे काढून टाकले असे आपणास सांगितले गेले आणि बावळट समाजाने 'कित्ती महत्त्वाचा निर्णय हो...' असे म्हणत या साधेपणाचा आव आणणाऱ्या निर्णयाचे कोण कौतुक केले. लाल दिवे गेले असतीलही. पण या मंत्र्यांसंत्र्यांच्या पुढच्या मागच्या गाड्यांची संख्या वाढली. घटनेनुसार जे पद अस्तित्वातच नाही त्या पदावरील व्यक्तीच्या ताफ्यात २५-२५ मोटारी असतात आणि नागरिकांच्या नाकावर टिच्चून रोंरावत जाताना या मंडळींस जनाची लाज नसते आणि मनाची असण्याचा प्रश्नच नसतो. हा झाला आहे इतका विकास कमी म्हणून की काय आता अरुंद गल्ल्यांतही गगनचुंबी इमारतींस परवानगी देण्याचा निर्णय आपल्या विकासाभिमुख सरकारने अलीकडेच घेतला. गरज पडल्यास अग्निशमन दलाच्या गाड्यांना तिथे पोहोचता आले नाही तरी चालेल, नागरिकांस येण्याजाण्यास पुरेसे मार्ग नसले तरी चालतील, वाहनांस रस्त्यांवर उभे करावे लागत असेल तरीही हरकत

> **...त्याकडे आतासारखे दुर्लक्षच करत राहिलो तर विकास होईल, शंभर मजली इमारती येतील, चकचकीत मेट्रो तयार होतील, बुलेट ट्रेन सुसाट धावेल. पण सामान्यांचे जगणे होते त्यापेक्षा अधिक वाईट होत राहील.**

नाही; पण 'विकास' हवा. विकास असला की विकासक येतात, त्यांचे वाढते चटई क्षेत्र येते, पाणथळ जागा बुजवण्याची संधी येते, मिठागरे बुजवून इमारती बांधण्याची गरज निर्माण होते. कोणा एका बड्या सरकारस्नेही उद्योगपतीस अनेक झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासाची कंत्राटे देता येतात आणि हे सगळे होत राहिले तर(च) निवडणुकीस हवा तितका निधी मिळत राहतो. तेव्हा विकास हवाच हवा. या विकासाच्या विशेषणांवर हिंदू-मुस्लीम इत्यादी धर्मभावनांचे अनुस्वार पखरले, पुढे-मागे वीररसपूर्ण उद्गारचिन्हे पसरली की झाले. खुळचट जनता खूश. हे आपले वास्तव. आज १ मेच्या महाराष्ट्र दिन मुहूर्तावर पुणे-मुंबईस जोडणारी एक नवी मार्गिका खुली होईल. तिच्या फायद्या-तोट्याचे मूल्यमापन राहिले दूर; पण हिशेबाची शाईही वाळली नसेल तर लगेच चर्चा कसली सुरू? तर या मार्गावर आणखी अर्धा डझनभर बोगदे कसे करता येतील. अधिक कामे म्हणजे अधिक कंत्राटे, म्हणजे ती देणाऱ्यांची अधिक कमाई.

हे आपले आजचे वास्तव. जनतेस गरज असो वा नसो; कामे काढत राहायची हे आपल्या सत्ताधीशांचे ब्रीद. दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत त्याचा प्रत्यय येतो. 'बीबीसी'ने अलीकडेच या भारतीय विकासकामांवर विस्तृत वृत्तांत प्रकाशित केला. त्यानुसार अलीकडे वर्षाला जवळपास दहा हजार कोटी डॉलर्स- सुमारे नऊ लाख ५० हजार कोटी रुपये- आपल्याकडे विमानतळ, मेट्रो आदींवर खर्च होत आहेत. पण ''प्रवासी/ वापरकर्ते आहेत कुठे'', असा प्रश्न हा वृत्तांत विचारतो. प्रचंड गवगवा झालेली मुंबई मेट्रो अपेक्षेपेक्षा निम्म्या प्रवाशांनाही वागवत नाही आणि उत्तर प्रदेशादी राज्यांतील अनेक विमानतळांवर विमाने सोडून सर्व काही आहे. सर्वाधिक परतावा मिळतो दिल्ली मेट्रोतून. तरीही तो ४८ टक्के इतकाच. परिस्थिती इतकी गंभीर की संसदेच्या समितीसही या सगळ्या वास्तवावर आपल्या अहवालात भाष्य करावे असे वाटले. या सगळ्यामुळे शहरांतील जीवनमान सुधारते आहे म्हणावे तर त्या आघाडीवरही ठणठणाट. इतके दिवस दिल्लीतील हवा श्वसनयोग्य नव्हती. आता मुंबई, पुणे, नागपूर आदी शहरांचीही त्यात भर पडलेली आहे. अन्यत्र असे काही मोजण्याची सोय नाही. त्यामुळे तेथील परिस्थिती बरी असेल असे मानायचे. आपल्या शहरांतील रस्त्याच्या दर्जाविषयी न बोललेच बरे. आणखी दोन दशकभरात महासत्तापदाचे स्वप्न पाहणारा हा देश प्रत्यक्षात 'राहणीमान निर्देशांका'त दिवसेंदिवस घसरू लागलेला आहे हे वास्तव आपण पाहणार की नाही? त्याकडे आतासारखे दुर्लक्षच करत राहिलो तर विकास होईल, अगदी १०० मजली इमारती येतील, चकचकीत मेट्रो तयार होतील, बुलेट ट्रेन सुसाट धावेल. पण तरी सामान्यांचे जगणे होते त्यापेक्षा अधिक वाईट होत राहील.

मुंबईत बुधवारी जे झाले ते या आगामी वास्तवाचे भयसूचक निदर्शक. तेही पाहावयाचे नसेल तर या कथित पायाभूत सुविधांच्या उभारणीतील अपघातात प्राण गेलेल्यांच्या कुटुंबीयांशी या विचारांधांनी जरूर संपर्क साधावा. अलीकडे एखादी क्रेन उलटून, पुलावरील बांधकाम साहित्य कोसळून, सळया/ तुळया तुटून/ आपटून गेलेल्यांची संख्या पाहा. हे वास्तव जाणवेल. ताज्या वाहतूक वास्तवात तर रस्त्यावरची क्रेन उलटून एका पोलिसाचा जीव गेला. पोलिसाचे प्राण गेलेले, ऐन उकाड्यात पाच-सहा तासांचा वाहतूक खोळंबा आणि वाहतूक पोलीस, महापौर आदी यंत्रणांना त्याचा पत्ताही नाही. हे आपले सध्याचे चित्र. माणसे उपासमारीने, आजाराने, दारिद्र्याने संकटग्रस्त होतात. पण भारतातील जनता सद्यःस्थितीत अशी विकासग्रस्त आहे. ही विकासग्रस्तता अनुभवणाऱ्यांनाच या विदारक वास्तवाची जाणीव नसेल तर त्यांची वाताहत अशीच होत राहणार, हे निश्चित. आजच्या महाराष्ट्रदिनी इतकी जाणीव ठेवली तरी पुरे.

महाराष्ट्राच्या आरोग्यात 'सार्वत्रिक' सुधार हवा!

लेख

डॉ. अभय शुक्ला
सार्वजनिक आरोग्यतज्ज्ञ
abhayshukla1@gmail.com

> **'महाराष्ट्रात सर्वसामान्यांना महागड्या आरोग्यसेवेविना पर्याय दिसत नाही; राजस्थानसारखी राज्येही सार्वजनिक आरोग्यसेवेत महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत' या वास्तवाचा आरसा अगदी ताज्या 'राष्ट्रीय नमुना पाहणी'ने दाखवला आहे. ही स्थिती बदलण्याची संधी राज्य सरकारच्या विचाराधीन असलेल्या आरोग्य सेवा धोरणातून मिळू शकते. महाराष्ट्र दिनानिमित्ताने यावर विचार व्हावा...**

राष्ट्रीय स्तरावर नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एनएसएसच्या (नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे) ८० व्या अहवालातून, आरोग्याबाबत अतिशय महत्त्वाची आकडेवारी पुढे आलेली आहे. या अधिकृत अहवालातील आकडे आरोग्यावरील वाढत्या खर्चाचे विदारक चित्र उभे करतात. ते पाहून प्रत्येकाचे डोळे उघडतील आणि आपल्याला याकडे गांभीर्याने पाहणे भाग पडेल.

सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था दुर्लक्षित

एनएसएसच्या ८० व्या ताज्या अहवालानुसार, देशातील ६०.३ टक्के रुग्ण खासगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होतात. हे प्रमाण २०१८ मध्ये झालेल्या ७५ व्या फेरीत ५८ टक्के होते. म्हणजे गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात रुग्णालय उपचारांचे खासगीकरण वाढले आहे. पण या अहवालात डोळे उघडणारी बाब म्हणजे, आता महाराष्ट्रात आरोग्य सेवेचे खासगीकरण भारतातील सर्व राज्यांपेक्षा जास्त झाले आहे. राज्यातील एकूण रुग्णालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या रुग्णांपैकी ७७ टक्के रुग्ण खासगी रुग्णालयात दाखल होतात; इतर सर्व राज्यांपेक्षा हे प्रमाण जास्त आहे. याउलट, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचा वापर कमी झाला आहे. महाराष्ट्रात केवळ १८.६ टक्के रुग्ण सरकारी दवाखान्यात दाखल होतात व हे प्रमाण देशात सर्व राज्यांपेक्षा कमी आहे.

महाराष्ट्राच्या तुलनेत, इतर राज्यांमध्ये रुग्णालय उपचारासाठी सार्वजनिक व्यवस्था अधिक वापरली जाते. तमिळनाडूमध्ये ४३ टक्के, राजस्थानमध्ये ४५.३ टक्के, छत्तीसगडमध्ये ४९.३ टक्के, पश्चिम बंगालमध्ये ५८.८ टक्के आणि गोव्यात ६४.७ टक्के रुग्ण भरती होऊन उपचार घेण्यासाठी सरकारी रुग्णालयात जातात. देशपातळीवर (सर्व राज्ये मिळून) सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपचार घेण्याचे प्रमाण सरासरी ३६.७ टक्के आहे, जे खरे तर कमी आहे. मात्र, आता महाराष्ट्रात सरकारी रुग्णालयांच्या वापराचे प्रमाण याच्यापेक्षाही निम्मे, म्हणजे १८.६ टक्के इतकेच राहिले आहे.

उपचार मोठ्या प्रमाणात खासगी रुग्णालयांमध्ये व्हायला लागतात, तेव्हा खर्च झपाट्याने वाढतो, आणि विमा असला तरीही कुटुंबांना स्वतःच्या खिशातून अधिक पैसे मोजावे लागतात. त्याच वेळी, सार्वजनिक रुग्णालयांचा वापर कमी झाल्यामुळे, सर्वांना आरोग्य सेवा देण्याची राज्याची क्षमता कमी होते. खासगीकरण मोठ्या प्रमाणात असेल तर सर्व स्तरांतील लोकांना आर्थिक अडचणी व उपचार न मिळण्याचा धोका वाढतो.

खासगी आरोग्य क्षेत्रात दुप्पट खर्च

एनएसएसच्या ८० व्या अहवालातील आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात कुटुंबांवरील आरोग्याचा आर्थिक बोजा आता लोकांच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रात खासगी रुग्णालयातील उपचाराचा सरासरी खर्च ४४ हजार ५८० रुपयांपर्यंत वाढला आहे, तर शहरी भागात तो आणखी वाढून सरासरी ६७ हजार ८३१ रुपयांवर पोहोचला आहे. २०१८ मध्ये ग्रामीण भागातील खासगी रुग्णालय खर्च २३ हजार ८२१ रुपये होता, पण गेल्या सात वर्षांत ग्रामीण भागातील खासगी रुग्णालयातील खर्चात ८७ टक्के इतकी प्रचंड वाढ झाली आहे.

२०१८ ते २०२५ या कालावधीत एकूण महागाईमुळे सर्व खर्च सुमारे ४३ टक्के वाढले आहेत, पण महाराष्ट्रातील खासगी रुग्णालयात उपचाराचा खर्च, महागाईच्या दरापेक्षा दुप्पट वेगाने वाढला असल्याचे स्पष्ट होते. खासगी आरोग्य सेवेच्या दरांवर कोणतेही प्रभावी नियंत्रण न ठेवण्याचा हा स्पष्ट परिणाम दिसत आहे. महाराष्ट्रात खासगी रुग्णालयांची महागडी बिले गरिबांसाठी कठीण आहेतच, तर मध्यमवर्गीयांसाठी पण स्थिती बिकट झाली आहे. मध्यमवर्गीयांना खासगी रुग्णालयात एकदा भरती झाल्यावर, सरासरी ७२ ते ८४ हजार रुपये मोजावे लागत आहेत. यातले अधिक खर्च असलेल्या १० टक्के रुग्णांची बिले दीड लाख रुपयांच्या वर गेलेली आहेत. म्हणजे ग्रामीण कष्टकरी, शहरी गरीब आणि मध्यमवर्ग - या सर्वांनाच आज खासगी क्षेत्रातील महागड्या उपचारांसाठी मोठी किंमत मोजायला लागत आहे.

सकारात्मक निर्णय, पण परिणाम कमी

सामान्य लोकांना आरोग्य सेवा सुलभ मिळण्यासाठी, ऑगस्ट २०२३ पासून महाराष्ट्र सरकारने दोन हजार ४१८ शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये सर्व वैद्यकीय उपचार आणि चाचण्या पूर्णपणे मोफत देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. त्याशिवाय २०२४ मध्ये 'महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजने'चे सार्वत्रिकीकरण करण्यात आले, आणि रेशनकार्डधारक प्रत्येक कुटुंबाला पाच लाख रुपयांपर्यंतचे विमा संरक्षण देण्यात आले, ज्यात २,३०० हून अधिक मोफत उपचारसुविधा देण्याचे आश्वासन दिले गेले.

हे निर्णय स्वागतार्ह असले तरी एनएसएसच्या ताज्या आकडेवारीवरून समोर आलेले चित्र चिंताजनक आहे. यावरून असे दिसून येते की, या उपाययोजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी पुरेशी नाही. ताज्या एनएसएस अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयातील भरतीसाठी ग्रामीण भागात सरासरी आठ हजार ८० रुपये, आणि शहरी भागात आठ हजार ३६४ रुपये लोकांना खर्च करावे लागतात. सरकारी रुग्णालयामध्ये खर्चाचा मोठा हिस्सा बाहेरून औषधे विकत घेण्यासाठी आणि तपासण्यांसाठी (डायग्नोस्टिक टेस्टवर) केला जातो, असे अनुमान आहे. तर ग्रामीण भागातील रुग्ण 'मोफत' सरकारी हॉस्पिटल उपचार घेत असताना, फक्त औषधांवर सरासरी तीन हजार ३५० रुपये खर्च करत असल्याचे अनुमान आहे.

राष्ट्रीय स्तरावर आयुष्मान भारत - ढटखअ आणि महाराष्ट्रात 'महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना' यांचे २०२० मध्ये एकत्रीकरण झाले. यातून लोकांचा रुग्णालयामध्ये स्वतःच्या खिशातून होणारा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी होणे अपेक्षित होते. एनएसएसच्या ८० व्या अहवालानुसार, महाराष्ट्रातील रुग्णालयामध्ये उपचाराचा सरासरी एकूण खर्च ४४ हजार ७७८ रुपये आहे, आणि यापैकी सरासरी ४० हजार ४९५ रुपये अजूनही लोकांना स्वतःच्या खिशातूनच भरावे लागत आहेत. याचा अर्थ महाराष्ट्रातील ९० टक्के रुग्णालय उपचाराचा खर्च लोक अजून स्वतःच्या खिशातून करत आहेत. विमा योजनांद्वारे थोड्या रुग्णांना संरक्षण मिळते, तर उर्वरित बहुसंख्यांना फारसा आधार मिळत नाही. आरोग्य विमा योजना वाढता खर्च रोखण्यात कमी पडतात, तेव्हा त्या योजनेच्या मूळ आराखड्यात सुधारणेची गरज अधोरेखित होते. विमा कार्ड देण्याच्या पलीकडे, खासगी रुग्णालयांच्या दरांवर नियंत्रण आणणे आणि जनतेला खऱ्या अर्थाने परवडणारी आरोग्य सेवा पुरवणे, हे उपाय महत्त्वाचे दिसतात.

हवे नवीन आरोग्य धोरण आणि परवडणारी सेवा!

खासगीकरणामुळे महाराष्ट्रात बाह्यरुग्ण (ओपीडी) उपचारांवर खर्चही वाढला आहे. २०१८ मध्ये हा खर्च रुग्णाला सरासरी ६६६ रुपये येत होता, तो आता खासगी क्लिनिक आणि रुग्णालयांमध्ये एक हजार ४४ ते एक हजार ३८५ रुपयांच्या दरम्यान झाला आहे. म्हणजेच येथेही खर्चात जवळपास दुप्पट वाढ झाली आहे. महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाला सध्या गतिमान नेतृत्व लाभले आहे, ज्यांनी या वास्तवाची तातडीने दखल घेणे गरजेचे आहे. किरकोळ सुधारणांच्या पलीकडे जाऊन, व्यापक आणि धाडसी धोरणात्मक पावले उचलण्याची वेळ आली आहे. आरोग्य सेवेचे बाजारीकरण आता सामान्यांच्या जिवावर उठले आहे; या कठीण वास्तवाचा प्रतिकार करण्यासाठी जनतेनेही आता डोळे उघडून संघटित होणे, व्यापक धोरणात्मक बदलांची मागणी करणे आवश्यक आहे.

या बदलांची मुख्य सूत्रे पुढीलप्रमाणे आहेत : पहिले - संपूर्ण राज्यात सार्वजनिक आरोग्य सेवा बळकट करून पूर्णपणे मोफत सेवा उपलब्ध करणे, ज्यामध्ये सर्व औषधे आणि चाचण्या विनामूल्य मिळण्याची खात्री असेल. दुसरे - राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयांमध्ये दरपत्रक काटेकोरपणे प्रदर्शित करणे, त्यांच्या दरांवर योग्य नियंत्रण आणणे, आणि रुग्ण हक्क सनदेची अंमलबजावणी करणे. तिसरे - सार्वजनिक आरोग्य सेवांचे सर्व प्रकारचे खासगीकरण थांबवणे. 'पब्लिक फर्स्ट'- सार्वजनिक व्यवस्थेला आणि जनतेच्या हिताला प्राधान्य देणारे दृष्टिकोन घेऊन, आरोग्य व्यवस्थेत सुधारणा करणे. चौथे - सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांच्या कामकाजावर लोकशाही अंकुश ठेवण्यासाठी, स्थानिक जनता आणि सामाजिक संस्था- संघटनांना प्रोत्साहन देऊन, सगळीकडे लोकाधारित देखरेख प्रक्रिया राबवणे. पाचवे - या सर्व सुधारणांचा आधार घेऊन, सार्वजनिक व खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रांचा समावेश असलेल्या 'सार्वत्रिक आरोग्य सेवा' (युनिव्हर्सल हेल्थ केअर) प्रणालीची उभारणी करणे. यामुळे महाराष्ट्रात प्रत्येकाला विनामूल्य आणि दर्जेदार उपचार, हक्क म्हणून मिळू शकेल.

महाराष्ट्र आरोग्य विभागाने राज्यातील तज्ज्ञ आणि आरोग्य कार्यकर्त्यांशी वेगवेगळ्या विभागांमध्ये चर्चा करून, लवकरच 'राज्य आरोग्य धोरण' तयार करावे. याचा एक प्रमुख उद्देश लोकांचा आरोग्यावरील असह्य खर्च कमी करणे हा असेल. महाराष्ट्रातील अलिखित खासगीकरणाचे 'धोरण' आता थांबवून, त्याऐवजी स्पष्टपणे जनतेला केंद्रस्थानी ठेवणारे 'सार्वत्रिक आरोग्य सेवा' (युनिव्हर्सल हेल्थ केअर) धोरण आणणे ही काळाची गरज आहे. महाराष्ट्र दिनानिमित्त, सर्वांसाठी परवडणारी आणि दर्जेदार आरोग्य सेवा हे ध्येय गाठण्यासाठी, लोकांमध्ये आणि आरोग्य यंत्रणेद्वारे एक मोठी राज्यव्यापी मोहीम सुरू करणे आता योग्य ठरेल. आरोग्य सेवेच्या व्यापारीकरणाच्या विळख्यात पूर्णपणे अडकण्यापूर्वी, आपण समाज म्हणून एकत्रितपणे सावरण्याचा आता हाच मार्ग दिसत आहे.

कर्मचारी कपातीच्या काळातही 'अभियांत्रिकी'कडे ओढा का?

विश्लेषण

चिन्मय पाटणकर
chinmay.patankar@expressindia.com

> **कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या प्रभावामुळे (एआय) कर्मचारी कपात, कॅम्पस प्लेसमेंट कमी होत असल्याच्या बातम्या येत असतानाही अभियांत्रिकी पदवीकडेच विद्यार्थ्यांचा ओढा असल्याचे 'जेईई मुख्य' परीक्षेच्या नोंदणी आकडेवारीवरून दिसून येते.**

'संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य' (जेईई-मेन) काय आहे?

देशातील आयआयटी, एनआयटी, आयआयआयटी अशा केंद्रीय संस्थांतील अभियांत्रिकी, तंत्रज्ञान अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी जेईई मुख्य परीक्षा घेतली जाते. राष्ट्रीय परीक्षा प्राधिकरणामार्फत या परीक्षेचे जानेवारी आणि एप्रिल अशा दोन सत्रांमध्ये आयोजन केले जाते. दोन्ही सत्रांतील परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये कोणत्याही एका सत्रातील परीक्षेतील सर्वाधिक गुण ग्राह्य धरले जातात. जेईई मुख्य परीक्षेतील निवडक विद्यार्थी 'जेईई ॲडव्हान्स्ड' या परीक्षेसाठी पात्र ठरवले जातात. तसेच देशभरातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयांतील अखिल भारतीय १५ टक्के कोट्यातील जागांसाठीही जेईई मुख्य परीक्षेतील गुण ग्राह्य धरले जातात. त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना प्रवेशासाठी होतो.

'जेईई मुख्य' परीक्षेची नोंदणी कशी वाढली?

२०१७ ते २०२६ या काळातील 'जेईई मुख्य' परीक्षेच्या दोन्ही सत्रांतील नोंदणीची आकडेवारी पाहता करोनानंतरच्या काळात नोंदणीमध्ये झपाट्याने वाढ झाल्याचे दिसून येते. २०१७ मध्ये ९.५६ लाख, २०१८ मध्ये १०.४३ लाख, २०१९ मध्ये ११.४७ लाख, २०२० मध्ये १०.२३ लाख, तर २०२१ मध्ये ९.३९ लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली होती. मात्र, महासाथीनंतरच्या काळात २०२२ मध्ये १०.२६ लाख, २०२३ मध्ये ११.६२ लाख, २०२४ मध्ये १४.७६ लाख, २०२५ मध्ये १५.३९ लाख, तर यंदा २०२६ मध्ये १६.०४ लाख विद्यार्थ्यांनी नोंदणी केली. तर 'जेईई ॲडव्हान्स्ड'साठी पात्र विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे एक लाख ६० हजार ते एक लाख ९० हजार या दरम्यान राहिल्याचे दिसून येते.

अभियांत्रिकी पदवीकडे ओढा कायम का आहे?

'पूर्वी बारावीला जे महत्त्व होते, तेच आता अभियांत्रिकी पदवीला आले आहे. ही पदवी मिळवल्यावर एमबीए, स्पर्धा परीक्षा किंवा अन्य काहीही करता येते, असा विचार विद्यार्थी, पालक करतात. करिअरचे वेगळे पर्याय विद्यार्थी, पालकांना सांगूनही ते त्यांना पटत नाहीत. त्यामुळे बहुसंख्याकांचा ओढा अभियांत्रिकीकडेच असल्याचे दिसते,' असे करिअर समुपदेशक डॉ. भूषण केळकर सांगतात. 'जेईई-मुख्य परीक्षेची वाढती नोंदणी ही सूज आहे. एक तर अभियांत्रिकी पदवीचे आता सुमारीकरण झाले आहे. त्यातून 'एआय'चा सर्वच क्षेत्रांवर किती व्यापक परिणाम होणार आहे, याचा अंदाज विद्यार्थी, पालकांना आलेला नाही,' असेही त्यांचे म्हणणे आहे. अभियांत्रिकी शाखेच्या स्पर्धा परीक्षांचे तज्ज्ञ मार्गदर्शक दुर्गेश मंगेशकर सांगतात, 'माहिती तंत्रज्ञानातील नोकऱ्या 'एआय'मुळे कमी होत असल्या, तरी रोबोटिक्स, मेकॅट्रॉनिक्स, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकलची मागणी वाढत आहे. तसेच, आयआयटीच्या वाढलेल्या जागा, एनआयटी, आयआयआयटीमध्ये असलेल्या संधी हीसुद्धा काही कारणे आहेत. शिवाय, 'जेईई मुख्य परीक्षेची तयारी अन्य प्रवेश परीक्षांसाठीही उपयोगी ठरते. अस्थिर जागतिक परिस्थिती, व्हिसा निर्बंधांसारख्या कारणांनी परदेशात जाण्याचेही प्रमाण कमी झाले आहे. त्यामुळे जेईई मुख्य परीक्षेची नोंदणी वाढत असल्याचे दिसते.

कॅम्पस प्लेसमेंटची स्थिती काय काय?

उच्च शिक्षणातील अन्य शाखांच्या तुलनेत अभियांत्रिकी पदवीधरांना अधिक संधी आहे. एआयमुळे काही नोकऱ्या कमी होत असल्या, तरी नव्या नोकऱ्याही निर्माण होत आहेत. नोकऱ्या कमी होण्यामागे कृत्रिम बुद्धिमत्तेपेक्षा गेल्या काही वर्षांतील बदलती भूराजकीय स्थिती, युद्ध अशा घटकांचा जास्त परिणाम आहे, असे निरीक्षण महाराष्ट्र ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट ऑफिसर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष डॉ. शीतलकुमार रवंदळे यांनी नोंदवले. याआधी प्लेसमेंटचे प्रमाण सरासरी ८० ते ८५ टक्क्यांपर्यंत होते. ते सध्या ७०-७५ टक्क्यांपर्यंत आले आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची प्लेसमेंट सरासरी ५० ते ६० टक्के आहे, नामांकित महाविद्यालयांत ती ८०-८५ टक्क्यांपर्यंतही आहे. शिकतानाच कौशल्ये विकसित करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना जास्त पटकन नोकरीच्या संधी मिळतात, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

हा कल भविष्यातही कायम राहणार?

अभियांत्रिकीचे वलय लोप पावण्याची सध्या तरी शक्यता नाही, असे तज्ज्ञ सांगतात. मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकलसारख्या मूलभूत शाखांचे महत्त्व टिकून आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणातील उपविषय निवडण्याच्या तरतुदींमुळे विद्यार्थ्यांना अभियांत्रिकी पदवीच्या काळातच अर्थशास्त्र, मानसशास्त्र असे विषय शिकता येत आहेत. त्यामुळे येत्या काळात अभियांत्रिकी शिक्षणाचे स्वरूपच बदलू शकते. झटपट पैसा मिळवण्यासाठी अभियांत्रिकीशिवाय दुसरे क्षेत्र नाही, असे विद्यार्थ्यांना वाटते. मात्र, 'एआय'मुळे परिस्थिती झपाट्याने बदलते आहे. नोकर भरतीची नेमकी आकडेवारी जाहीर होत नाही. कोट्यवधींचे पॅकेज मोजक्यांना मिळते. त्यामुळे बदलत्या परिस्थितीची पालक, विद्यार्थ्यांना जाणीव व्हायला दोन ते तीन वर्षे लागतील, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

अन्वयार्थ

विमान कंपन्यांची व्यथा

आपत्ती निवारण जमत नसेल तर आपत्ती व्यवस्थापनाचे मार्ग तरी खुले असावेत, हे कोणत्याही व्यवस्थेच्या परिपक्वतेचे आणि जागरूकतेचे प्रधान लक्षण. पश्चिम आशियात फेब्रुवारीअखेरीस सुरू झालेल्या युद्धामुळे भारतासारख्या अतिविशाल आणि ऊर्जावलंबी देशात या लक्षणाचा फेरविचार करण्याची वेळ आलेली आहे. एकूण गरजेपैकी जवळपास ८८ टक्के खनिज तेलाची भारताला आयात करावी लागते. यातील जवळपास ५० टक्के खनिज तेल आणि ६० टक्के नैसर्गिक वायू होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतून येतो. युद्धास तोंड फुटल्यानंतर लगेचच इराणने व्यूहरचनात्मक डावपेचाचा भाग म्हणून या सामुद्रधुनीची नाकेबंदी सुरू केली. त्यामुळे प्राणवायू रोखल्यागत इंधनावलंबी अर्थव्यवस्था तडफडू लागल्या आहेत. भारत यांपैकीच एक. त्याला स्वयंपाकाच्या इंधनापासून भूपृष्ठ आणि हवाई वाहतूक इंधनापर्यंत सर्वांचाच तुटवडा जाणवू लागला. त्यामुळे दरवाढ करणे क्रमप्राप्त बनले. पण सध्या निवडणुकांचा हंगाम असल्यामुळे आणि स्वयंपाक इंधन तसेच वाहतूक इंधन दरवाढ राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनशील आणि जोखमीची ठरत असल्यामुळे सरकार त्यांच्या वाटेला गेले नाही. हवाई वाहतूक इंधनाचे (एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल - एटीएफ) मात्र तसे नाही. त्यामुळे त्यांचे दर सरकारने वाढवलेच. त्यातही स्थानिक विमान प्रवास आणि परदेशी विमान प्रवास असा दुजाभाव करण्यात आला. पश्चिम आशियातील युद्धस्थिती आणि त्यातून सुरू झालेल्या विस्कळीत तेलपुरवठ्यानंतर, १ एप्रिलपासून पेट्रोलियम मंत्रालयाने आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर एटीएफ दरात १०० टक्के वाढ (७३ रुपये प्रतिलिटर) केली. पण देशांतर्गत मार्गांसाठी मात्र वाढीवर २५ टक्क्यांची (१५ रुपये प्रतिलिटर) मर्यादा घालून देण्यात आली. देशांतर्गत हवाई वाहतूक क्षेत्रासाठी वाढीव दराचा भार सरकारी तेल विपणन कंपन्या सोसणार आहेत. पण आंतरराष्ट्रीय मार्गांसाठी अतिरिक्त दरवाढ या कंपन्यांनी विमान कंपन्यांकडे सरकवलेली आहे. आधीच पश्चिम आशियातील हवाईक्षेत्रास वळसा घालून जावे लागते, पाकिस्तानच्या हवाई हद्दीचा वापर करता येत नाही आणि रुपयाची सततची घसरण या तिहेरी संकटांमुळे भारतीय विमान कंपन्यांसाठी आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे प्रचंड तोट्याची ठरू लागली आहेत. या उड्डाणांना मागणी मर्यादित आहे. उलट देशांतर्गत उड्डाणांची मागणी (किमान मुख्य मार्गांवर तरी) चढी आहे. पण तेथे एटीएफचे दर वाढवता येत नाहीत, असा कोंडमारा भारतीय कंपन्यांना सहन करावा लागत आहे.

तो सहन न झाल्यामुळेच इंडिगो एअरलाइन्स, एअर इंडिया आणि स्पाइसजेट या कंपन्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या फेडरेशन ऑफ इंडियन एअरलाइन्स (एफआयए) या संघटनेने काही दिवसांपूर्वी सरकारचा धावा केला. आमचा खेळ संपेल असे सरकारला सांगण्याचे धाष्ट्र्य त्यांनी दाखवले, हेच मुळात कौतुकास्पद ठरते. कारण आपण अडचणीत आहोत असे सरकार कधी म्हणत नाही. पण सरकारकडे असे गाऱ्हाणे मांडण्याची हिंमत किंवा इच्छाशक्तीही कोणी दाखवत नाही. जगात इंधन तुटवड्यामुळे सारेच हवालदिल असताना भारतासारख्या सर्वस्वी आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशात सारे काही आलबेल कसे असू शकते? विमान वाहतूक कंपन्यांनी किमान यानिमित्ताने चांगला पायंडा पाडला असे म्हणता येईल. सहसा एटीएफचे दर हवाई वाहतूक कंपन्यांच्या एकूण खर्चापैकी ४० टक्के इतके असतात. ताज्या परिस्थितीत ते प्रमाण ५५ ते ६० टक्क्यांवर गेल्याचे विमान कंपन्यांचे म्हणणे आहे. देशांतर्गत एटीएफ विक्रीवरील ११ टक्के उत्पादन शुल्क रद्द करावे, तसेच दिल्ली, मुंबई, बेंगळूरु चेन्नई हे नफा मिळवून देणारे विमानतळ असलेल्या राज्यांमधील मूल्यवर्धित कर कमी करावेत अशीही मागणी आहे.

एटीएफ दरांवरील नियंत्रण २००१ मध्ये उठवण्यात आले. त्यांची निश्चिती दर महिन्याला आंतरराष्ट्रीय बाजारातील खनिज तेलांच्या दरांशी संलग्न राहून केली जाते. म्हणजे त्यात चढ-उतार आंतरराष्ट्रीय बाजारानुसार होत असतो. पेट्रोल आणि डिझेलबाबत मर्यादित दरनियंत्रण असते, तसे ते एटीएफच्या बाबतीत का नसते अशी विचारणा विमान कंपन्या नेहमीच करत असतात. भारतात तेलशुद्धीकरण उत्पादनापैकी केवळ चार टक्केच एटीएफ असते. या शुद्धीकृत एटीएफपैकी ३० टक्के देशांतर्गत विमान कंपन्या आणि २० टक्के आंतरराष्ट्रीय विमान कंपन्या वापरतात. उर्वरित ५० टक्के एटीएफची निर्यात होते. त्यामुळे एटीएफच्या दरांबाबत सरकारने विमान कंपन्यांचा विचार करावा ही मागणी अवास्तव ठरत नाही.

नवभारत टाइम्स • विचार

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शुक्रवार, 1 मई 2026

संवैधानिक नैतिकता कोई स्वाभाविक भावना नहीं है, इसे विकसित करना पड़ता है।

– डॉ. बी.आर. आंबेडकर

अधिकार सर्वोपरि

सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिग रेप सर्वाइवर के 30 हफ्ते के भ्रूण की मेडिकल टर्मिनेशन के मामले में अपना पिछला फैसला बहाल रखा। उसने कहा कि टर्मिनेशन का निर्णय पीड़िता के परिजन करें। शीर्ष अदालत ने इस मामले में सही फैसला किया है। उसने 24 अप्रैल को मेडिकल टर्मिनेंसी की अनुमति दी थी, जिसके खिलाफ एम्स ने क्यूरेटिव पिटिशन दाखिल की थी। अदालत ने बुधवार को इसे खारिज कर दिया।

संवेदनशीलता की जरूरत । इस फैसले के सामाजिक आयाम भी हैं। समाज अनब्याही नाबालिग या महिला के गर्भपात कराने को लांछन समझता और उन्हें ताउम्र प्रताड़ित करता है। ऐसी मां जिस शिशु को जन्म देती है, उसे भी सामाजिक उपेक्षा झेलनी पड़ती है। इसलिए ऐसे मामलों में समाज से और संवेदनशील होने की अपेक्षा की जानी चाहिए।

एम्स की अर्जी खारिज

एम्स का तर्क । सुप्रीम कोर्ट ने एम्स की याचिका खारिज करते हुए कहा कि वह उसके 24 अप्रैल के निर्णय को मानने के बजाय एक नाबालिग के संवैधानिक अधिकारों का हनन करना चाहता है। उसने फैसले में कहा था कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी एक्ट, 1971 गर्भाधान के 24 हफ्तों के बाद गर्भपात की इजाजत नहीं देता, लेकिन सिर्फ इस आधार पर मौजूदा केस में पीड़िता के संवैधानिक अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता।

क्या कहता है कानून । संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि अपने शरीर , खासतौर से प्रजनन के मामलों में, की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और निजता का पालन होना चाहिए। किसी भी अदालत को किसी महिला और उससे भी बढ़कर एक नाबालिग को उसकी इच्छा के विरुद्ध, गर्भ को पूर्ण अवधि तक रखने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। ऐसा करना स्त्री के मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह होगा।

अवैध गर्भपात का डर । अदालत के मुताबिक, गर्भपात की कानूनी अनुमति न मिलने से ही पीड़िता अक्सर खतरनाक रास्तों का चुनाव कर अवैध गर्भपात केंद्रों की ओर रुख करते हैं। इस मामले में तो यह नाबालिग दो बार खुदकुशी का प्रयास भी कर चुकी है। वहीं, एम्स की दलील थी कि गर्भावस्था के लगभग अंतिम चरण में अबॉर्शन की कोशिश असफल भी रह सकती है। इससे न सिर्फ नाबालिग की जान को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है, उसके भविष्य में मां बनने की क्षमता भी खत्म हो सकती है।

नजीर बनेगा फैसला । मेडिकल वजहें अपनी जगह ठीक हैं और ऐसे किसी मामले में उन पर गंभीरता से गौर किया जाना चाहिए। मगर सबसे ऊपर पीड़िता के संवैधानिक अधिकार हैं, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है। उसका यह फैसला आने वाले वक्त में नजीर बनेगा।

तिराहा

ये मुर्दों का गांव

सुधर्मा का चेहरा क्लांत था। नजर सामने रखे अखबार पर थी। सुखनंदन ने पत्नी से चिंता का कारण पूछा। 'कहां पहुंच गए हैं हम! यह खबर देखी? बैंक में सबूत देने के लिए कंकाल लाना पड़ा, ताकि मुट्ठी भर पैसा पा सके।' स्वर में क्षोभ था।

प्रेम शंकर मिश्र

'प्रिये! इतना व्यथित मत हो। बैंक तो व्यवस्था का पालन कर रहे हैं और व्यवस्था इंद्रासन की चेरी है। कथा नहीं पढ़ी? इंद्र का सिंहासन डोलने लगा तो महर्षि दधीचि को हड्डियां दान करनी पड़ीं। वियोग में पत्नी चल बसीं। नवजात पुत्र को पीपल की पत्तियां खा जान बचानी पड़ी।' 'इसका आज से क्या संबंध?' सुधर्मा ने पूछा। 'बहुत गहरा', सुखनंदन मुस्कराए। 'बैंक, LIC और दूसरे वित्तीय संस्थानों में पड़ी आम जनता की बचतें दधीचि की हड्डियां ही तो हैं, जो इंद्रासन पर न्योछावर होती हैं। बैंकों के पास 72 हजार करोड़ रुपये पड़े हैं, जिनका कोई दावेदार नहीं। क्योंकि, इनके लिए कब्र से कंकाल खोद लाने की जिजीविषा या जरूरत इनके जमाकर्ताओं के पास नहीं। गरीब कुछ हजार के फेर में पेड़ पर लटक जाता है, जबकि यही संस्थाएं किसी को करोड़ों रुपये घोड़ा खरीदने के लिए दे देती हैं, क्योंकि उसने अपनी पूंजी इंद्रासन में लगाई है। पेड़ पर लटका कंकाल भी राजनीतिक निवेश हो जाता है।' सुखनंदन ने कहना जारी रखा, 'भीष्म पितामह को वरदान था कि वह अपनी इच्छा से मर सकते थे। अब यह शक्ति व्यवस्था में समाहित हो गई है। यह कागजों में मुर्दा को जिंदा और जिंदा को मुर्दा कर सकती है। तभी तो मुर्दे वोट दे आते हैं और जिंदा मृत्यु प्रमाण पत्र खारिज कराने दौड़ते रहते हैं।'

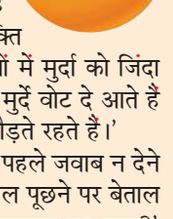

'कोई सवाल क्यों नहीं करता?' 'क्योंकि पहले जवाब न देने पर विक्रम का सिर फट जाता था, अब सवाल पूछने पर बेताल का सिर फट जाता है।' 'और संवेदना, मनुष्यता का क्या?' सुधर्मा हैरान थी। 'इसके लिए आप विज्ञापन और घोषणापत्र देखें।' सुखनंदन ने जवाब दिया। दूर कहीं कबीर का निर्गुण बज रहा था, 'साधो ये मुर्दों का गांव...।'

एकदा

संकलन : रिंकल शर्मा

बर्न्स का प्रकृति प्रेम

स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय कवि रॉबर्ट बर्न्स का जन्म सन् 1759 में हुआ था। उन्हें स्नेह से 'रैबी बर्न्स' भी कहते हैं। वह अपनी गहरी संवेदनशीलता और प्रकृति-प्रेम के लिए जाने जाते हैं। एक दिन वह अपने खेत में हल चला रहे थे। अचानक उनका हल एक चूहे के बिल से टकरा गया। वह नन्हा-सा जीव भयभीत और असहाय होकर इधर-उधर भागने लगा। यह देखकर बर्न्स का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने उस चूहे के दर्द को गहराई से महसूस किया। इस अनुभव ने उनके भीतर एक गहन विचार जगाया कि मनुष्य अपनी योजनाओं में इतना उलझा रहता है कि वह अक्सर दूसरों, यहां तक कि छोटे जीवों पर भी अपना प्रभाव जमाने से नहीं चूकता। इसी संवेदना से प्रेरित होकर उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कविता 'To a Mouse' की रचना की, जिसमें उन्होंने जीवन की अनिश्चितता और सभी प्राणियों के प्रति सहानुभूति का संदेश दिया। उनका मानना था कि 'सच्ची महानता केवल बड़े कार्यों में नहीं, बल्कि छोटे-छोटे जीवों के प्रति दया और समझ में भी निहित होती है। जब हम दूसरों के दर्द को महसूस करना सीख लेते हैं, तभी हमारा व्यक्तित्व वास्तव में महान बनता है।'

Subrata Dhar

हिंद महासागर आर्थिक और सामरिक शक्ति का केंद्र, इस पर नियंत्रण बढ़ाना ज़रूरी

ग्रेट निकोबार: चीनी चक्रव्यूह का जवाब

सरकार की महत्वाकांक्षी 'ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना' को लेकर देश में एक तीखी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। विपक्ष के नेता ने हाल में इस द्वीप का दौरा किया और सोशल मीडिया के माध्यम से परियोजना को इकोलॉजी और पर्यावरण के विनाश का कारण बताते हुए एक 'बड़ा घोटाला' और 'राष्ट्रीय धरोहर के खिलाफ अपराध' करार दिया। पर्यावरण की चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन जब राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और भविष्य की रणनीतिक दिशा की बात हो, तो तस्वीर का केवल एक हिस्सा देखना उचित नहीं लगता। यह परियोजना देश के भविष्य की एक सख्त सामरिक और आर्थिक आवश्यकता है।

आर के एस भदौरिया

ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना

- स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पश्चिमी प्रवेश द्वार के पास है द्वीप
- रणनीतिक बढ़त का मौका, विदेशी पोर्ट पर निर्भरता खत्म

चीन की बढ़ेगी टेंशन

भारत लंबे समय तक अपनी सुरक्षा सोच में भूमि-सीमाओं पर अधिक केंद्रित रहा। हिंद महासागर वैश्विक व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति और सामरिक शक्ति का केंद्र है।

ग्रेट निकोबार का भूगोल अपने आप में भारत के लिए एक प्राकृतिक वरदान है। यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है और स्ट्रेट ऑफ मलक्का के पश्चिमी प्रवेश द्वार से मात्र 40 समुद्री मील की दूरी पर है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया का लगभग 30% कंटेनर व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है।

मैंने अपने करियर में कई बार महसूस किया कि जब आपकी निगरानी की क्षमता सीमित होती है, तो आपकी प्रतिक्रिया भी सीमित हो जाती है। लेकिन जब आपके पास अग्रिम मोर्चे पर ठोस ढांचा हो - हवाई पट्टी, बंदरगाह, संचार प्रणाली, तो आप स्थिति को नियंत्रित करने की स्थिति में आ जाते हैं।

ग्रेट निकोबार को 'अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर' कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारे पास समुद्र के बीच एक ऐसा स्थायी ठिकाना होगा, जो किसी जहाज की तरह डूब नहीं सकता, लेकिन उसकी तरह काम कर सकता है। वहां से वायुसेना के विमान उड़ सकते हैं, नौसेना के जहाज संचालन कर सकते हैं, और तीनों सेनाएं मिलकर एक संयुक्त रणनीति बना सकती हैं। अंडमान और निकोबार में पहले से ही त्रि-सेवा कमान है, लेकिन उसे आधुनिक और व्यापक ढांचे की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे सबसे बड़े भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी चीन का 75% से 80% ऊर्जा व तेल आयात इसी मलक्का कॉरिडोर से होकर गुजरता है। पेइचिंग में बैठे चीनी रणनीतिकार इसे अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानते हैं, जिसे वे 'मलक्का डिलेमा' कहते हैं। चीन दशकों से 'स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स' रणनीति के तहत हमारे पड़ोसी देशों, जैसे पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हंबनटोटा और म्यांमार के क्याउकप्यू बंदरगाह में अपने सैन्य और दोहरे उपयोग वाले बेस बनाकर हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। वह थाईलैंड में 'क्रा कैनाल' बनाने की फिराक में है ताकि मलक्का स्ट्रेट को बाईपास कर सीधे हिंद महासागर में प्रवेश कर सके। ऐसे में, ग्रेट निकोबार में एक मजबूत, आधुनिकीकृत और सैन्यीकृत उपस्थिति दर्ज करना चीन के इस विस्तारवादी चक्रव्यूह का सबसे सटीक, अचूक और 'हार्ड-पावर' जवाब है।

वैश्विक व्यापार का केंद्र बनेगा

बिना मजबूत अर्थव्यवस्था के कोई भी सेना लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ सकती। आर्थिक दृष्टिकोण से यह परियोजना भारत की दशकों पुरानी रसद और ढांचागत कमियों को दूर करने का एक अचूक उपाय है। मजबूत सप्लाई चेन, तेज लॉजिस्टिक्स और आत्मनिर्भर ढांचा, ये सभी किसी भी राष्ट्र की शक्ति को परिभाषित करते हैं। अगर हम अपने व्यापारिक मार्गों को मजबूत करते हैं, तो हम न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी आत्मनिर्भर बनते हैं।

आज वास्तविकता यह है कि भारत के 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो का प्रबंधन विदेशी बंदरगाहों, मुख्य रूप से श्रीलंका के कोलंबो (45%), सिंगापुर और मलेशिया के पोर्ट क्लैंग द्वारा किया जाता है। दूसरे देशों के बंदरगाहों पर इस निर्भरता के कारण हमारे देश को हर साल 20 से 40 करोड़ डॉलर का भारी नुकसान उठाना पड़ता है और सप्लाई चेन में भी देरी होती है।

ग्रेट निकोबार के गैलाथिया बे की टोपोग्राफी और भौगोलिक स्थिति दुनिया में अद्वितीय है। यहां समुद्र तट से मात्र एक नॉटिकल मील की दूरी पर 20 मीटर से अधिक की प्राकृतिक गहराई उपलब्ध है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यहां दुनिया के सबसे बड़े अल्ट्रा लार्ज कंटेनर जहाज, जो 10 हजार से 25 हजार TEU माल ढोते हैं, बिना किसी भारी और महंगी ड्रेजिंग के आसानी से डॉक कर सकते हैं। गैलाथिया बे में 16.2 मिलियन TEU क्षमता का 'इंटरनैशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल' (ICTT) बनने से भारत विदेशी बंदरगाहों पर अपनी निर्भरता खत्म करेगा और स्वयं पूरे दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए एक प्राथमिक वैश्विक व्यापार नोड बन जाएगा। इससे भारी विदेशी मुद्रा की बचत होगी, साथ ही साथ इस क्षेत्र में 1 लाख से अधिक प्रत्यक्ष और 1.5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार भी पैदा होंगे।

82% जंगल संरक्षित रहेगा

इस परियोजना के लिए द्वीप के कुल वन क्षेत्र का केवल 1.82% हिस्सा ही डाइवर्ट किया जा रहा है। पर्यावरण मंत्रालय के मास्टर प्लान के तहत, ग्रेट निकोबार का 82% जंगल पूरी तरह से अछूता, संरक्षित और विकास कार्यों से मुक्त रहेगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI), वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (WII) जैसी शीर्ष वैज्ञानिक संस्थाओं के अध्ययन के बाद इसे मंजूरी मिली है। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने भी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

असहमति लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन राष्ट्रीय हितों को समझने के लिए हमें व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। सीमा केवल जमीन पर नहीं होती। सीमा वहां भी होती है, जहां से हमारे जहाज गुजरते हैं, जहां से हमारी ऊर्जा आती है, और जहां से दुनिया हमें देखती है। उस सीमा पर मजबूत खड़े रहना केवल एक विकल्प नहीं, हमारी जिम्मेदारी है।

लेखक एयर चीफ मार्शल (रिटायर्ड) हैं

कांच में हज़ारों बरस डेटा रहेगा सुरक्षित

आज दुनिया तेजी से डिजिटल हो रही है और डेटा लगातार बढ़ रहा है। हर दो साल में डेटा लगभग दोगुना हो जाता है। हार्ड ड्राइव और मैग्नेटिक टेप जैसे स्टोरेज कुछ ही बरसों में खराब हो जाते हैं। इसलिए फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए बार-बार कॉपी करना पड़ता है। इसमें समय, ऊर्जा और उपकरण ज्यादा लगते हैं।

मुकुल व्यास

नए माध्यम की तलाश । डेटा को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक स्टोरेज के नए माध्यम खोज रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट का प्रॉजेक्ट सिलिका कांच में डेटा स्टोर करने पर काम कर रहा है। हाल ही में गर्मी से बचाने वाले बोरोसिलिकेट कांच की पतली प्लेट में लगभग दो टेराबाइट (TB) जानकारी सुरक्षित रखी गई और फिर सही तरीके से वापस भी हासिल कर ली गई।

देखरेख जरूरी नहीं । यह सिस्टम खुद लिखता, पढ़ता और डिकोड करता है। बगैर बिजली और देखरेख के यह सुरक्षित रहता है। रिसर्चर्स ने कांच में डेटा लिखने के लिए प्रकाश की छोटी किरणों का इस्तेमाल किया। इससे कांच में हल्के बदलाव और छोटे निशान बने। ये डेटा को सुरक्षित रखते हैं और कम देखभाल में लंबे समय तक टिकते हैं।

भरोसेमंद तरीका । कांच में डेटा स्टोर करने के लिए फेमटोसेकंड लेजर का इस्तेमाल किया जाता है, जो बेहद तेज होता है और एक सेकंड के खरबवें (लाख करोड़) हिस्से में एक निशान बनाता है। ये निशान सूक्ष्म 3D संरचनाओं यानी वोक्सेल कांच के अंदर सुरक्षित रहते हैं।

ज्ञान-विज्ञान

AI Image

फिल्में और म्यूजिक भी । कांच में डेटा स्टोरेज लैब तक सीमित नहीं है। इसमें सुपरमैन जैसी फिल्में और म्यूजिक आर्काइव भी स्टोर किए गए हैं। यह डेटा रूम टेंपरेचर पर 10 हजार साल से ज्यादा सुरक्षित रह सकता है और इस पर तेज गर्मी और पानी का भी असर नहीं होता। यह सिस्टम मामूली अनदेखी के बाद भी ठीक रह सकता है। फिर भी डेटा का लंबे समय तक सुरक्षित रहना इस पर निर्भर करेगा कि लोग भविष्य में कांच को कैसे हैंडल करते हैं। भले ही कांच में डेटा रखने का विचार तकनीकी तौर पर भरोसेमंद लगता हो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ने अभी इसे कमर्शल प्रॉडक्ट बनाने की घोषणा नहीं की है।

कांटे की बात

ईरान अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को राष्ट्रीय संपत्ति मानकर उनकी रक्षा करेगा। हजारों किलोमीटर दूर से लालच के कारण आने वाले विदेशियों की यहां कोई जगह नहीं है, सिवाय समुद्र के तल के।

मोजतबा खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर

समाह की शख्सियत

एक खिलौने के लिए रॉजर ने रची थी पूरी दुनिया

रॉजर स्वीट की क्रिएटिव सोच ने एनिमेशन की दुनिया में एक नए दौर की शुरुआत की। उन्होंने ही 'ही-मैन एंड द मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' जैसा आइकॉनिक शो और उसका सुपरहीरो किरदार ही-मैन (He-Man) दिया था।

आइडिया से आइकॉन तक

पिछले दिनों 91 साल की आयु में रॉजर स्वीट का निधन हो गया। टॉय कंपनी मैटल में काम के दौरान मस्कुलर हीरो के उनके कॉन्सेप्ट ने बच्चों की कल्पना को सीधे छू लिया। इसकी खास बात यह थी कि पहले खिलौना बनाया गया और फिर उसके लिए पूरी काल्पनिक दुनिया गढ़ी गई। उनकी क्रिएटिविटी ने एक पूरी पीढ़ी को प्रभावित किया।

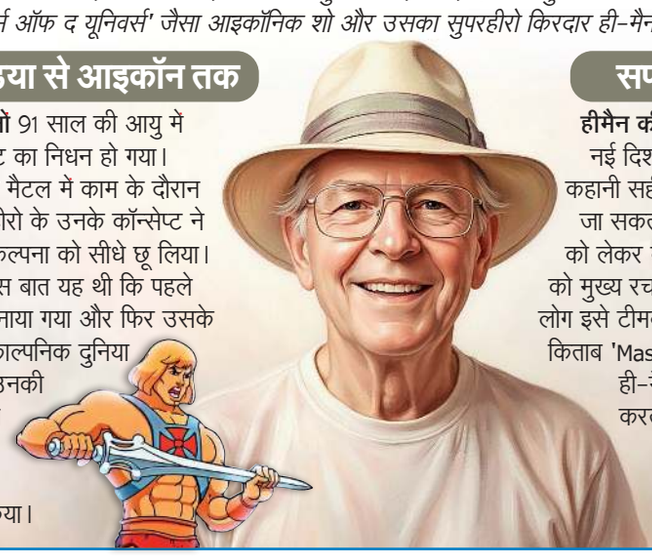

सफलता और सबक

हीमैन की सफलता ने टॉय इंडस्ट्री को नई दिशा दी। इसने दिखाया कि अगर कहानी सही हो तो उसे प्रॉडक्ट में बदला जा सकता है। हालांकि, इसके क्रिएशन को लेकर कई विवाद भी हुए। स्वीट खुद को मुख्य रचनाकार मानते रहे, जबकि कई लोग इसे टीमवर्क बताते हैं। फिर भी, उनकी किताब 'Mastering the Universe' और ही-मैन की लोकप्रियता यह साबित करती है कि उनका योगदान आज भी प्रभावशाली और प्रासंगिक बना हुआ है।

प्रस्तुति- अभिषेक मिश्र

जनता जंक्शन

इरफ़ान

लोगों की बात सरकार तक पहुंचाना मोर्चा लेना नहीं

*उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। BJP अभी से इसकी तैयारियों में जुट गई है। क्या है पार्टी की प्लानिंग और क्या चल रहा है संगठन के अंदर, ऐसे तमाम मुद्दों पर उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और BJP सांसद **त्रिवेंद्र सिंह रावत** से बात की **महेश पांडे** ने :*

■ आप राज्य में अवैध खनन, गिरती कानून-व्यवस्था और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते रहे हैं। आखिर नाराजगी क्या है आपकी?

मेरी नाराजगी किसी से भी नहीं। जनप्रतिनिधि होने के नाते जब हम सत्ता में होते हैं तो राज्य और जनता के प्रति जो जिम्मेदारी है, उसका अनुपालन नियम अनुकूल हो, इसकी कोशिश रहती है। मैं हरिद्वार से सांसद हूं। वहां और कई दूसरे जिलों से शिकायत आ रही थी कि खनन में माफिया घुस चुके हैं और नियमों को तोड़ा जा रहा है। मैंने मुख्यमंत्री से बात की और अधिकारियों से भी मामले को देखने को कहा। लेकिन, खनन माफिया न सरकार को कुछ समझते हैं और न जनप्रतिनिधियों को। इसलिए मैंने मामला उठाया। मंत्री हों या मुख्यमंत्री, उनको नियमों के बारे में अधिकारी खासतौर पर उनके सचिव बताते हैं। नियमों को लागू कैसे करना है, यह सीएम तय करते हैं।

■ आपने संसद में उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध खनन का मुद्दा उठाया, जबकि सरकार तो कहती है कि उसने इससे कई गुना अधिक राजस्व जुटाने में सफलता पाई है।

यह बात 100% सच है कि खनन से राजस्व बढ़ा है, लेकिन कई बार धन गौण हो जाता है, विशेषकर जब पर्यावरण को क्षति पहुंचने लगती है। पिछले दिनों दुनिया के सर्वाधिक गर्म शहरों की जो लिस्ट आई, उसमें 92 भारत के हैं। ऐसे में हमें पर्यावरण की अनदेखी के प्रति सजग रहने की जरूरत है। हर साल आग से हमारे जंगल, वन्यजीव खाक हो जाते हैं। अवैध खनन जैसी गतिविधियों की हमें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।

विशुद्ध राजनीति

इंटरव्यू

■ आपने बेरोजगारों पर लाठीचार्ज पर सवाल उठाए। अपराध रोकने में पुलिस की विफलता पर भी बात की। क्या यह सरकार से मोर्चा लेना नहीं?

बेरोजगारों के आंदोलन में न तोड़फोड़ हुई, न हिंसा। वे अपनी मांग शांतिपूर्ण तरीके से रख रहे थे। सरकार की भी जिम्मेदारी थी उनकी बात सुनना। मैंने यही बात कही और मुख्यमंत्री ने मेरी बात पर गौर किया। वह धरनास्थल पर पहुंचे और उनकी मांग मानते हुए परीक्षा पेपरलीक की CBI जांच का निर्णय लिया। मैंने जो किया, वह सरकार से मोर्चा लेना नहीं, उसकी सहायता करना हुआ।

■ इन दिनों चारधाम यात्रा से भारी अव्यवस्था की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि कई जगह भीड़ बेकाबू होने से यात्रियों को परेशानी हुई। क्या आपको लगता है कि आपके समय में गठित देवस्थानम बोर्ड से दिक्कत कम होती?

चारधाम में जिस तरह श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, हमें निर्णय लेना ही होगा। हमने त्वरित निर्णय लेने के लिए बोर्ड बनाया था। कई बार स्थितियां ऐसी होती हैं कि वहीं पर फैसला करना होता है। हमने तब इसके लिए FCRA लाइसेंस भी हासिल कर लिया था। विदेश में रह रहे कई हिंदू यहां दान भेजना चाहते हैं। इससे इनके विकास में योगदान मिलता। देवस्थानम बोर्ड जब विधानसभा में पास हुआ, तब मैं वहां मौजूद तक नहीं था। इस बोर्ड से पूरे क्षेत्र का कायाकल्प हो सकता था।

■ उत्तराखंड BJP में अंतर्कलह है?

किसी अंतर या बाहरी कलह की बात ही कहां है। आज पार्टी में लाखों नेता और उससे कहीं ज्यादा कार्यकर्ता हैं। सब आगे बढ़ना चाहते हैं। आगे बढ़ने की कोशिश को अंदरूनी झगड़े से नहीं जोड़ना चाहिए। जब बात पार्टी की आती है, तो सभी पूरी लगन के साथ उसकी बेहतरी के लिए जुट जाते हैं।

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें

www.speakingtree.nbt.in

बुद्ध ने अपना ज्ञान सबके साथ बांटने की दी सीख

आनंदमूर्ति गुरुमां

बुद्ध का हृदय दया और करुणा से भरा हुआ था। उनकी यही करुणा उनके उपदेशों के रूप में बहती है और लोगों को सही रास्ता दिखाती है। उनका मकसद केवल दुनिया को बदलना नहीं, इंसान के मन को समझकर उसे बाहरी दुनिया के साथ जोड़ना और उसके बीच संतुलन स्थापित करना भी था।

बुद्ध पूर्णिमा का दिन बहुत खास माना जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ, इसी दिन उन्हें ज्ञान मिला और इसी दिन उन्होंने इस संसार को छोड़ा। यह एक अनोखी बात है कि जीवन की शुरुआत, ज्ञान की प्राप्ति और अंत, तीनों एक ही दिन हुए। इसलिए बुद्ध पूर्णिमा को चेतना और जागरूकता का दिन भी कहा जाता है। भले ही आज बुद्ध हमारे बीच नहीं और लगभग ढाई हजार साल बीत चुके हैं, फिर भी उनकी सीख और करुणा आज भी लोगों के जीवन में दिखाई देती है। यह दिन हमें अपने भीतर झांकने और खुद को समझने का मौका देता है।

AI Image

पहले के समय में राजा-महाराजा अपने जन्मदिन पर लोगों के साथ दया का व्यवहार करते थे। कई बार वे इस मौके पर कैदियों को भी माफ कर देते। कई बार उपहार देकर अपनी प्रजा को संतुष्ट करते। जब एक सामान्य मनुष्य के रूप में एक दुनियावी राजा-महाराजा ऐसा कर सकता है तो बुद्ध तो समाटों के भी सम्राट थे, राजाओं के भी राजा थे। उनकी तुलना में बुद्ध तो बहुत बड़े और महान थे। इसलिए उनका यह दिन सिर्फ जन्मदिन नहीं, ज्ञान और शांति का भी दिन है।

एक कथा के अनुसार, जब बुद्ध गहरी ध्यान अवस्था में थे, तब देवता चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि अगर बुद्ध इसी तरह शांत होकर चले गए, तो लोगों को सही रास्ता कौन दिखाएगा। उन्होंने बुद्ध को अपना ज्ञान लोगों के साथ बांटने की सलाह दी। पहले बुद्ध ने कहा कि जो खोजेगा, वह खुद पा लेगा, जैसे मैंने बिना किसी गुरु के खोज लिया, ऐसे ही दूसरे भी खोज लेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने लोगों की भलाई के लिए अपना ज्ञान सबके साथ साझा करना शुरू किया।

बुद्ध पूर्णिमा हमें सिखाती है कि हम भी कुछ समय शांत रहें, ध्यान करें और अपने मन को समझें। यही उनके प्रति सच्चा सम्मान है- अपने भीतर अच्छाई लाना और सही रास्ते पर चलना।

आर.एन.आई.नं. 510/57 © सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। यह समाचार पत्र स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित, आशीष पांडे द्वारा संपादित (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी) तथा मनीष सिन्हा द्वारा, टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, 13/1&2, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद, गाजियाबाद (उ.प्र.) से और नवनीत आहूजा द्वारा, प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर-11, IMT मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा-122051 से मुद्रित। फोन : 23302000, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु. ; रविवार : नेपाली 6 रु.

संपादकीय

सरकारी तिजोरी खोला !

इराण युद्धाचे ढग अजून जगाच्या अवकाशात कायम आहेत. शांततेच्या बोलण्यांमध्ये इराण आता थोडा नरमला, तर अमेरिकेने ताठर भूमिका घेतली आहे. पेट्रोल-डिझेल या इंधनाच्या दरवाढीचे संकट दरवाजावर उभे आहे. विमानाच्या इंधनाची महागाई आकाशाला भिडल्याने कंपन्यांनी हात टेकले आहेत. ..आणि या सगळ्यांचे एक कारण असलेली रुपयाची घसरण हीच आता परिणामात परावर्तित झाली आहे. गुरुवारी एक डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत ९५च्या पुढे गेली आणि आधीची चिंता आता अधिकच गडद बनली. हा ऐतिहासिक नीचांक आहे आणि त्याची कारणे व परिणाम गुंतागुंतीचे आहेत. १९४७ मध्ये ३ रुपये ३० पैशांना मिळणारा डॉलर, १९६६ मध्ये साडेसात रुपये, १९९१ मध्ये २५ रुपये, २०१० मध्ये ४५ रुपये, २०२० मध्ये ७५ रुपये असे घसरणीचे टप्पे पार करीत स्वातंत्र्याच्या ऐंशीव्या वर्षात प्रवेशाच्या उंबरठ्यावर शंभरीच्या घरात आहे आणि स्वातंत्र्याला शंभर वर्षे होताना विकसित, समृद्ध, आत्मनिर्भर बनण्याच्या स्वप्नात हा मोठा अडथळा बनू पाहात आहे. १९६६ मध्ये भुकेचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आणि १९९१ मध्ये आर्थिक संकटावेळी भारताने स्वत:च केलेले रुपयाचे अवमूल्यन वगळता ही इतकी घसरण नैसर्गिक कारणांनी म्हणजे आयात-निर्यातीमधील, अर्थात व्यापारातील तुटीमुळे झाली. आताही तेल, सोने, कोळसा, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंच्या आयातीवर जास्त डॉलर खर्च होत असल्याने रुपयाची मागणी कमी झाली. कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतीचा फटका रुपयाला बसला. कर्जाचा डोंगर, त्यावर डॉलर्समध्ये मोजावे लागणारे व्याज, महसुली तूट, अमेरिकेन टॅरिफचा तडाखा आणि विदेशी गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारातून पैसे काढल्याने घसरणीची घसरगुंडी झाली. आता महागाई आणखी वाढेल. परदेशात शिकणाऱ्या मुलांसाठी अधिक पैसे मोजावे लागतील. सोने-चांदीचे दर वाढतील. आयात मालाच्या, खासकरून इंधनाच्या किमती आणखी वाढतील. डिझेलची किंमत वाढली की वाहतुकीचा खर्च वाढेल आणि त्यामुळे अगदी भारतातच तयार होणाऱ्या जीवनावश्यक वस्तूही महागतील. रुपयाच्या घसरणीचा थोडाबहुत फायदा होईल तो निर्यातीच्या रूपाने. आपण कपडे, औषधे, सॉफ्टवेअर, अभियांत्रिकी उत्पादने, हस्तकलेची उत्पादने प्रामुख्याने निर्यात करतो. पण, या उत्पादनांसाठी लागणारा बराचसा कच्चा मालदेखील आयात करावा लागतो आणि त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारात डॉलर्सच मोजावे लागतात. तरीदेखील रुपया घसरल्यामुळे ही निर्यातक्षम उत्पादने परदेशी खरेदीदारांना स्वस्त वाटतात. निर्यात वाढली तर देशात जास्त डॉलर येतात. यामुळे व्यापारातील घाटा कमी होण्यास मदत होते. पण, या फायद्याला मर्यादा आहेत आणि तीच सध्या मोठी चिंता आहे. ही चिंता केवळ आजची नाही आणि एखादी कळ फिरवून ती मिटणारीही नाही. हे असे संकट आहे की, ज्यावर सतत नजर ठेवावी लागते. रोज उपाय शोधावे लागतात. विदेशी मुद्राभांडार वाढविणे, व्याजदर बदलणे किंवा बाजारात हस्तक्षेप करणे असे उपाय रिझर्व्ह बँक आताही करील. पण, ते अल्पकालीन असतात. निर्यात वाढविणे, आयात कमी करणे, उत्पादनक्षमता वाढविणे आणि महागाई आटोक्यात ठेवणे, हे सरकारकडून अपेक्षित असलेले दीर्घकालीन उपाय दिसतात तितके सोपे नाहीत. त्यासाठी आत्मनिर्भर भारत वगैरे घोषणांच्या पलीकडे पाहण्याची आणि प्रत्यक्ष कृतीची गरज असते. या आघाडीवर आतापर्यंतचा अनुभव फार उत्साहवर्धक नाही. दरवेळी रुपया घसरला की, वित्तमंत्री किंवा सरकारमधील उच्चपदस्थांची भाषा असते की, चिंता करण्याचे कारण नाही. तेवढ्याच्या आधारे व्हॉट्सॲप युनिव्हर्सिटीत विद्वान बनलेली फौज सरकारच्या बचावासाठी सोशल मीडियावर सक्रिय होते. आभासी वादावादीतून प्रत्यक्ष सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळत नाही. तो मिळावा आणि महागड्या डॉलर्सची झळ कमी राहावी, यासाठी सरकार काय करणार आहे, हाच खरा प्रश्न आहे. आधीच्या संकटावेळी केले तसे रुपयाचे स्वत:च आणखी अवमूल्यन शक्य नाही. ती दुधारी तलवार आहे. तिचे तोटे लगेच होतात आणि फायदे उशिरा मिळतात. तेव्हा, महागाईला आळा हे एकच लक्ष्य सरकारने नजरेसमोर ठेवण्याची गरज आहे. तसेही सांगितले जातेच की, देशात भरपूर विदेशी चलनसाठा आहे. विकासाचा वेग चांगला आहे. आर्थिक स्थिती भक्कम आहे. मधली अनेक वर्षे कच्चे इंधन स्वस्त असताना सरकारी गंगाजळीदेखील बरीच फुगली आहे. तिचा वापर केवळ खिरापत वाटून निवडणुकीत मते मिळविण्यासाठी न करता रुपयाच्या घसरणीचे दुष्परिणाम रोखण्यासाठी करायला हवा.

महाराष्ट्राचे पाऊल निरंतर प्रगतीच्या दिशेनेच..

केवळ भौगोलिक रचनेतून नव्हे, तर महाराष्ट्र धर्मातून महाराष्ट्र प्रकट होतो. महाराष्ट्र म्हणजे इतिहास, भूगोल आणि संस्कृतीचा समुच्चय आहे.

देवेंद्र फडणवीस
मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य

यंदाचा महाराष्ट्र दिन विशेष आहे. महात्मा जोतिराव फुले यांच्या २०० व्या जयंतीचे हे वर्ष आहे, संत गाडगे महाराज यांच्या १५०व्या जयंतीचे वर्ष आहे, चवदार तळ्याच्या ऐतिहासिक लढ्याचे शताब्दी वर्ष आहे. हे वर्ष आपण समता आणि सामाजिक समरसता वर्ष म्हणून साजरे करतो आहोत. केवळ भौगोलिक रचनेत महाराष्ट्र व्यक्त होत नाही तर महाराष्ट्र धर्मातून महाराष्ट्र प्रकट होतो. महाराष्ट्र म्हणजे इतिहास, भूगोल आणि संस्कृतीचा समुच्चय आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी दिलेली स्वराज्याची प्रेरणा, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घालून दिलेला न्याय आणि प्रज्ञेचा पाया, महात्मा जोतिराव फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी पेटविलेली शिक्षण आणि समतेची मशाल, लोकमान्य टिळकांनी जागविलेली राष्ट्रभावना, देशासाठी अनन्यसाधारण यातना सहन करण्याची ताकद देणारे स्वातंत्र्यवीर सावरकर या सगळ्यांच्या विचारांचा एकत्रित संगम म्हणजे महाराष्ट्र. केवळ भौगोलिक रचनेत महाराष्ट्र व्यक्त होत नाही तर महाराष्ट्र धर्मातून प्रकट होतो.

जगातील ३०वी अर्थव्यवस्था

महाराष्ट्र देशाच्या जीडीपीमध्ये १३.५ टक्क्यांहून अधिक योगदान देत आहे. २०२४-२५ मध्ये महाराष्ट्राने १,६४,८७५ कोटी रुपयांची थेट परकीय गुंतवणूक आकर्षित केली. हे प्रमाण देशात आलेल्या एकूण एफडीएच्या ३९ टक्के इतके आहे. दावोसमधील वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरममध्ये महाराष्ट्राने ३० लाख कोटींचे सामंजस्य करार केले, ज्यातून ४० लाख रोजगार निर्माण होणार आहेत. जगात आर्थिक समस्या असताना महाराष्ट्राने जगातील ३०वी अर्थव्यवस्था म्हणून झेप घेतली आहे, हा विकास समतोल असावा, याचा विचार करून गडचिरोली, धुळे, नंदुरबार यांसारखी शहरेसुद्धा आता गुंतवणुकीच्या नकाशावर आली आहेत.

जलयुक्त शिवारचे लक्ष्य

यावर्षी पाऊस सरासरीपेक्षा कमी असेल, असा अंदाज आहे. त्यामुळे पेरणीची घाई करू नका. कृषी विभागाकडून येणाऱ्या प्रत्येक सूचनांकडे लक्ष द्या. राज्य शासन म्हणून आम्ही आधीपासूनच पाणी, चारा याचे नियोजन प्रारंभ केले आहे. जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवारच्या कामांना गती देण्यास व प्राधान्याने निधी देण्यास सांगितले आहे. राज्यात खते आणि बियाणांची कोणतीही कमतरता नाही. लिंकिंग करणाऱ्या दुकानांवर कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. राज्य शासन तुमच्यासोबत आहे.

शेतकरी कर्जमाफी योजना

गेल्यावर्षी पूर आणि अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर १५,५७६ कोटी रुपये जमा केले गेले. शेतकऱ्यांसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना आपण जाहीर केली आहेच. शेतकऱ्यांना मोफत वीज दिली जात आहे, आता सौरऊर्जेचा मोठा कार्यक्रम हाती घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्राला २०४७ पर्यंत ५ ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनवण्याचे स्वप्न आणि त्या दिशेने आपण आत्तापासूनच काम सुरू केले आहे.

सुप्रशासनासाठी अनेक पावले

शासनाच्या सर्व सेवा व्हॉट्सॲपवर देण्यासाठी मोठा पुढाकार घेण्यात आला आहे. गडचिरोली नक्षलमुक्त झाले आहे आणि पोलाद शहर म्हणून नावारूपास येण्यासाठी वेगाने पाऊले टाकते आहे. महाराष्ट्रातील ११ किल्ले युनेस्को जागतिक वारसा यादीमध्ये समाविष्ट झाले आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पराक्रमाची ही जगाने घेतलेली दखल आहे. महाराष्ट्र मजबूत, आत्मनिर्भर, महत्त्वाकांक्षी आहे. शेतकरी, कामगार, महिला, तरुण, उद्योजक प्रत्येकासाठी या राज्य शासनाने आपली कटिबद्धता सिद्ध केली आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विकसित भारत २०४७ च्या स्वप्नात महाराष्ट्र सर्वात पुढे राहील, हे माझे महाराष्ट्रदिनी आपल्याला वचन आहे.

वाढवण येथे चौथे बंदर

महाराष्ट्र आज देशातच नाही, जगातही पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीत आघाडीवर आहे. सध्या मुंबई, पुणे आणि नागपूरमध्ये १७३ किलोमीटरच्या मेट्रो मार्गिका कार्यरत आहेत. दरवर्षी ५० कि.मी.ची मेट्रो सेवेत येईल, असे नियोजन आहे. समृद्धीच्या साथीला शक्तिपीठ येतो आहे. वाढवण येथे चौथे मुंबई बंदर विकसित केले जाणार आहे, जे जगातील 'टॉप टेन' पैकी एक असेल. आज महाराष्ट्रदिनी मला एक अत्यंत आनंदाची बातमी सांगायची आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील १३.३ कि.मी.चा 'मिसिंग लिंक' प्रकल्प आज जनतेसाठी खुला होत आहे. यामुळे दोन शहरांमधील अंतर सुमारे ६ कि.मी.ने आणि प्रवासाचा वेळ २५ ते ३० मिनिटांनी कमी होणार आहे.

५० लाख लखपती दीदी

४० लाखांहून अधिक महिला आता 'लखपती दीदी' झाल्या आहेत. उमेद अभियानांतर्गत ६४ लाखांहून अधिक कुटुंबांना बँक कर्जे उपलब्ध करून दिले आहे. लखपती दीदींची संख्या यावर्षी ५० लाखांपर्यंत नेण्याचे नियोजन आहे. लाडकी बहीण योजना आहेच. सारथी, बार्टी, महाज्योती, आर्टी, वनार्टी, अमृतच्या माध्यमातून समावेशकतेची पायाभरणी केली जाते आहे. आमच्यासाठी विकास म्हणजे प्रत्येकाचे जीवन उंचावणे आहे.

१० पायऱ्या चढायला ४० वर्षे लागतात, तेव्हा...

हल्ली अनेकांना पायऱ्या चढायच्या नसतात, त्यांना लिफ्ट हवी असते. भाजपने मात्र पक्षासाठी वर्षानुवर्षे पायपीट केलेल्यांचा सन्मान केला आहे !

यदु जोशी
राजकीय संपादक, लोकमत

विधान परिषदेचा उमेदवारी अर्ज भरायला भाजपचे सुनील कर्जतकर आले होते, ते जरा झुकून चालतात, त्यांच्या नम्रतेने त्यांना झुकवले आहे. विधानभवनच्या दहा पायऱ्या चढून आमदारकीचा अर्ज भरायला ते गेले त्यामागे ४० वर्षे पक्षासाठी केलेले कष्ट आहेत. सामाजिक आणि राजकीयदृष्ट्या महाराष्ट्रातील प्रत्येक तालुक्याची खडान्‌खडा माहिती असलेले जे पाचजण आहेत, त्यात कर्जतकर एक आहेत. पक्षाने सांगितले तसे ते चालत राहिले, गावोगावी एसटीने तर कधी दुचाकीने उन्हातान्हात फिरले.

नागपूरचे संजय भेंडे ३५ वर्षांहून अधिक काळ भाजपचे काम करताहेत. आधीही आमदारकीसाठी त्यांचे नाव चर्चेत आले; पण जमले नाही. त्यांनीही आरडाओरड केली नाही. माधवी नाईक, प्रमोद जठारदेखील तसेच. चौघेही पक्षनिष्ठेबाबत २४ कॅरेट. निष्ठेचे फळ एक ना एक दिवस मिळते याचे हे ठसठशीत उदाहरण. निष्ठा बरेचदा त्वरित फळ देत नाही, पण वेळ आल्यावर व्याजासकट परतफेड करते.

लोकांना या चौघांनी चढलेल्या विधान परिषदेच्या पायऱ्या दिसल्या; पण त्या आधी केलेली शेकडो किलोमीटरची पायपीट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दिल्लीला दिसली म्हणून ते आमदार होत आहेत. आजकाल अनेकांना पायऱ्या चढायचा, पायपीट करायचा कंटाळा येतो, त्यांना लिफ्ट हवी असते. विनाकष्टाने सहज काही मिळण्याची अपेक्षा असलेल्यांची पक्षात गर्दी होत असताना आपली हयात पक्षासाठी दिलेल्या जुन्याजाणत्यांना संधी देऊन फडणवीसांसह दिल्लीतील नेतृत्वानेही एक मेसेज दिला आहे. लिफ्टने वर गेलेल्यांना मजले आठवत नाहीत, पायऱ्यांनी चढलेल्यांना प्रत्येक पायरीची कथा सांगता येते. निष्ठा ही आंधळी असते बरेचदा, पुढे काय मिळणार हे दिसत नसतानाही ती चालत राहते. पक्षाकडून जगण्याची सोय बघणारे अनेक असतात; पण पक्षासाठी जगणाऱ्यांचे मोल होणे महत्त्वाचे असते; ते यावेळी झाले आहे. संघर्ष वाया जात नाही, तो संधीच्या रूपाने असा परत येतो. उमेदवारीत भाजपने क्षेत्रीय, सामाजिक संतुलनही साधले.

यांनाच संधी का दिली?

सुनील कर्जतकर यांना संधी दिल्याची प्रतिक्रिया अशी आहे की, ज्यांना कधीच काही मिळाले नाही त्यांना मिळाले. कर्जतकर ब्राह्मण; त्यांना उमेदवारी दिल्याने दुसरे ब्राह्मण विदर्भाचे संघटनमंत्री डॉ. उपेंद्र कोठेकर आणि तिसरे ब्राह्मण पुण्याचे राजेश पांडे राहून गेले. एकच्या वर ब्राह्मण देता येणार नाही असा दिल्लीचा निरोप होता म्हणतात. नागपूर-विदर्भात एक आमदारकी दिलीच पाहिजे यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस आग्रही होते अन् संजय भेंडेंचे नाव पुढे आले. कोठेकर यांचे तिकीट 'आरएसी'पर्यंत आले होते, पण ते कन्फर्म न होता, वेटिंगवर असलेल्या भेंडेंचे तिकीट कन्फर्म झाले. कर्जतकर आणि राजेश पांडे असा टाय आला होता; पण मुंबईतील भाजपचे नेते कर्जतकरांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहिले, एका अर्थाने हा मुंबईने केलेला पुण्याचा पराभव आहे.

पक्षात ४० वर्षे काम केल्यानंतर विधानभवनच्या पायऱ्या चढताना सुनील कर्जतकर.

विवेक कोल्हे आणि प्रमोद जठार या दोघांमध्ये एक समानता आहे. त्यांच्या जिल्ह्यातील प्रस्थापित नेत्यांना एक मेसेज दिला गेला की तुम्हाला महत्त्व दिले असले तरी पक्षातील जुन्याजाणत्यांचे आणि प्रभावी नेत्यांचे बोट सोडले जाणार नाही. सिंधुदुर्गातील भाजप म्हणजे राणे असे चित्र असताना जठारांना आमदारकी दिली. तसेच कोपरगावमध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी कोल्हे परिवाराने संयम दाखवला आणि ज्यांच्याशी अनेक वर्षांचा संघर्ष आहे अशा काळेंच्या पाठीशी ते भक्कमपणे उभे राहिले. चार महिन्यांपूर्वीच्या निवडणुकीत कोल्हेंनी नगरपालिकेवर भाजपचा झेंडा फडकवला, ते तर आहेच शिवाय कोल्हे शिक्षण आणि सहकारातील दिग्गज नाव आहे. विखेंचे महत्त्व कायम ठेवत त्यांचे अंतर्गत विरोधक असलेले कोल्हे यांनाही महत्त्व दिलेच जाईल, असे विवेक यांना आमदारकी देऊन भाजप नेतृत्वाने स्पष्ट केले आहे. स्नेहलताताईंनी आमदारकीला थांबावे लागले, तेव्हा फडणवीस यांनी दिलेला शब्द विवेक यांना आमदारकी देऊन पाळला.

फडणवीसांच्या टीममध्ये एक चांगली भर पडली आहे. ४० वर्षांच्या निष्ठेची कदर झाली अन् पक्षांतर करणाऱ्यालाही (बच्चू कडू) झटपट उमेदवारी मिळाली. संयमी, अभ्यासू अशा डॉ. नीलम गोऱ्हे यांना एकनाथ शिंदे यांनी पुन्हा संधी दिली. मातोश्रीची साथ सोडून त्या शिंदेंसोबत गेल्या, शिंदेंनी त्यांना रिटर्न गिफ्ट दिले. 'झेंडा बदलला, पण अजेंडा तोच आहे' हे वाक्य इम्प्रेशन मारायला ठीक आहे, पण आमदारकीसाठी शिंदेसेनेत प्रवेश घेऊन बच्चूभाऊंनी स्वत:ची धार स्वत:च बोथट करून घेतली आहे. त्यांच्या रूपाने शिंदेंनी भाजपचा एक विरोधक जवळ केला आहे.

yadu.joshi@lokmat.com

जगभर

पाकमध्ये फुग्यात गॅस भरून होतोय स्वयंपाक !

अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यातील युद्धात पाकिस्तानला मध्यस्थीची संधी मिळाली असली आणि पाकिस्तान त्यामुळे स्वत:ची पाठ थोपटून घेत असला तरी, निदान आजवर तरी पाकिस्तानची ही मध्यस्थी कुणालाच फायद्याची ठरलेली नाही. उलट इराणच्या अनेक तज्ज्ञांनी पाकिस्तान हा भरवशाचा देश नसल्यानं पाकिस्तानऐवजी भारत मध्यस्थ असायला हवा होता, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.

पाकिस्तान कितीही गमजा मारत असला तरी त्यांना रोज नव्यानं नवनवीन समस्यांना तोंड द्यावं लागतंय. पाकिस्तानात जवळपास प्रत्येक गोष्टीची टंचाई आहे आणि प्रत्येक वस्तूचे भाव गगनाला भिडलेले आहेत. स्वयंपाकाचा गॅस तर तिथे जवळपास हद्दपारच झाला आहे. सर्वसामान्यांना स्वयंपाकाचा गॅस मिळणं दुरापास्त झाल्यानं अनेकांनी आता फुग्यामध्ये एलपीजी गॅस भरून त्यावर स्वयंपाक करणं सुरू केलं आहे. तज्ज्ञांनी याबाबत तीव्र चिंता व्यक्त केली असून, हा प्रकार म्हणजे चालता-फिरता बॉम्ब असल्याचं म्हटलं आहे. हा 'बॉम्ब' केव्हाही, कोणाचाही जीव घेईल, त्यामुळे हा प्रकार तातडीनं बंद व्हावा आणि नागरिकांना तातडीनं एलपीजी गॅसचा पुरवठा करावा, अशी मागणी केली आहे. पाकिस्तानात गॅसची मोठी कमतरता असल्यामुळे लोक आता प्लॅस्टिकच्या फुग्यांमध्ये गॅस भरून त्याद्वारे स्वयंपाक करू लागले आहेत.

हा धोकादायक प्रकार विशेषतः कराचीमध्ये पाहायला मिळत आहे. तिथल्या लोकांचं म्हणणं आहे, सातत्यानं मागणी करूनही गॅस मिळत नाही. अनियमित गॅसपुरवठ्यामुळे 'जुगाड' करण्याशिवाय आता त्यांच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय शिल्लक नाही. स्वयंपाकासाठी गॅस मिळावा यासाठी लोक एका खास प्रकारच्या प्लास्टिकच्या फुग्यांमध्ये गॅस भरतात. थोड्या वेळासाठी गॅस पुरवठा झाला की हे फुगे भरून घेतले जातात आणि नंतर त्याचाच वापर करून स्वयंपाक केला जातो.

हे फुगे स्थानिक बाजारात सुमारे १००० ते १५०० रुपयांमध्ये उपलब्ध आहेत. तज्ज्ञांनी ही पद्धत अत्यंत धोकादायक असल्याचं म्हटलं आहे. सुरक्षा विश्लेषकांचं म्हणणं आहे, प्लॅस्टिकच्या फुग्यांमध्ये गॅस भरणं म्हणजे 'मोबाइल बॉम्ब'सारखं आहे, कारण अगदी हलकं घर्षण, उष्णता किंवा ठिणगीही मोठा स्फोट घडवू शकते. घरांमध्ये अशा गॅसनं भरलेले फुगे ठेवणं म्हणजे स्वत:हून अपघाताला आणि मृत्यूला निमंत्रण आहे. विशेषतः दाट लोकवस्ती असलेल्या भागांमध्ये याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

अमेरिका आणि इराणमध्ये सुरू असलेल्या तणावामुळे ऊर्जा पुरवठा साखळी प्रभावित झाली आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या मार्गावरही परिणाम झाल्यानं गॅस आणि तेल पुरवठा संकटात आहे. कराचीमध्ये अनेक वर्षांपासून गॅसची कमतरता, कमी दाब आणि दीर्घकाळ कपातीची समस्या सुरू आहे. हिवाळ्यात तर परिस्थिती आणखी वाईट होते, कारण त्यावेळी मागणी आणखी वाढते आणि पुरवठा तर जवळपास बंद झाला आहे. त्यामुळे नागरिकांचे हाल होत आहेत.

घरगुती गॅस (मिथेन/एलपीजी) अत्यंत ज्वलनशील असतो. थोडीशीही गॅसगळती झाली आणि जवळ ठिणगी, काडेपेटी किंवा विजेचा स्पार्क आला, तर लगेच आग पसरू शकते किंवा स्फोट होऊ शकतो. म्हणूनच तज्ज्ञांनी हा चालता-फिरता बॉम्ब' आपल्यापासून दूरच ठेवण्याचा सल्ला दिला आहे.

जनमन

शाश्वत विकास, आजची अपरिहार्य गरज

विकासाच्या शर्यतीत जग वेगाने धावत असताना, 'शाश्वत विकास' हा शब्द केवळ चर्चेपुरता मर्यादित राहू नये. आर्थिक प्रगती, औद्योगिकीकरण आणि नागरीकरण यामुळे जीवनमान उंचावले असले, तरी त्याची किंमत पर्यावरणाच्या ऱ्हासाच्या रूपाने मोजावी लागत आहे. त्यामुळे विकास आणि पर्यावरण यांच्यात समतोल राखणे ही आजची सर्वांत मोठी गरज ठरते. गेल्या काही दशकांत पाणीटंचाई, हवामान बदल, जंगलतोड आणि प्रदूषण यांसारख्या समस्या गंभीर होत चालल्या आहेत. शहरांमध्ये वाढत चाललेले प्रदूषण, तर ग्रामीण भागात कमी होत चाललेले जलस्रोत, ही त्याची जिवंत उदाहरणे आहेत. नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा अतिरेकाने वापर केल्यामुळे भविष्यातील पिढ्यांसाठी संकट उभे राहण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळे आजचा विकास उद्याच्या विनाशाचे कारण ठरू नये, याची खबरदारी घेणे आवश्यक आहे.

शाश्वत विकास म्हणजे असा विकास, जो वर्तमानाच्या गरजा पूर्ण करताना भविष्यातील पिढ्यांच्या गरजांवर परिणाम करत नाही. ही संकल्पना केवळ पर्यावरणापुरती मर्यादित नसून, ती सामाजिक आणि आर्थिक समतोल साधण्यावरही भर देते. उदाहरणार्थ, ऊर्जा बचत, जलसंवर्धन, पुनर्वापर आणि पुनर्निर्मिती यांसारख्या उपाययोजना केवळ पर्यावरणाचे संरक्षण करीत नाहीत, तर आर्थिकदृष्ट्याही फायदेशीर ठरतात. सरकारकडून विविध योजना राबविल्या जात असल्या, तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि जनसहभाग महत्त्वाचा आहे. शाश्वत विकास ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून, प्रत्येक नागरिकाची सामूहिक जबाबदारी आहे.

- वीरेंद्र सोनवणे, पुणे

समकालीन महत्त्वाचे मुद्दे मांडणारी, नवी चर्चा सुरू करणारी वाचक-पत्रे या स्तंभामध्ये प्रसिद्ध केली जातील. आपली पत्रे येथे पाठवा : **janman@lokmat.com**

आंदोलनांचे अंतरंग

एका खुर्चीसाठी १८ वर्षे कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवल्या, कारण...

पाण्यासाठीच्या आंदोलनातील एक आक्रमक महिला 'जीजी' थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर जाऊन बसल्या ! समजावले, तरी त्या ठाम होत्या.

डॉ. नीलम गोऱ्हे
उपसभापती, महाराष्ट्र विधान परिषद

काळाच्या ओघात गावागावांत नळ आले, घरापर्यंत पाणी पोहोचले, तरीही आजही गरिबी आणि जातिपातीचा फटका दलित व गरीब समाजातील स्त्रियांना बसतो. जात स्पष्टपणे समोर येत नसली, तरी पाण्याचा संघर्ष हा थेट अस्तित्वाचा लढा ठरतो. पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुका आणि महाराष्ट्रातील काही गावांमध्ये आजही महिलांना पाण्याच्या एका टँकरसाठी मोठी पायपीट करावी लागते. १९९०च्या दशकात तर या गावांची संख्या मोठी होती.

१९९५च्या सत्तांतरानंतर 'टँकर राज' हा शब्द रूढ झाला. टँकरची व्यवस्था चालू राहावी, यासाठी काही हितसंबंधी प्रयत्न करतात, असे आरोपही झाले. पण जिथे पाण्याचे स्त्रोतच नाहीत, तिथे ग्रामपंचायतीचा ठराव, तहसीलदारांची उपस्थिती आणि विशिष्ट अर्जाची पूर्तता केल्याशिवाय टँकर मिळत नाही. ही प्रक्रिया अत्यंत क्लिष्ट आणि वेळखाऊ ठरते, परिणामी महिला आंदोलनात सहभागी होतात.

आम्ही पाण्याच्या प्रश्नावर एकदा पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महिलांचा मोठा मोर्चा आयोजित केला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांची भेट घेण्यासाठी आम्ही वेळ मागितली; पण बाहेर उभ्या असलेल्या शेकडो महिला अतिशय अस्वस्थ आणि संतापलेल्या होत्या. कित्येकींच्या डोळ्यात पाणी होते, तर काहीजणी आक्रमक झाल्या होत्या.

माझ्यासोबत रिपब्लिकन पक्षाचे नेते ॲड. जयदेव गायकवाड आणि मुरलीधर जाधव, एल.डी. भोसले, वसंत साळवे होते. सर्वच महिलांना शिष्टमंडळात यायचे होते. गर्दी एवढी होती की कार्यालयाचा जिना आणि गच्ची महिलांनी भरून गेली. तरीही गर्दी आवरत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या दालनात आम्ही काही मोजके नेते शिरलो. परंतु २०/२५ माणसे बसतील अशा दालनात ६०/७० महिला हळूहळू आल्या. महिला पोलिसांची संख्या तेव्हा कमी असे. परिणामी पोलिस व कार्यकर्ते यांना न जुमानता महिला आत येतच होत्या. शेवटी दालन महिलांनी भरून गेले.

अचानक अजबच म्हणायची अशी घटना घडली. आंदोलनातील एक आक्रमक महिला, 'जीजी' थेट जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर जाऊन बसल्या ! मी त्यांना समजावून सांगितले; पण त्या ठाम होत्या.

तेवढ्यात जिल्हाधिकारी आत आले आणि समोरचे दृश्य पाहून थक्क झाले. त्यांच्या इतक्या वर्षांच्या कारकिर्दीत कदाचित पहिल्यांदाच जनतेने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीचा ताबा घेतला होता. मी कशीबशी परिस्थिती सावरली, त्यानंतर निवेदन देण्यात आले. प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले आणि आठ दिवसांत पाणीपुरवठ्याची व्यवस्था झाली.

आंदोलन यशस्वी झाले; पण काही दिवसांतच पोलिसांचे 'प्रेमळ' पत्र आले ! आमच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. 'जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर बसून गोंधळ घातला आणि प्रशासकीय कामात अडथळा आणला,' असा आमच्यावर आरोप होता. आम्ही महिलांना खुर्चीवर बसण्यासाठी प्रोत्साहित केले नव्हते, तरीही नैतिक जबाबदारी म्हणून तो गुन्हा आमच्या नावावर नोंदवला गेला.

१९९०च्या दशकात सुरू झालेली ही न्यायालयीन लढाई तब्बल २००७ पर्यंत चालली. दरम्यानच्या काळात २००२ मध्ये मी आमदार झाले, त्यानंतर जयदेव गायकवाडही आमदार झाले. अखेर १८ वर्षांनंतर आम्ही या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त झालो.

एका खुर्चीसाठी आम्हाला १८ वर्षे कोर्टाच्या पायऱ्या झिजवाव्या लागल्या. पण जेव्हा सामान्यातील सामान्य माणूस आपल्या हक्कासाठी त्या खुर्चीपर्यंत पोहोचतो, तेव्हा सगळे खडबडून जागे होतात. पाण्याचा तो संघर्ष आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या खुर्चीवर बसलेल्या महिलेचा तो आवेश आजही माझ्या स्मरणात कायम आहे. तेव्हापासून शिष्टमंडळे व मोर्चात मी शिस्त पाळायची फार खबरदारी घेते !

neeilamgorhe@gmail.com

तिरकस आणि चौकस

गजानन घोंगडे

हे पत्र लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेडच्या वतीने मुद्रक व प्रकाशक **बालाजी मुळे** यांनी प्लॉट नं. ए - ८१८ इंडस्ट्रियल एरिया, एम.आय.डी.सी., महापे, नवी मुंबई येथे मुद्रित करून 'लोकमत', पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई कार्यालय - ४००७०५ येथून प्रसिद्ध केले. ● दूरध्वनी क्र : ०२२ ४६०४१७८४
● **मुंबई कार्यालय :** लोकमत मीडिया प्रा. लिमिटेड, तिसरा मजला, पारिजात हाउस, प्लॉट नं. १०७६, आपटे इंडस्ट्रियल इस्टेट, लक्ष्मीनरसिंग पपन मार्ग, डॉ. ई मोझेस रोडसमोर, गांधीनगर, वरळी, मुंबई, ४०००१८. ● दूरध्वनी क्र : ०२२- ४६०३५९३०, ०२२- ४७५०७९४६ ● **ठाणे कार्यालय :** वेस्टर्न व्ह्यू, श्री गजानन महाराज चौक, वारकरी भवनाजवळ, ठाणे, फोन : २५४४१९०५, २५३८१७७४ ● **नवी मुंबई कार्यालय :** पृथ्वी पार्क, सेक्टर ३०, सानपाडा, नवी मुंबई ४००७०५. फोन : ०२२ ४६०४१७८४ ● संस्थापक संपादक : **स्व. जवाहरलाल दर्डा** ● मानद संपादिका : **श्रीमती उषाताई दर्डा** ● चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड : **डॉ. विजय दर्डा** ● एडिटर इन चिफ : **राजेंद्र दर्डा** ● समूह संपादक : **विजय बाविस्कर**
● संपादक : **अतुल कुलकर्णी*** (*पी. आर. बी. कायद्यानुसार संपादकीय जबाबदारी यांची आहे.) 'लोकमत'मधील लेखांचे हक्क राखून ठेवले आहेत. लोकमत ® हे चिन्ह लोकमत मीडिया प्रायव्हेट लि. चे. व्यापारचिन्ह आहे.

संपादकीय जागरण

शुक्रवार, 1 मई, 2026 : वैशाख पूर्णिमा वि. 2083

सफलता कोई गंतव्य नहीं, अपितु निरंतर चलने वाली यात्रा है

साइबर ठगों के साथी

कानपुर में चार बैंक मैनेजरों समेत आठ साइबर ठगों की गिरफ्तारी इस आशंका की पुष्टि करती है कि बैंक कर्मियों और आनलाइन ठगी करने वालों में मिलीभगत कायम हो गई है। आमतौर पर साइबर ठग ठगी की रकम इधर-उधर करने के लिए किसी अन्य के खातों यानी म्यूल खातों का सहारा लेते हैं। ऐसे तमाम खाते बैंक अधिकारियों की साठगांठ से खुलते हैं। कानपुर का प्रसंग पहला ऐसा प्रकरण नहीं, जिसमें साइबर ठगी के किसी मामले में बैंक अधिकारियों की भूमिका पाई गई हो। हाल के समय में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जो यह बताते हैं कि बैंक अधिकारी साइबर ठगों से मिलकर फर्जी या म्यूल खाते खुलवाते हैं। कुछ समय पहले लखनऊ में एक बैंक मैनेजर समेत चार लोगों को साइबर धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह तेलंगाना पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाकर साइबर ठगों से मिलीभगत में दो बैंकों के मैनेजरों को गिरफ्तार किया था। ये बिना सत्यापन के खाते खुलवाते थे और इसके बदले साइबर ठगों से कमीशन लेते थे। कुछ बैंक मैनेजर डिजिटल अरेस्ट के जरिये की जाने वाली ठगी के मामले में भी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।

साइबर ठगी के मामलों में बैंकों की संदिग्ध भूमिका का सबसे पहले उल्लेख सुप्रीम कोर्ट ने तब किया था, जब वह डिजिटल अरेस्ट के नाम पर की जाने वाली ठगी के मामलों की सुनवाई कर रहा था। उसके आदेश-निर्देश के बाद साइबर ठगों के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू हुई और उनकी गिरफ्तारियां भी हुईं। इसके अतिरिक्त रिजर्व बैंक के निर्देश पर भी बैंकों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके ऐसी पहल शुरू की, जिससे ठगी का पैसा द्रुत गति से एक खाते से दूसरे और दूसरे से तीसरे में हस्तांतरित हो तो बैंकों को इसकी भनक लग जाए, पर यह ध्यान रहे कि साइबर ठग धोखाधड़ी के नए-नए तौर-तरीके इस्तेमाल करने में माहिर हैं। चूंकि इसकी भरी-पूरी आशंका है कि साइबर ठग आनलाइन धोखाधड़ी पर लगाम लगाने के लिए सक्रिय एजेंसियों को मात देने के लिए अपने तौर-तरीके बदल सकते हैं, इसलिए उन्हें सतर्क रहना होगा। वैसे भी यह देखने को मिलता रहा है कि पुलिस एवं अन्य एजेंसियां डाल-डाल हैं तो साइबर ठग पात-पात। इसकी भी अनदेखी न की जाए कि साइबर ठग भी एआइ समेत अन्य आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करने में सक्षम हैं। इसी कारण वे विदेश में बैठकर भी साइबर ठगी को अंजाम देते रहते हैं। साइबर ठगों की धरपकड़ में तेजी आने के बाद भी यह शुभ संकेत नहीं कि उनके दुस्साहस में कोई कमी आती नहीं दिखती। साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए एजेंसियों की अपनी सक्रियता का स्तर बढ़ाने के साथ यह भी आवश्यक है आम लोगों को कम से कम इतना तो पता होना ही चाहिए कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती।

गंभीर मामला

शालीमार बाग क्षेत्र में दो घरों से लगभग ढाई करोड़ रुपये के स्वर्ण आभूषण और नकदी चुराने वाली घरेलू सहायिका को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जांच के दौरान विभिन्न बैंकों में उसके 15 गोल्ड अकाउंट मिले हैं, जिनमें वह चोरी का सोना रखती थी। उसके ऊपर पहले भी अपराधिक मामला दर्ज हो चुका है। इस घटना से पुलिस और बैंकों की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। पुलिस को सत्यापन की प्रक्रिया को आसान बनाने के साथ-साथ लोगों को जागरूक करने के लिए नियमित अभियान चलाने चाहिए।

बैंकों की लापरवाही से आरोपित ने उनके पास चोरी का सोना रखकर लिया था ऋण, बैंकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए

गोल्ड लोन देने वाले बैंकों को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जब कोई व्यक्ति बड़ी मात्रा में सोना लाकर रखता है, तो बैंकों को उसकी उचित जांच-पड़ताल करनी चाहिए। इसमें लापरवाही के कारण ही चोरी का सोना बैंक में रखकर आरोपित महिला ने ऋण भी ले लिया। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित बैंकों के विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए। इस अपराध में और लोगों के शामिल होने की आशंका है। इसलिए सभी दोषियों को पकड़कर कानून के अनुसार कठोर सजा दिलानी होगी, ताकि ऐसे अपराधों को रोका जा सके।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या एक्जिट पोल के रुझानों पर भरोसा किया जा सकता है?

आज का सवाल
क्या बंगाल में भारी मतदान सत्ता परिवर्तन का संकेत है?

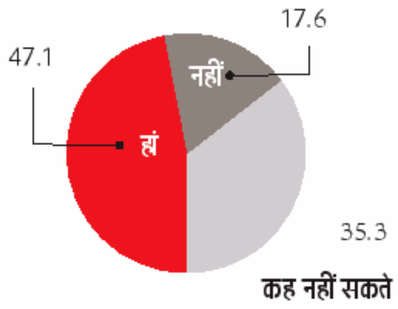

कह नहीं सकते

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। (सभी आकड़े प्रतिशत)

नारी सशक्तीकरण का स्रोत उज्ज्वला

धर्मेंद्र प्रधान

उज्ज्वला योजना इसका भी प्रमाण बनी कि जब नीतियां संवेदनशीलता के साथ बनती हैं, तो करोड़ों जिंदगियां बदल देती हैं

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। यह केवल एक सरकारी योजना की दशक भर की यात्रा ही नहीं, अपितु भारत के विकास संबंधी दृष्टिकोण में आए एक बड़े परिवर्तन का जीवंत प्रमाण है। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि राष्ट्र के विकास की सबसे मजबूत आधारशिला के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एक मई, 2016 को बलिया की क्रांतिकारी धरा से इस योजना की शुरुआत हुई थी। उज्ज्वला योजना ने स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल की। महिला सम्मान, स्वास्थ्य और गरिमा को केंद्र में रखकर विकास के एक नए सोच को भी इसने राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया। सरकार का संकल्प सुस्पष्ट था कि शासन के केंद्र में हाशिए पर मौजूद उस अंतिम महिला को रखें, जो दशकों से रसोई के धुएं में अपना स्वास्थ्य और सपने गंवा रही थी। मोदी सरकार का यह मूल मंत्र रहा है कि स्थायी प्रगति का रास्ता देश की नारी शक्ति के जीवन की सुगमता से होकर ही गुजरता है। ग्रामीण बहनों के जीवन में आई सहजता ही वास्तव में राष्ट्रीय उन्नति का सबसे ठोस आधार है।

महिला-नेतृत्व वाले विकास का जो संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया था, उज्ज्वला योजना की सफल यात्रा उसी संकल्प को साकार करते हुए करोड़ों महिलाओं के सम्मान और बेहतर जीवन का आधार बना है। स्वच्छ रसोई ऊर्जा की दिशा में यह दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। जिस तेजी और व्यापक स्तर पर इसे लागू किया गया, उसकी मिसाल कहीं नहीं। इस योजना ने करोड़ों महिलाओं की पीढ़ियों से चली आ रही कठिन दिनचर्या को बदला और उनके स्वाभिमान की पुनर्स्थापना का माध्यम बनी। यह योजना 'सबका साथ, सबका विश्वास' के मंत्र को व्यावहारिक रूप देने वाली सरकार की प्रारंभिक और सबसे प्रभावशाली जनकल्याणकारी पहलों में एक मानी जाती है, जिसने विकास को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचाने का कार्य किया।

उज्ज्वला से पहले की तस्वीर बहुत चुनौतीपूर्ण थी। अप्रैल 2015 तक भारत में एलपीजी का दायरा 56.2 प्रतिशत परिवारों तक ही सीमित था। यह एक विडंबना थी कि बिजली तो गांवों तक पहुंच रही थी, लेकिन रसोई का ईंधन अब भी सदियों पुराना था। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के अनुसार उस समय 44 प्रतिशत परिवार ही स्वच्छ ईंधन का उपयोग कर पा रहे थे। उज्ज्वला ने इस खाई को पाटने का काम किया। इसके तहत कम आय वाले परिवारों की महिलाओं के नाम पर बिना

भोजन पकाने में सुगमता और स्वास्थ्य लाभ बढ़ाने वाली साबित हुई उज्जवला योजना ● फाइल

किसी सुरक्षा राशि के गैस कनेक्शन दिए गए। अगस्त 2018 में पांच करोड़ कनेक्शन का पहला लक्ष्य हासिल हुआ। इसे 2019 तक बढ़ाकर आठ करोड़ कर दिया गया। उज्ज्वला 2.0 ने उन प्रवासी परिवारों की चिंता भी दूर कर दी, जिनके पास स्थायी पते का प्रमाण नहीं था। 1 मार्च 2026 तक 10.56 करोड़ महिलाएं इस योजना की लाभार्थी बन गईं। इस योजना की सफलता सिर्फ कनेक्शन देने तक ही सीमित नहीं। इसके साथ ही गैस वितरण की व्यवस्था का भी व्यापक विस्तार हुआ। 2014 में देश में कुल 14.52 करोड़ गैस कनेक्शन थे। यह संख्या नवंबर 2024 तक बढ़कर 32.83 करोड़ हो गई। गैस वितरकों की संख्या लगभग दोगुनी हो चुकी है। इनमें से ज्यादातर केंद्र ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में खोले गए। पिछड़े क्षेत्रों में एलपीजी ढांचे को मजबूत करने में तेल विपणन कंपनियों ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। इसमें जन-धन, आधार और मोबाइल की तिकड़ी ने पारदर्शिता के साथ सार्थक भूमिका निभाई। इसके जरिये सब्सिडी का पैसा सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचने लगा। बीच के सभी रिसाव दूर किए गए।

स्वच्छ ईंधन का सबसे गहरा और सकारात्मक असर महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ा। लकड़ी और उपलों के धुएं से होने वाली बीमारियां महिलाओं और बच्चों के लिए हमेशा से एक बड़ा जोखिम रही हैं। उज्ज्वला ने इस संकट को जड़ से मिटाने का काम किया। जहां भी इस योजना का विस्तार हुआ, वहां श्वसन संबंधी बीमारियों में भारी कमी दर्ज की गई। यह एक मूक स्वास्थ्य क्रांति की तरह है, जिसने महिलाओं को 'चूल्हे के धुएं' की गुलामी से आजाद किया। समय की बचत भी इस योजना का एक और क्रांतिकारी पहलू है। ईंधन जुटाने और पारंपरिक चूल्हे पर खाना पकाने में लगने वाले घंटों की बचत ने महिलाओं को एक नया आकाश दिया। अब वे उस बचे हुए समय का उपयोग आर्थिक गतिविधियों में कर पा रही हैं। कई महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ रही हैं या छोटे व्यवसाय शुरू कर रही हैं। जब घर में सुविधा बढ़ती है, तो वह सशक्तीकरण की ओर ले जाती है। महिलाओं के पास समय होने से बेटियों की शिक्षा और उनके भविष्य पर भी बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

अब जब यह योजना अपने दूसरे दशक में प्रवेश कर रही है, तो सरकार का पूरा ध्यान इसके निरंतर उपयोग पर है। यह बहुत सुखद है कि उज्ज्वला लाभार्थियों में गैस की खपत काफी बढ़ी है। साल 2019-20 में यह औसतन तीन सिलिंडर थी, जो 2025-26 में बढ़कर लगभग पांच सिलिंडर तक पहुंच गई। यह बदलाव बताता है कि लोग अब स्वच्छ ऊर्जा को अपनी आदत बना रहे हैं। सरकार भी लक्षित सब्सिडी और छोटे सिलिंडर जैसे विकल्पों के जरिये सुनिश्चित करने में लगी है कि लागत कभी बाधा न बने। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है कि स्वच्छ रसोई का यह सफर स्थायी बने।

प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण में महिला सशक्तीकरण केवल एक नीतिगत नारा नहीं, बल्कि यह एक ऐसी व्यवस्था है, जो जमीनी स्तर पर परिणाम देती है। 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' से लेकर बजट में महिलाओं के लिए बढ़ी हुई हिस्सेदारी तक, हर कदम इसी दिशा में है। इसी क्रम में उज्ज्वला योजना भी इसका प्रमाण बनी कि जब नीतियां संवेदनशीलता के साथ बनती हैं, तो करोड़ों जिंदगियों को बदल देती हैं। धुएं से आजादी और रसोई में सम्मान की बहाली ही विकसित भारत की सच्ची पहचान है। जब घर की रसोई में सुविधा का उजाला होता है, तो पूरा देश आगे बढ़ता है। उज्ज्वला योजना भारत की नारी शक्ति के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

(लेखक केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं)
response@jagran.com

एफटीए का लाभ उठाने की चुनौती

कुमार रोहित

जब तक हमारे युवा कौशल के वैश्विक मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, तब तक एफटीए के लाभ सीमित ही रहेंगे

कौशल की कसौटी पर खरे उतरने की चुनौती ● फाइल

पिछले दिनों भारत ने न्यूजीलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) किया। इसके पहले यूरोपीय संघ (ईयू) से ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौता हुआ था। ये समझौते केवल दो व्यापारिक शक्तियों का मिलन नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी के लिए वैश्विक नागरिक बनने के द्वार का खुलना है। आज यूरोप सहित सभी विकसित देश अपनी वृद्ध होती जनसंख्या के कारण भीषण श्रम संकट से जूझ रहे हैं और भारत अपनी जनसांख्यिकीय शक्ति यानी लाभांश के चरम पर है। अब लखनऊ, पटना या भुवनेश्वर का युवा यह सोच सकता है कि उसका करियर केवल दिल्ली-मुंबई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि बर्लिन और पेरिस तक पहुंचेगा। यह बदलाव केवल भौगोलिक नहीं, बल्कि मानसिकता और आकांक्षाओं का भी विस्तार है। एफटीए की असली ताकत माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप में भी है, जो भारतीय पेशेवरों के लिए यूरोप में सुरक्षित, व्यवस्थित और सम्मानजनक अवसर सुनिश्चित करता है। नई दिल्ली में स्थापित लीगल गेटवे आफिस इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

अब भारतीय प्रतिभा का प्रवास अनौपचारिक नहीं, बल्कि संस्थागत और संरक्षित होगा। यूरोपीय श्रम बाजार में ही वर्तमान में जो रिक्तियां हैं, वे चौंकाने वाली हैं। ईयू में रोजगार दर 76.3 प्रतिशत के उच्च स्तर पर होने के बावजूद वहां प्रतिभा का अकाल है। ईयू देशों में 10 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य पेशेवरों की तत्काल आवश्यकता है। जर्मनी, फ्रांस और आयरलैंड जैसे देशों में भारतीय नर्सों, केयरगिवर्स और फिजियोथेरापिस्ट की भारी मांग है। यूरोपीय संघ की ग्रीन प्लस वन रणनीति के कारण वहां तकनीकी क्रांति तेज हुई है। साफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा साइंस और साइबर सुरक्षा में भारतीय युवाओं के लिए नए अवसर पैदा हो रहे हैं। यूरोप का नेट-जीरो लक्ष्य 2035 तक अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में रोजगार का विस्फोट करेगा। सोलर तकनीशियन, विंड टर्बाइन विशेषज्ञ और इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) इंजीनियरों के लिए वहां का बाजार अभी से पलकें बिछाए खड़ा है। केवल उच्च शिक्षित ही नहीं, बल्कि लाजिस्टिक्स, निर्माण और होटल उद्योग में भी लाखों अवसर हैं। वेयरहाउस आपरेशंस, स्मार्ट इलेक्ट्रिशियन और कृषि प्रसंस्करण में कुशल युवाओं की विशेष मांग देखी जा रही है।

अवसर तो बहुत हैं, पर उनकी राह में देश के युवाओं में कौशल की भारी कमी है। एक हालिया शोध के अनुसार भारत में स्नातक युवाओं में से केवल 8.25 प्रतिशत ही अपनी शिक्षा के अनुरूप काम कर रहे हैं, जबकि 50 प्रतिशत से अधिक युवा अपनी योग्यता से कम स्तर के कार्यों में लगे हैं। हिंदी भाषी राज्यों में केवल अंग्रेजी ही नहीं, बल्कि जर्मन, फ्रेंच और स्पेनिश भाषा की जानकारी का अभाव सबसे बड़ी रुकावट है। हमारे आइटीआइ और विश्वविद्यालयों के कई प्रमाणपत्र यूरोपीय मानकों के साथ मेल नहीं खाते। यह समझना अनिवार्य है कि यूरोप केवल श्रमिक नहीं, बल्कि विशेषज्ञ मांगता है। अब खानापूर्ति वाले प्रशिक्षण का दौर बीत चुका है।

यदि प्रशिक्षण की गुणवत्ता लचर है तो यह केवल युवाओं के समय की बर्बादी नहीं, बल्कि राष्ट्र के साथ छल है। नीतिगत स्तर पर हमें मात्रा के बजाय गुणवत्ता को मूल मंत्र बनाना होगा। प्रशिक्षण संस्थानों को अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षकों, उद्योग-संबद्ध पाठ्यक्रमों और वैश्विक प्रमाणपत्रों को अपनाना होगा। जब तक युवा वैश्विक मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे, तब तक उनके लिए एफटीए के लाभ सीमित ही रहेंगे या फिर कागजों पर ही रहेंगे। युवाओं को अपनी कौशल पहचान बदलनी होगी। बिहार का लैंग्वेज लेबोरेटरी माडल एक शानदार उदाहरण है जहां अरबी, अंग्रेजी, जर्मन और जापानी सिखाई जा रही है। युवाओं को स्नातक साथ ही कम से कम एक यूरोपीय भाषा में दक्षता हासिल करनी चाहिए। यूरोपास सीवी बनाना और ईयू टैलेंट पूल पर अपनी प्रोफाइल को सत्यापित करना सीखना अब ऐच्छिक नहीं, अनिवार्य है। यूरोपीय कार्यसंस्कृति में संवाद, समयबद्धता और सांस्कृतिक संवेदनशीलता तकनीकी ज्ञान जितनी ही महत्वपूर्ण है। स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इसी दिशा में सही कदम है, जो वाराणसी और भुवनेश्वर में चालू हो चुके हैं। डिजिटल स्किल पासपोर्ट जैसी पहल भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगी और युवाओं के करियर को सुरक्षित करने में बहुत सहायक भी बनेगी।

एक समय था जब बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लाखों लोग गिरमिटिया के रूप में मजबूरी में विदेश गए। आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। अब प्रवास मजबूरी नहीं, बल्कि विकल्प और सम्मान का माध्यम बन चुका है। भारतीय युवा अधिकारों और अवसरों के साथ अब वैश्विक प्रतिभा है। यह ब्रेन ड्रेन नहीं, बल्कि ब्रेन सर्कुलेशन का युग है। यूरोपीय संघ और न्यूजीलैंड के साथ भारत का एफटीए केवल व्यापारिक संधि नहीं, बल्कि भारतीय युवाओं के लिए एक नवजागरण है, पर इस सुनहरे भविष्य की चाबी केवल गुणवत्तापूर्ण कौशल में छिपी है। यदि हम अपने युवाओं को श्रेष्ठता के मानक पर तैयार कर सकें तो वह दिन दूर नहीं जब भारतीय हुनर दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन बनेगा। यह समय अपनी कमियों को स्वीकारने और उन्हें वैश्विक दक्षता में बदलने का है।

(लेखक अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त एवं 'सुयोजन' संस्था के संस्थापक हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

सृष्टि और संबंध

मानव का इस धरातल पर अवतरण होते ही वह अदृश्य, अटूट संबंधों की सूक्ष्म कड़ियों में बंध जाता है। जन्म के साथ ही इन संबंधों का बीजारोपण हो जाता है, जो कालांतर में मोह रूपी सघन वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। इसी मोहपाश में आबद्ध होकर व्यक्ति संसार के चक्रव्यूह में फंसकर स्वयं को विस्मृत कर बैठता है। वस्तुतः सत्य यह है कि जहां जीवन का स्पंदन है, वहां संबंधों की उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि समाज और सृष्टि का समूचा ताना-बाना इन्हीं पारस्परिक सूत्रों से निर्मित हुआ है।

प्रत्येक परिवार में संबंधों का एक सहज और नैसर्गिक आकर्षण विद्यमान रहता है, किंतु उनकी सार्थकता व्यक्ति की चेतना की ऊंचाई पर निर्भर करती है। वर्तमान युग की विडंबना यह है कि संबंध प्रायः रक्त-संबंधों की मर्यादा तक सीमित होकर रह गए हैं और दुखद तथ्य यह है कि इन रक्त-संबंधों के आवरण में भी स्वार्थ की गहन छाया छिपी रहती है। संबंधों का विघटन प्रायः कटु वचनों के आघात से होता है, जिसके दुष्प्रभाव से वर्षों से चला आ रहा स्नेह क्षणभर में तार-तार हो जाता है। प्रकृति के साथ हमारा संबंध शाश्वत और अटूट है, जबकि विषय-वासनाओं पर आधारित संबंध क्षणिक और नश्वर हैं। उनमें स्थायित्व और स्थिरता नहीं।

अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव विवेक के प्रकाश में अपने संबंधों का मूल्यांकन करे। संबंधों को सहेजना और उनका पोषण करना आवश्यक है, उन्हें तुच्छ कारणों से विच्छिन्न करना बुद्धिमत्ता नहीं है, तथापि यदि स्वाभिमान और सत्य की रक्षा के लिए संबंध-विच्छेद अपरिहार्य हो जाए तो फिर पीछे मुड़कर देखना आत्मिक दुर्बलता सिद्ध होगी। अंततः सार यही है कि मनुष्य को मोहक प्रतीत होने वाले संबंधों के स्थान पर श्रेयस्कर संबंधों का चयन करना चाहिए। कोई संबंध वही श्रेष्ठ है, जो आत्मिक समुत्कर्ष और लोक-कल्याण के पथ को प्रशस्त करे। साथ ही जीवन में सत्य, प्रेम और करुणा त्रिवेणी सहज ही प्रवाहित हो।

महंत आचार्य नारायण दास

पाठकनामा

pathaknama@nda .jagran.com

बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा भरें

संपादकीय 'छात्रों की आत्महत्याएं' पढ़कर स्पष्ट होता है कि यह समस्या आज अत्यंत गंभीर रूप ले चुकी है। यह सवाल स्वाभाविक है कि आखिर पढ़े-लिखे और जागरूक छात्र भी ऐसा कठोर कदम क्यों उठा रहे हैं। इससे यह भी संकेत मिलता है कि आज शिक्षा का उद्देश्य सर्वांगीण विकास के बजाय केवल अंकों की होड़ और डिग्री प्राप्ति तक सीमित होता जा रहा है। छात्रों की आत्महत्या की घटनाएं अत्यंत दुखद और चिंताजनक हैं। ऐसे हादसों को रोकने के लिए केवल केंद्र या राज्य सरकार ही नहीं, बल्कि शिक्षा संस्थानों, कोचिंग केंद्रों और अभिभावकों-सभी को समान रूप से जिम्मेदारी निभानी होगी। समय के साथ प्रतियोगिताओं का दायरा बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही बच्चों पर पढ़ाई का दबाव भी बढ़ रहा है। यह दबाव धीरे-धीरे उनके बचपन को प्रभावित कर रहा है। कई बार अभिभावक सामाजिक प्रतिष्ठा या अपेक्षाओं के कारण बच्चों पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं, वहीं शिक्षा संस्थान अपनी रैंकिंग को लेकर चिंतित रहते हैं। परिणामस्वरूप बच्चे तनावग्रस्त हो जाते हैं। यह भी सत्य है कि माता-पिता, शिक्षक और कोचिंग संस्थानों का उद्देश्य बच्चों का अहित करना नहीं होता, बल्कि वे उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। किंतु आवश्यक है कि यह प्रयास संतुलित और संवेदनशील तरीके से किया जाए। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों को प्रेमपूर्वक यह समझाएं कि मेहनत, लगन और आत्मविश्वास से हर लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बच्चों में सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और मानसिक संतुलन विकसित किया जाए। यदि हम उन्हें केवल प्रतिस्पर्धा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाएं तो वे हर चुनौती का सामना दृढ़ता से कर पाएंगे।

raju09023693142@gmail.com

सत्यापन की कमी, बढ़ता अपराध

देश के महानगरों में घरेलू सहायकों की जरूरत लगातार बढ़ रही है। नौकरीपेशा परिवार और समय की कमी के कारण लोग घर के कामों के लिए इन पर निर्भर हो चुके हैं। समस्या तब होती है, जब जरूरत के बीच सुरक्षा को नजरअंदाज कर दिया जाता है। कई घरेलू सहायक कई घरों में काम करते हैं। एक घर वाले को लगता है कि दूसरे ने सत्यापन कराया होगा, दूसरे को लगता है तीसरे ने कराया होगा। इसी भ्रम में अक्सर सही सत्यापन नहीं हो पाता। इतनी घटनाओं के बाद भी कई लोग जागरूक नहीं होते और पुलिस सत्यापन कराने से घबराते हैं। वहीं, पुलिस और जनता के बीच संवाद की कमी भी नजर आती है, जिससे सुरक्षा प्रक्रिया कमजोर पड़ती है। महानगरों में घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अत्यधिक विश्वास के कारण लोग घर की निजी बातें और दिनचर्या तक साझा कर देते हैं। ऐसे में यदि कोई गलत मानसिकता वाला व्यक्ति घर में प्रवेश कर जाए, तो खतरा बढ़ जाता है। कुछ गलत लोगों की वजह से ईमानदार घरेलू सहायकों पर भी शक होता है। इसलिए हर घरेलू सहायक का पुलिस सत्यापन और पहचान जांच अनिवार्य होनी चाहिए, ताकि जरूरत भी पूरी हो और सुरक्षा भी बनी रहे।

कमल सिंह भाकुनी, दिल्ली

यातायात नियमों का करें पालन

देश में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, जो न केवल कानून की अनदेखी है बल्कि सीधे तौर पर जीवन के प्रति लापरवाही भी दर्शाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली कुल मौतों में लगभग 28-30 प्रतिशत मौतें दोपहिया वाहन चालकों की होती है। देश की राजधानी में लापरवाही का आलम यह है कि 15 अप्रैल तक बिना हेलमेट पहने वाले चालक के करीब 4.50 लाख चालान काटे गए हैं। आंकड़ों के अनुसार, दोपहिया दुर्घटनाओं में मरने वाले 40-50 प्रतिशत लोग बिना हेलमेट थे। यह स्थिति इसलिए और चिंताजनक हो जाती है, क्योंकि हेलमेट पहनने से सिर की चोट के जोखिम को 60-70 प्रतिशत तक कम किया जा सकता है। युवाओं के द्वारा मोटरसाइकिल पर स्टंट करना व रील बनाना भी किसी खतरे से कम नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा जागरूकता अभियान चलाना, चालान काटना व नियमों को लागू करना आवश्यक कदम हैं। इसके अतिरिक्त सामाजिक अभियान जैसे नो हेलमेट, नो पेट्रोल या परिवार स्तर पर जागरूकता भी प्रभावी हो सकती है। हेलमेट कोई विकल्प नहीं बल्कि जीवन की सुरक्षा का सबसे सरल और प्रभावी साधन है। जब तक व्यक्ति स्वयं अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, तब तक कानून और अभियान सीमित प्रभाव ही डाल पाएंगे। इसलिए देश के युवाओं को इस विषय पर गंभीरता से सोचकर अपने व्यवहार में बदलाव लाना होगा, ताकि सड़कें सुरक्षित बन सकें और अनावश्यक मौतों को रोका जा सके।

वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

पोस्ट

गुजरात के आणंद में भाजपा ने 52 सीटों में से छह पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे और सभी की जमानत जब्त हो गई। अच्छी-खासी संख्या होने के बावजूद मुसलमानों ने भी उन्हें वोट नहीं दिया और फिर वे शिकायत करते हैं कि भाजपा मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती?

अमित कुमार सिंधी@AMIT_GUJJU

बंगाल में दशकों बाद गंभीर हिंसा, आगजनी और गड़बड़ी के बिना चुनाव हुए और मतदान का विश्व रिकार्ड बना। इसके लिए केंद्रीय बलों और चुनाव आयोग की तारीफ करने की जगह जनमत की डकैती बताने वालों के सोच पर अफसोस भी होता है और चिंता भी।

शिव कांत@shivkant

भारतीय क्रिकेट की बेहतरी की खातिर जसप्रीत बुमराह को गेंदबाजों की कब्रगाह बनते जा रहे इस आइपीएल से दूर रखा जाए। अच्छा नहीं लगता कि यह दिग्गज गेंदबाज बस ऐसा तमाशबीन बनकर रह जाए, जो अपनी एक के बाद एक गेंदों को सीमा रेखा के पार जाते हुए बस निरीहता से देखता रहे। रहम करें, उन्हें बख्श दें।

प्रदीप मैगजीन@pradeepmagazine

जनपथ

बिन हिंसा मतदान में मरा न मानुष एक,
सारे सेक्युलर जल उठे यही व्यवस्था देख।
यही व्यवस्था देख चकित होता मतदाता,
और कमल का फूल देखकर बटन दबाता!
ले बापू का नाम घोलकर पियें अहिंसा,
किंतु न चलता काम सेक्युलरों का बिन हिंसा!!

-ओम प्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व. नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा जागरण प्रकाशन लि. के लिए डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा-201309 से मुद्रित एवं 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित संपादक (दिल्ली एनसीआर)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 120- 4615800, E- mail:delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No 50755/90 समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त। वर्ष 36 अंक 286

चिंतन

अब अमेरिका-ईरान में सोशल मीडिया पर जंग

बंगाल चुनाव
प्रमोद भार्गव

अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ा टकराव अब सिर्फ सैन्य या कूटनीतिक मोर्चे तक सीमित नहीं रहा, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी एक नई जंग के रूप में सामने आ चुका है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के बीच सोशल मीडिया पर चल रही बयानबाजी इस बात का संकेत है कि आधुनिक युद्ध का एक बड़ा हथियार अब शब्द, तस्वीरें और डिजिटल संदेश बन चुके हैं। ट्रंप की हालिया पोस्ट जिसमें "तूफान आने वाला है" जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है। इससे पहले भी वे अपने प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपनी एक तस्वीर पोस्ट कर चुके हैं, जिसमें वे एक असॉल्ट राइफल पकड़े हुए हैं और साथ में लिखा है, 'अब और नहीं, मिस्टर नाइस गाय'। यह भाषा दर्शाती है कि वे खुद को आक्रामक और निर्णायक नेता के रूप में पेश करना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वास्तविक ताकत का प्रदर्शन है या कमजोर पड़ती रणनीति को छिपाने का प्रयास? ट्रंप वैसे भी सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए जाने जाते हैं। भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान भी ट्रंप ने कई बार कहा कि इस जंग में कई विमान मार गिराए हैं, लेकिन कभी यह नहीं बताया कि ये लड़ाकू विमान किसके थे। अब करीब सालभर बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि इस युद्ध में पाकिस्तान के 11 फाइटर जेट क्रैश हुए थे। ऐसे दावे न केवल भ्रम फैलाते हैं, बल्कि सुरक्षाबलों के मनोबल को कमजोर करते हैं। ईरान युद्ध में ट्रंप जिस तरह से बैकफुट पर दिख रहे हैं, उससे साफ है कि अब उनके हाथ में बहुत पत्ते नहीं रह गए हैं। अपनी आदत के अनुरूप वह युद्ध में खुद को जीता हुआ दिखाना चाहते हैं, इसलिए सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा। पेजेश्कियान का बयान कि अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी असफल होगी, सीधे-सीधे अंतरराष्ट्रीय कानून और वैश्विक व्यवस्था को चुनौती देने जैसा है। उन्होंने 'नेशनल पर्शियन गल्फ डे' के मौके पर कहा कि इस तरह की नाकाबंदी अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। उन्होंने चेतावनी दी कि जंग के बीच कच्चे तेल की कीमत 126 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं। यह जल्द ही 140 डॉलर प्रति बैरल पहुंच सकता है। ईरान के सर्वोच्च नेता मुर्तजा खामेनेई ने भी अमेरिका को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि फारस की खाड़ी में उनके लिए जगह केवल समुद्र की तलहटी है। वहीं, स्वतंत्र पर्यवेक्षकों का कहना है कि ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी बेसिस को भारी नुकसान पहुंचाया है और उसके सभी हथियारों को नष्ट कर दिया है। इन बेसिस को दोबारा बनाने में अरबों डॉलर खर्च होंगे। अब अमेरिका यहां यूरोप और एशिया से हथियार ला रहा है। दरअसल, अमेरिका ने ईरान को कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। ईरानी नेतृत्व अब ट्रंप के दावों का मजाक उड़ा रहा है और तंज कस रहा है कि होर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी के कारण तेल के दाम बढ़ रहे हैं। होर्मुज बंद होने से पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है। आखिरकार, सवाल यह उठता है कि क्या सोशल मीडिया पर लड़ी जा रही यह जंग किसी वास्तविक समाधान की ओर ले जाएगी, या सिर्फ हालात को और बिगाड़ेगी? आज जरूरत है संयम और जिम्मेदार कूटनीति की, क्योंकि डिजिटल दुनिया में बोले गए शब्द भी कभी-कभी असली गोलियों से ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं।

घुसपैठ से मुक्ति के लिए बदलाव की लहर

पश्चिम बंगाल में मतदाताओं ने जबरदस्त मतदान करके इतिहास रच दिया है। साथ ही अंतिम चरण के मतदान के बाद एग्जिट पोल ने बंगाल और असम में भाजपा की जीत तय कर दी है। बंगाल में तृणमूल को पराजय का सामना करना पड़ता है तो ममता बनर्जी के लिए यह न केवल बड़ा झटका होगा, बल्कि तृणमूल का अस्तित्व वामदलों की तरह रसातल में डूबता दिखाई देगा। असम एवं बंगाल में सबसे बड़ा कोई मुद्दा रहा है तो वह घुसपैठ और इन राज्यों में बढ़ता इस्लामीकरण है। अनेक सीमांत जिलों में घुसपैठ ने दोनों राज्यों में जनसंख्यात्मक घनत्व को बिगाड़ दिया है। कई जिलों में मुस्लिमों की आबादी 90 से 95 फीसदी तक पहुंच गई है। इन बदतर हुए हालातों के प्रति नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने मतदाताओं को जागरूक किया। हिंदू संदेशखाली और आरजीकर में हुए महिला दुष्कर्मों के चलते ध्रुवीकृत हुए। भाजपा ने इन मुद्दों को भुनाने की दृष्टि से आरजीकर अस्पताल में दुष्कर्म व हत्या की शिकार हुई डॉक्टर की मां रत्ना देबनाथ को और संदेशखाली आंदोलन की चेहरा रहीं रेखा पात्र को उम्मीदवार बनाया था। इन महिलाओं की उम्मीदवारी से बंगाल की महिलाओं में संवेदना जगी और बदलाव की लहर बनाने में उनकी प्रमुख भागीदारी रही। इन सब बिंदुओं के उभार ने बंगाल में कुल मतदान को 92.47 प्रतिशत तक पहुंचाकर लोकतंत्र की गरिमा को महिमामंडित करने का काम कर दिया। इसी का परिणाम है कि छह में से पांच एग्जिट पोल बंगाल में भाजपा को स्पष्ट बहुमत दे रहे हैं।

ये पोल असम में दूसरी बार भाजपा को एकतरफा जीत का ऐलान कर रहे हैं। वहीं, तमिलनाडु में द्रमुक की जीत लगभग तय है। केरल में कांग्रेस को हरी झंडी दिखाई है। पुडुचेरी में भाजपा को कांग्रेस से बहुत आगे बता दिया है। अर्थात पांच राज्यों में से तीन में भाजपा का डंका बजने जा रहा है। मतदान के दौरान निर्वाचन आयोग पूरी तरह चौकन्ना रहा। जहां से भी गड़बड़ी की खबर मिली, तुरंत एक्शन लिया। इस कारण लंबे समय तक अराजक तत्वों द्वारा मतदान रोकना संभव नहीं हो पाया। किसी भी झड़प को बड़े संघर्ष का रूप लेने से पहले ही केंद्रीय बलों के जवान उसे नियंत्रित करने में सफल दिखे। पहली बार अमल में लाई गई त्वरित प्रतिक्रिया दल ने भी अपने दायित्व का पूर्ण रूप से दायित्व का पालन किया। बावजूद सच्चाई का पता चार मई को आने वाले परिणामों से ही चलेगा। बंगाल के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि न तो बमों के धमाके हुए और न ही बंदूकों से गोलियां गरजीं। अतएव न रक्त बहा और न ही कोई मौत हुई। छिटपुट घटनाओं को छोड़ दें तो स्वतंत्र मतदान शांतिपूर्ण रहा। ऐसा 2.40 लाख सैन्य बलों की तैनाती के चलते संभव हुआ, इसीलिए बंगाल में पहली बार लगा कि सही मायनों में लोकतंत्र के इस पर्व में सभी समुदाय के लोग सद्भाव के साथ शामिल हुए है। बावजूद बौद्धिक पाखंडी बढ़े मतदान को ममता की वापसी बता रहे हैं। इस बार बंगाल में पिछली बार की तुलना में करीब 9 प्रतिशत अधिक वोट पड़े। ये वोट भाजपा के पक्ष में जाते दिख रहे हैं।

निर्वाचन आयोग ने एसआईआर के जरिए भी घुसपैठ करके अवैध मतदाता बने करीब 92 लाख मतदाताओं को मत से वंचित कर दिया है। इनमें से बढ़ा प्रतिशत

तृणमूल के समर्थकों का रहा है, क्योंकि ये लोग जानते थे कि भाजपा आई तो बंगाल से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए मुस्तैद हो जाएगी। भाजपा चूंकि वामदलों की तरह अनुशासन कार्यकर्ताओं का राजनीतिक दल है। संघ के जमीनी स्वयंसेवकों का भी उसे सहयोग मिलता है। ये लोग अपने दल का अस्तित्व बनाए रखने की चिंता के चलते पार्टी के हितों की रक्षा करने को तत्पर रहते हैं। ओपिनियन पोल, मसलन जनमत सर्वेक्षण जहां मतदान पूर्व मतदाता की मंशा टटोलने की कोशिश है, वहीं एग्जिट पोल अर्थात सटीक सर्वेक्षण, मतदान पश्चात, मतदाता का निर्णय जानने का प्रयास है। एग्जिट पोल मतदान के चलते कराए जाते हैं, इसलिए ये वास्तविक परिणाम के पूर्व अनुमान माने जाते हैं। अतएव कोई राजनीतिक दल इन्हें अपनी इच्छानुसार कराने में रुचि नहीं लेता। मतदान के बड़े प्रतिशत को अब तक सत्तारूढ़ दल के खिलाफ व्यक्तिगत असंतुष्ट और व्यापक असंतोष के रूप में देखा जाता था, लेकिन मतदाता में आई बड़ी जागरूकता ने परिदृश्य को बदला है, इसलिए इसे केवल नकारात्मकता की तराजू पर तोलना बड़ी भूल होगी? सकारात्मक दृष्टि से देखने की भी जरूरत है। मध्यप्रदेश विधानसभा-2023 के चुनाव में लाडली बहना योजना के चलते महिलाओं ने बढ़-चढ़कर मतदान किया था, जो भाजपा के पक्ष में स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसलिए मध्यप्रदेश में भाजपा चुनाव जीत पाई थी। पारंपरिक नजरिए से मतदान में बड़ी रुचि को सामान्यतः एंटी इनकमबेंसी का संकेत, मसलन मौजूदा सरकार के विपरीत चली लहर माना जाता है। इसे प्रमाणित करने के लिए 1971, 1977 और 1980 के आम चुनाव में हुए ज्यादा मतदान के उदाहरण दिए जाते हैं, लेकिन यह धारणा पिछले कुछ चुनावों में बदली है। 2023, 2013, 2008 और 2003 में बड़े मतदान का लाभ सत्तारूढ़ होते हुए भी मध्यप्रदेश में भाजपा को मिलता रहा है। 2010 के चुनाव में बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़कर 52 हो गया था, लेकिन नीतीश कुमार की ही वापसी हुई, जबकि बंगाल में 2011 में ऐतिहासिक मतदान 84 फीसदी हुआ और मतदाताओं ने 34 साल पुरानी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार को परास्त कर ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को जीत दिलाई थी। गोया, चुनाव विश्लेषकों और राजनीतिक दलों को अब किसी मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है। मतदाता पारंपरिक जड़ता और प्रचलित समीकरण तोड़ने पर आमदा हैं। बड़े मत प्रतिशत का सबसे अहम, सुखद व सकारात्मक पहलू है कि यह अनिवार्य मतदान की जरूरत की पूर्ति कर देता है।

हालांकि हमारे देश में अनिवार्य मतदान की संवैधानिक बाध्यता नहीं है। निकट भविष्य में इस उम्मीद की पूरी होने की संभावना भी नहीं है। एसआईआर के जरिए देश से घुसपैठिए बाहर कर दिए जाते हैं तो इस अवैध घुसपैठ से लाभ उठाने वाले नेताओं की भूमिका को भी जनता नकार देगी। बढ़ा मतदान प्रतिशत ही ऐसा प्रमुख कारण है, जिसके चलते एग्जिट पोल एकतरफा नहीं रह गए हैं, क्योंकि इसके सर्वे के नमूने का प्रतिशत बहुत कम होता है। गोया, इस आधार पर बड़े मतदाता समूह की मंशा की पड़ताल करना और व्यावहारिक नतीजे पर पहुंचना बहुत कठिन काम है। वैसे भी अब कई सर्वे एजेंसियां क्षेत्रीय पत्रकारों से फोन पर बात करके नतीजों का अनुमान लगाने का तरीका अपना रही हैं। दरअसल क्षेत्रीय पत्रकार किसी न किसी दल या प्रत्याशी से प्रभावित रहते हैं और उसी प्रभाव के चलते वे अपनी राय व्यक्त कर देते हैं, जिसे तटस्थ नहीं कहा जा सकता है। इस बार के एग्जिट पोल अनुमान के निकट इसलिए खरे उतरेंगे, क्योंकि मतदाताओं का दलगत विभाजन पांचों राज्यों में स्पष्ट दिखाई दिया है।

(लेखक वरिष्ठ स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

जन्मदिवस विशेष
शरद मिश्रा

सर्वप्रिय सबके प्यारे मोहन भैय्या

रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि समूचे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता-जनार्दन के लिए संकल्प, समर्पण और समाधान की एक सटीक मिसाल हो सकते हैं। पिछले करीब 40 सालों से जनता में दुःख दर्द में हमेशा काम आने वाले एक सर्वप्रिय नेता की छवि कायम रखते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने देश के अन्य नेताओं को अपने संकल्प, समर्पण से जनहित पर समाधान की जो राह दिखाई है वो अद्भुत, अविश्वसनीय और अविस्मरणीय है। बृजमोहन अग्रवाल यानी सब के प्यारे मोहन भैय्या लोकतंत्र का संकल्प, समर्पण और सम्पूर्ण समाधान हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगातार 8 बार के विधायक, (1989 से 2023) तक साथ ही हर बार पिछले बार से ज्यादा वोट मार्जिन से जीतना कोई आसान काम नहीं है। 1989 में ही अपने पहले निर्वाचन में अविभाजित मध्यप्रदेश की तत्कालीन सुंदर लाल पटवा की भाजपा सरकार में स्थानीय शासन मंत्री बने बृजमोहन अग्रवाल को अविभाजित मध्यप्रदेश में ही सर्वश्रेष्ठ विधायक का सम्मान भी हासिल हुआ। देश में ऐसे कुछ नेता,जनप्रतिनिधि अवश्य हैं, जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से पिछले 20, 30 सालों से लगातार जीतते आ रहे हों लेकिन उनके और रायपुर के बृजमोहन अग्रवाल के चमत्कारिक राजनैतिक उत्कर्ष- वैभव की बात करें तो हमें मिलेगा कि बिना किसी जोर दबाव, दबंगई के जनता के मन मस्तिष्क यानी जेहन में जो स्थान बृजमोहन अग्रवाल ने बनाया है वो देश के अन्य नेताओं के लिए अनुकरणीय हो सकता है। सबके प्रति प्रेम, सहयोग, दोस्ती, मित्रता का भाव बृजमोहन अग्रवाल के व्यक्तित्व की सबसे अहम खासियत है, उसमें समय के साथ लगातार और निखार भी आता जा रहा है। बृजमोहन अग्रवाल 65 पार हो चुके हैं लेकिन ऊर्जा और सक्रियता पर अभी भी 40 के बांके जवान को मीलों पीछे छोड़ देंगे। उनमें अभी भी 15 साल की राजनैतिक मेहनत और सक्रियता पूरी तन्मयता से बाकी है। आधी रात में भी जनता को मदद करने में हमेशा से आगे रहने वाले आपके, हमारे ही नहीं बल्कि सबके मोहन भैय्या यानी बृजमोहन अग्रवाल रायपुर से 2024 की लोकसभा में सांसद बनने के बाद छत्तीसगढ़ पर संसद में लगातार सवाल उठाकर विकसित छत्तीसगढ़ पर केंद्र की मोदी सरकार के लिए और पुख्ता आधार तैयार करने में प्रबल सहयोग कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ पर महीन से महीन बारीक जानकारी रखते हुए उसे राज्य के विकास के लिये बेहतर से बेहतर ढंग से क्रियान्वित करना कोई मोहन भैय्या से सीखे। पत्रकारिता जगत में पत्रकारों के बीच मित्रवत व्यवहार मोहन भैय्या के अंदर पत्रकारिता कौशल का कुशल परिचायक है। खबरों को विषय वस्तु के साथ सटीक ढंग से संपादित करना शायद बृजमोहन अग्रवाल जी से आज के पत्रकारों को सीखना चाहिए। बृजमोहन अग्रवाल जी की पत्रकारों से दोस्ती भी पूरे देश में चर्चित है। संसद सत्र के दौरान पत्रकारों की बृजमोहन अग्रवाल के नाम पर उत्सुकता इसका प्रमाण है,और मैं इसका प्रत्यक्ष साक्षी रहा हूं। चेन्नै, हैदराबाद से दिल्ली होते हुए बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद, भोपाल, रायपुर के पत्रकारों में बृजमोहन जी को लेकर एक विशेष लगाव और प्यार देखने को मिलता है।

अविभाजित मध्यप्रदेश में 80 के मध्य दशक में रायपुर शहर की एमजी रोड में कॉंग्रेस के तत्कालीन कद्दावर मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह को काले झंडे दिखाकर मनमानी सत्ता के खिलाफ़ अपने अंदर के गुस्से को ज़ाहिर करते हुए जन-मानस में अपने अंदर के नेता को प्रतिष्ठित करने वाले मोहन भैय्या ने 2000 में मध्यप्रदेश की दिग्विजय सिंह सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ के हीरा खदानों को विदेशी कंपनी डिबियर्स को देने का पुरजोर विरोध किया और नतीजन कंपनी के अफसरों को रायपुर एयरपोर्ट से ही वापस लौटना पड़ा। बृजमोहन अग्रवाल को कृषि विभाग का नेतृत्व मिलते ही वर्ष 2014, 2015 एवं 2016 में निरंतर तीन वर्षों तक छत्तीसगढ़ को कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ। इस वर्ष ही बृजमोहन अग्रवाल को व्यक्तिगत तौर पर एग्रीकल्चर लीडरशीप अवार्ड से नवाजा गया। बृजमोहन अग्रवाल के अब तक के अन्य कार्यों में रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण, 65,000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला भारत में दूसरा और विश्व का चौथा सबसे बड़ा खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियम का रायपुर में निर्माण हुआ। इसके साथ पर्यटन के क्षेत्र में राज्य के विभिन्न पर्यटन क्षेत्रों का विकास एवं विभिन्न मोटलों का निर्माण, राज्य के विभिन्न पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों में होने वाले बड़े-बड़े मेलों को महोत्सव का स्वरूप दिलाने के साथ-साथ राज्य के त्रिवेणी संगम राजिम में विशाल कुम्भ मेले की शुरूआत करना प्रमुख रूप से शामिल हैं।

युवा पीढ़ी में सार्थक व रचनात्मक राजनीति के प्रति रूझान पैदा करते हुए उनकी अध्ययनशीलता को प्रोत्साहन देने में मोहन भैया की रूचि जग जाहिर है। देर रात तक देश दुनिया और राज्य में जारी राजनैतिक और सामाजिक गतिविधियों का अध्ययन करना बृजमोहन अग्रवाल का दैनिक शगल है। विभिन्न सामाजिक संगठनों में सक्रिय भागीदारी करते हुए राजनीतिक चेतना का विकास करना बृजमोहन अग्रवाल की बौद्धिक विशेषता है। ऐसी लगातार सक्रियता और प्रभावशाली कार्य प्रणाली ही बृजमोहन अग्रवाल यानी मोहन भैया को पूरे प्रदेश का सबसे लोकप्रिय जननेता बनाती है।

रायपुर की हर धड़कन के साथ हर पल खड़े रहे उसके अपने बृजमोहन भैया रायपुर के आत्मविश्वास और साहस भी हैं। रायपुर की हँसी, रुदन और नील नील अंबर में दूर दूर तक फैली खुशहाली भी हैं। रायपुर के सरकारी दफ्तरों की फाइल में लोककल्याण की महकती सोंधी सोंधी खुशबू हैं। चाह और फर्ज के बीच रायपुर सहित समूचे छत्तीसगढ़ में फैला मोहन भैया का नूर सांसद बनने के बाद अब समूचे देश में भी जगमगाए। असीम शुभकामनाओं के साथ।

संकलित
दर्शन

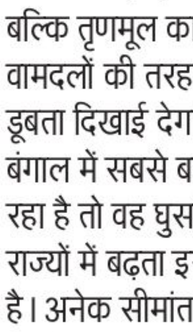

समत्वं योग उच्यते

जिस मनुष्य का जीवन योगयुक्त है, उसे जीवन चलाने के कर्म बंधन में बांधने वाले नहीं होते। जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी कमल ही रहता है। युक्त और अयुक्त का अर्थ योगयुक्त और योगअयुक्त से है अर्थात योग है समत्व बुद्धि। 'समत्वं योग उच्यते'। समत्व बुद्धि से तात्पर्य सोच-विचार कर किए गए कर्म को योगयुक्त कर्म कहते हैं। समत्व बुद्धि से अर्थ सुख-दुख, विजय-पराजय, हर्ष-शोक, मान-अपमान इत्यादि द्वंद्वों में विचलित हुए बिना एक समान शांत चित्त रहे- वही कर्मयोगी कहलाता है। स्थितप्रज्ञ : जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को त्याग देता है, उस काल में आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ, जैसे जहाज को चलाने वाले के पास ठीक दिशा बताने वाला कम्पास या यंत्र होना चाहिए, उसी तरह श्रेष्ठ जीवन जीने के तथा मोक्ष के अभिलाषी व्यक्ति के पास 'योग' होना चाहिए। योग नहीं तो जीवन दिशाहीन है। यही बात कृष्ण ने गीता में स्थितप्रज्ञ के विषय में कही है। बुद्धि को निर्मल और तीव्र करने के लिए योग ही एक मात्र साधन है। योग स्थित व्यक्ति साधारण मनुष्यों से विलक्षण देखने लगता है। जिस व्यक्ति के भीतर जीवन में सत्य की किरणें फैल जाती हैं, सत्य का सूर्य जगता है और जिसकी आंतरिक चेतना जागृति को, पूर्ण जागृति को उपलब्ध हो जाती है, उसका जीवन स्पांटेनियस हो जाता है, सहज हो जाता है, सहज-स्फूर्त हो जाता है। उसके जीवन में किसी ढांचे को खोजना मुश्किल है। उसके जीवन में कोई बंधी-बंधाई रेखाएं नहीं होतीं।

संकलित
प्रेरणा

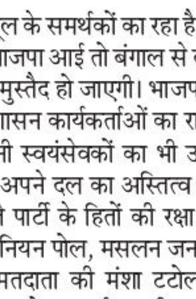

तुलसीदास जी द्वारा श्रीराम के दर्शन का उपाय

एक ब्राह्मण दिनभर गोस्वामी जी के कुटिया के बाहर बैठकर लोभवश राम-राम रटता। संध्या के समय श्रीहनुमान जी उसे धन दे देते थे। एक वार उसने भगवान के दर्शन के लिए बड़ा हठ किया। गोस्वामी जी ने कहाः उसके लिए प्रेम और भाव चाहिए, संत की कृपा चाहिए। ऐसे ही एकदम भगवान नहीं मिलते। उसने कहाः आप समर्थ महापुरुष है, आप भगवान के दर्शन करवा सकते है। वह हठ पर अड़ गया। गोस्वामी जी ने कहाः ठीक है यहाँ सामने इस पेड़ पर चढ़ जाओ, पेड़ के नीचे त्रिशूल गाढ़ दो और उस त्रिशूल पर कूद पडो। भगवान के दर्शन हो जायेंगे। वह त्रिशूल गाडकर वृक्षपर चढ़ा, परंतु कूदने की हिम्मत नहीं हुई। एक घुडसवार उधर से जा रहा था, उसने पूछाः पेड़ पर क्या कर रहे हो? ब्राह्मण बोलाः तुलसीदास जी ने कहा है पेड़ पर से त्रिशूल पर कूदो तुम्हे भगवान श्रीराम के दर्शन होंगे। उस व्यक्ति ने कहाः क्या सच में यह बात तुलसीदास जी के श्रीमुख से निकली है? ब्राह्मण बोलाः जी हाँ ! वह व्यक्ति तुरंत पेड़ पर चढ़कर त्रिशूलपर कूद पडा। उसे भगवान ने आकर हाथ से पकड़ लिया और उसे श्रीराम के दर्शन प्राप्त हो गये। हनुमान जी ने उसे तत्त्वज्ञान का उपदेश भी दिया। गोस्वामी जी ने सत्य ही कहा था, जिनमें प्रेम-भाव हो एवं संत की कृपा हो वही भगवान के दर्शन पाता है।

मई दिवस

बिहार के पटना में गुरुवार को लेबर डे, जिसे मई दिवस भी कहा जाता है, की एक शाम पहले एक ईंट फैक्ट्री में मजदूर ईंटें ढोते हुए।

आज की पाती

विरोधाभासों से परिपूर्ण है ट्रंप की बयानबाजी

अमरीकी राजनीति में बयानबाजी हमेशा से तीखी रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के दौर में यह प्रवृत्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई है। ट्रंप की सोशल मीडिया गतिविधियां अक्सर अचानक, विरोधाभासी और वैश्विक असर डालने वाली होती हैं। एक दिन वे किसी देश की प्रशंसा करते हैं, तो अगले ही दिन उसी देश की आलोचना कर देते हैं। यह केवल भारत ही नहीं, बल्कि ग्रीनलैंड, ईरान और यहां तक कि यूरोपीय सहयोगियों के संदर्भ में भी देखा गया है। हाल के वर्षों में ट्रंप के बयानों और नीतियों में यह अस्थिरता और स्पष्ट दिखी है। उदाहरण के लिए, उन्होंने पहले भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की बात कही, वहीं दूसरी ओर कुछ पोस्ट्स और बयानों में भारत की नकारात्मक छवि को बढ़ावा देने वाले विचारों का समर्थन भी किया। इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए।

– सुभाष तिवारी, सरायपाली

ट्रेंड

स्नातक होने पर बधाई

पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ उत्तर भारत का प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान है, जो चिकित्सा देखभाल, शिक्षा और अनुसंधान में उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है और अपने स्नातकों के लिए गर्व का स्रोत है। आप सभी को स्नातक होने पर हार्दिक बधाई।

- जेपी नड्डा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री

मुफ्त एलपीजी कनेक्शन

समाजवादी पार्टी के जमाने में लोग केरोसिन की कालाबाजारी करते थे, और कांग्रेस के शासनकाल में तो एलपीजी सिलेंडर बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं थे। आज देश में 10 करोड़ महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

- योगी आदित्यनाथ, सीएम, उप्र

महिला आरक्षण का समर्थन

लंबे संघर्षों के बावजूद राजनीति में महिलाओं की उचित भागीदारी सुनिश्चित करने की पहल के तहत संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का मुद्दा आगे नहीं बढ़ पाया है, जो बेहद खेदजनक, दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है; बीएसपी महिला आरक्षण का समर्थन करती है।

- मायावती, पूर्व सीएम, उप्र

सरकार की साख गिरी

श्री गंगानगर से भाजपा विधायक जयदीप बिहानी पर आरयूआईडीपी अधिकारियों द्वारा किया गया हमला राज्य में बढ़ती अराजकता का प्रतीक है। सरकार को ऐसी घटनाओं को गंभीरता से लेना चाहिए; जनता के बीच सरकार की साख तेजी से गिर रही है।

- अशोक गहलोत, पूर्व सीएम, राजस्थान

करंट अफेयर

अमेरिका ने भारत को 1.4 करोड़ डॉलर की प्राचीन वस्तुएं लौटाई

अमेरिका ने भारत को करीब 1.4 करोड़ अमेरिकी डॉलर मूल्य की 657 प्राचीन वस्तुएं लौटायी हैं और कहा है कि इस एशियाई देश को चुराई गई कलाकृतियां वापस दिलाने के लिए 'अभी और काम किया जाना बाकी है।' प्राचीन वस्तुएं लौटाने की घोषणा मंगलवार को मैनहट्टन के जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने की। लौटाई गई वस्तुओं में 'अवलोकितेश्वर' की लगभग 20 लाख डॉलर मूल्य की कांस्य प्रतिमा भी शामिल है, जो शेरों से सजे सिंहासन पर द्वि-कमल आसन पर विराजमान है। इस पर अंकित शिलालेख में कारीगर का नाम द्रोणादित्य बताया गया है, जो छत्तीसगढ़ के वर्तमान रायपुर के पास स्थित सीपुर का निवासी था।

यह अवलोकितेश्वर प्रतिमा 1939 में लक्ष्मण मंदिर के पास मिली कांस्य प्रतिमाओं के एक बड़े भंडार का हिस्सा थी और 1952 तक रायपुर के महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय के संग्रह में शामिल हो गई थी। इस प्रतिमा को संग्रहालय से चुरा लिया गया और 1982 तक अमेरिका तस्करी कर ले जाया गया। अंततः 2014 तक यह न्यूयॉर्क के एक निजी संग्रह में पहुंच गई। 2025 में मैनहट्टन जिला अटॉर्नी कार्यालय ने इस कांस्य कलाकृति को उस संग्रह से खोजकर जब्त कर लिया।

ऑफ बीट

आपकी विशिष्ट गंध बता सकती है क्या बीमारी है

हमारे शरीर से हर सेकंड सैकड़ों रसायन हवा में प्रवाहित होते हैं। ये रसायन हवा में आसानी में घुल जाते हैं क्योंकि इनमें वाष्प का दबाव अधिक होता है, जिसका अर्थ है कि वे उबल जाते हैं और कमरे के तापमान पर गैस में बदल जाते हैं। वे इस बात का पता देते हैं कि हम कौन हैं और कितने स्वस्थ हैं। प्राचीन यूनानी काल से, हम जानते हैं कि जब हम अस्वस्थ होते हैं तो हमारी गंध अलग-अलग होती है। जबकि आज हम रक्त विश्लेषण पर भरोसा करते हैं, प्राचीन यूनानी चिकित्सक बीमारियों के निदान के लिए गंध का उपयोग करते थे। आपकी सांस का एक झोंका लेकर वह बता सकते थे कि आपको फेटोर हेपेटिकस (मतलब खराब लीवर) है, तो इसका मतलब होता था कि आप लीवर की बीमारी की ओर बढ़ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की सांस की हवा में मीठापन या फलों की गंध होती थी, तो चिकित्सकों का निष्कर्ष होता था कि पाचन तंत्र में शर्करा टूट नहीं रही है, और उस व्यक्ति को संभवतः मधुमेह है। विज्ञान ने तब से दिखाया है कि प्राचीन यूनानी सही थे – जिगर की विफलता और मधुमेह तथा संक्रामक रोगों सहित कई अन्य बीमारियों आपकी सांसों को एक विशिष्ट गंध देती हैं। 1971 में, नोबेल पुरस्कार विजेता रसायनज्ञ लिनुस पॉलिंग ने सांस में 250 विभिन्न गैसीय रसायनों की गिनती की।

अपने विचार

हरिभूमि कार्यालय

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से hbcgpati@gmail.com पर भेज सकते हैं।

प्रेरणा

खुश रहना है तो कभी पेड़ों, हवा और आसमान से भी दोस्ती कर लीजिए। -गुलजार

संपादकीय

एआई पर वैश्विक कानूनी फ्रेमवर्क बनाना जरूरी है

एंथ्रोपिक ने अपने क्लॉड-परिवार में माइथोस- साइबर सिक्योरिटी मॉडल की बात स्वीकारी है। दरअसल यह वर्जन औपचारिक रूप से रिलीज नहीं हुआ लेकिन लीक हो गया। इसके खतरों के बारे में यूके के एआई सिक्योरिटी इंस्टिट्यूट ने दुनिया को सतर्क करते हुए बताया था कि यह किसी भी आईटी सिस्टम में घुसकर और उसकी कमजोरियों को पहचानकर उस पर कई बार हमले कर सकता है, उसे बदल सकता है और अपनी मर्जी से आदेश दे सकता है। भारत दुनिया के सबसे बड़े एआई मॉडल यूजर्स में से एक होने के कारण एआई को वैश्विक रेगुलेशन के दायरे में लाने की मांग करता है और उसमें अपनी भूमिका चाहता है। इसी बीच चीन ने भी ठीक माइथोस की तरह का अपना नया साइबर सिक्योरिटी मॉडल- क्विहो-360 विकसित कर लिया है। चीन अपने शोध के बारे में दुनिया को बेहद कम जानकारी देता है, लिहाजा किसी भी वैश्विक प्रोटोकॉल को लागू करना मुश्किल हो जाता है। चीन के वुहान इंस्टिट्यूट से बगैर बायो-सेफ्टी लेवल-4 की सुरक्षा सुनिश्चित किए जीन-परिवर्तित वायरस लीक होने की खबरें आई थीं। नतीजतन, कोरोना जैसी बड़ी तबाही देखी गई। एआई पर भी तत्काल अंतरराष्ट्रीय संगठन के तहत दिशानिर्देश बनाना जरूरी हैं। कारण, माइथोस में आईटी सिस्टम पर लगातार हमले करने और सिस्टम को ही बदलने वाले लक्षण पाए गए हैं।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

अवकाश अवश्य मनाएं पर इन चार बातों का ध्यान रखें

बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां लग चुकी हैं या लग रही हैं। अधिकांश पैरेंट्स बच्चों को लेकर यात्रा पर निकलने की तैयारी में हैं। ऋषि-मुनि भी अवकाश अर्जित करते थे। छुट्टियां मनाने का उनका अपना ढंग था, क्योंकि गुरुकुल व्यवस्था थी। जब आप अवकाश का मन बनाएं तो सबसे पहले समय-सीमा तय करें। सहयोगी कौन रहेंगे? क्षेत्र बदले तो सावधानी रखिए। पुराना स्थान छोड़ा है तो वहां से संपर्क कितने समय रखना है, इसमें सचेत रहें। और सबसे बड़ी बात, सकुशल लौटें। अवकाश का सदुपयोग कैसे हो, इस पर रामचरितमानस में एक पंक्ति आई है। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण वन के समय एकांत में अवकाश ही मना रहे थे। तो पंक्ति है- एहि बिधि गए कछुक दिन बीती, कहत बिराग ज्ञान गुन नीति। कुछ दिन ऐसे बीते कि उन्होंने एक-दूसरे से वैराग्य, ज्ञान, गुण और नीति पर चर्चा की। अवकाश मनाएं, पर ये चार बातें इस दौरान होती रहें तो मानसिक स्वास्थ्य के साथ जाएंगे, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मनाएंगे और दोनों के साथ ही लौटेंगे। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

विश्लेषण • 'आप' में टूट से समीकरणों में आया परिवर्तन

पंजाब को लेकर भाजपा की रणनीति अब बदल रही है

सियासत

नीरजा चौधरी
वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार
neerja_chowdhury@yah oo.com

आम आदमी पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों के भाजपा में चले जाने से पंजाब का मोर्चा हालिया विधानसभा चुनावों का शोर थमने से पहले ही खुल गया है। ध्यान रहे कि 'आप' राज्यसभा में चौथी सबसे बड़ी पार्टी थी। एक दशक पहले ही बनी एक नई पार्टी के लिए यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं। इसकी तुलना में शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पास भी राज्यसभा में एक-एक ही सांसद हैं। लेकिन सात सांसद निकलने के बाद अब राज्यसभा में 'आप' के तीन ही सदस्य बचे हैं। 'आप' इस पाला-बदल को अदालत में चुनौती देने की योजना बना रही है।

जब तक अदालत इन सात सांसदों के फैसले पर तत्काल रोक नहीं लगाती, वे भाजपा के सदस्य बने रहेंगे। अदालत के अंतिम फैसले तक तो यही स्थिति रहने वाली है। संभवतः तब तक उनका राज्यसभा का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका होगा। अनुभव बताते हैं कि दल-बदल के मामले अदालतों में वर्षों चलते रहते हैं। भले ही इससे दल-बदल कानून की समीक्षा की जरूरत महसूस होने लगी हो, लेकिन फिलहाल तो इस घटनाक्रम का असर 'आप' के भविष्य, पंजाब में उसकी सरकार, केजरीवाल के नेतृत्व और पंजाब में भाजपा व कांग्रेस की स्थिति पर भी पड़ेगा।

देखें तो राज्यसभा में भाजपा के खाते में सात सांसदों की बढ़ोतरी उसे खासी राहत देगी, लेकिन इसके बावजूद उसके पास सदन में अब भी बहुमत से 10 सीटें कम हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पिछले साल मिली हार के बाद कमजोर दिख रही 'आप' को इस घटनाक्रम ने बड़ा झटका दिया है। इतने सांसदों के पाला बदलने से कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित होगा और केजरीवाल की पार्टी को एकजुट रखने की क्षमता पर सवाल उठेंगे। पंजाब में भी पार्टी के हौसले पर असर पड़ेगा, जहां अगले साल चुनाव होने वाले हैं।

पंजाब में 'आप' के पास 117 में से 94 सीटों का मजबूत बहुमत है। पार्टी नेतृत्व अब इस बात को लेकर चिंतित है कि विधायकों को खरीद-फरोख्त से कैसे बचाया जाए। 'आप' विधायक सतर्क हैं और जानकारों की मानें तो वे एक-दूसरे पर नजर भी रख रहे हैं कि कौन-कौन राघव चड्ढा और भाजपा में गए नेताओं के संपर्क में हैं। पाला बदलने वाले चड्ढा और केजरीवाल के प्रमुख रणनीतिकार संदीप पाठक की अहमियत इसलिए नहीं है कि वे भाजपा के लिए जमीनी समर्थन जुटा लेंगे, क्योंकि वे जन-नेता तो हैं ही नहीं। हां, छात्रों और फर्स्ट टाइम वोटरों में चड्ढा का थोड़ा आकर्षण जरूर है।

चड्ढा ने 2022 में पंजाब चुनाव की जिम्मेदारी संभाली थी और पाठक केजरीवाल के बेहद भरोसेमंद थे। यहां तक कि टिकट वितरण समेत अन्य सभी महत्वपूर्ण कामकाज तक भी वे देखते थे। इसलिए ये दोनों ही पंजाब में 'आप' के विधायकों को अच्छे से जानते हैं। बताया जाता है कि पार्टी छोड़ने के बाद उन्होंने कई विधायकों से संपर्क किया भी है।

तो क्या वे पंजाब में 'आप' विधायकों में बगावत करवा सकते हैं? खासकर, जिन विधायकों को मंत्री या कोई अन्य पद नहीं मिला और जो असंतुष्ट हैं, उनमें? क्या इससे सरकार गिर सकती है और चुनाव से पहले राष्ट्रपति शासन लग सकता है? फिलहाल इस पर कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि क्या इन बदली परिस्थितियों में पंजाब की 'आप' में कोई 'एकनाथ शिंदे' हो सकता है, जो सियासी समीकरणों को बदल दे और भाजपा को इसका फायदा हो? खैर, ये सब तो अभी अटकलें ही हैं,

कुछ समय पहले तक भाजपा मान रही थी कि पंजाब में भगवंत मान ही सत्ता में बने रहें तो बेहतर। वह नहीं चाहती थी कि इस राज्य में कांग्रेस की वापसी हो। लेकिन अब पंजाब को लेकर भाजपा की रणनीति में बदलाव आ रहा है।

लेकिन पंजाब में भाजपा के गेम प्लान को लेकर चर्चाएं जरूर अभी से शुरू हो चुकी हैं।

भाजपा अब पारंपरिक जातीय समीकरणों पर निर्भर रहने के बजाय जनता के बीच मुद्दों को लेकर अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर सकती है। 2020-21 के किसान आंदोलन के बाद उसने पंजाब में जमीन खो दी थी। उसका सबसे पुराना सहयोगी शिरोमणि अकाली दल उससे अलग हो गया। हालांकि, दोनों में बातचीत चलती रही है, लेकिन नतीजा नहीं निकल पाया।

कुछ ही समय पहले तक भाजपा मान रही थी कि चूंकि 2027 के चुनाव तक वह पंजाब में मजबूत होने की स्थिति में नहीं है तो बेहतर होगा भगवंत मान ही सत्ता में बने रहें। क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि इस सीमावर्ती राज्य में कांग्रेस की वापसी हो। हालांकि 'ऑपरेशन-7' को अब पंजाब को लेकर भाजपा की रणनीति में बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। पार्टी की सोच बदल रही है। यह सिर्फ राज्यसभा में 'आप' को तोड़ने का ही नहीं, बल्कि 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भाजपा को मजबूत दावेदार के तौर पर खड़ा करने की शुरुआत भी हो सकती है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

दूरदृष्टि • वोट-शेयर में मामूली बदलाव भी निर्णायक

सीटों के बजाय वोट-शेयर का पूर्वानुमान ज्यादा महत्वपूर्ण है

एग्जिट पोल

संजय कुमार
प्रोफेसर व राजनीतिक टिप्पणीकार
sanjay@csds.in

29 अप्रैल की शाम को असम, तमिलनाडु, केरल, बंगाल तथा पुडुचेरी के लिए जारी किए गए एग्जिट पोल कई नेताओं और दलों के लिए सुकून का कारण नहीं बन सके। कारण, कम से कम दो राज्यों- तमिलनाडु और बंगाल के लिए एग्जिट पोल के अनुमान एक-दूसरे से काफी भिन्न हैं। लेकिन असम व केरल में लगभग सभी एजेंसियों के बीच इस बात पर व्यापक सहमति दिखाई देती है कि कौन-सा दल या गठबंधन जीत रहा है।

अधिकांश एग्जिट पोल असम में भाजपा-नेतृत्व वाले गठबंधन को निर्णायक बढ़त देते हैं, जबकि केरल में कांग्रेस-नेतृत्व वाले यूडीएफ की जीत का संकेत मिलता है। लेकिन बंगाल और तमिलनाडु में परिणाम को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। कुछ एजेंसियों ने तो बंगाल के लिए एग्जिट पोल का अनुमान जारी करने को टालना तक उचित समझा है, क्योंकि वहां मतदान का दूसरा चरण 29 अप्रैल को ही समाप्त हुआ था और वे आंकड़ों को बेहतर ढंग से समझने के लिए थोड़ा समय लेना चाहते हैं। इसे मैं एक विवेकपूर्ण निर्णय कहूंगा, क्योंकि कई बार मतदान आधिकारिक समय समाप्त होने तक भी लंबी कतारों के कारण जारी रहता है। हालांकि यह भी याद रखना चाहिए कि एक दिन और रुक जाना इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि सीटों का अनुमान अधिक सटीक हो जाएगा। आखिरकार तमिलनाडु में तो मतदान 23 अप्रैल को ही समाप्त हो गया था और एजेंसियों के पास आंकड़ों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त समय था, फिर भी विभिन्न एजेंसियों के अनुमान वहां भी एक-दूसरे से भिन्न हैं।

असम और केरल के लिए लगभग सभी एग्जिट पोल एक ही दिशा में संकेत दे रहे हैं, लेकिन इसका यह कारण नहीं है कि एजेंसियों को डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए असाधारण रूप से अधिक समय मिला था। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं- जैसे अपेक्षाकृत कम राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के सामने विपक्ष द्वारा पेश की गई चुनौती का स्वरूप, और अन्य फैक्टर्स। फिर भी, असम और केरल के एग्जिट पोल को सावधानी से पढ़ने की आवश्यकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सभी एग्जिट पोल चूक गए थे; उन्होंने एनडीए के लिए 400 से अधिक सीटों का अनुमान लगाया था। इसी तरह, 2024 के हरियाणा चुनाव में भी लगभग सभी एजेंसियों के बीच कांग्रेस की बड़ी जीत को लेकर सहमति थी। यही स्थिति 2023 के छत्तीसगढ़ चुनाव में भी देखने को मिली, जहां एग्जिट पोल द्वारा कांग्रेस की निश्चित जीत का अनुमान लगाया गया था। बिहार विधानसभा चुनाव में एग्जिट पोल की सफलता का रिकॉर्ड मिश्रित रहा। कई ने एनडीए की जीत का अनुमान लगाया था, लेकिन किसी ने भी इतनी बड़ी जीत की भविष्यवाणी नहीं की थी।

तमिलनाडु में एग्जिट पोल के अनुमान कुछ जटिल प्रतीत होते हैं। जिन चार एग्जिट पोल पर मेरी नजर गई, उनमें से तीन ने डीएमके गठबंधन की जीत का अनुमान लगाया है, एआईएडीएमके गठबंधन को दूसरे स्थान पर और विजय के नेतृत्व वाली टीवीके को तीसरे स्थान पर रखा है, जबकि तमिलनाडु के संदर्भ में एक एग्जिट पोल अपवाद के रूप में सामने आता है। जिस राज्य ने सबसे अधिक लोगों की सांसें थाम रखी हैं, वह बंगाल है। वहां चुनाव अत्यंत कड़े मुकाबले में लड़े गए हैं। अब तक सार्वजनिक किए गए अधिकांश एग्जिट पोल बंगाल में भाजपा की जीत का अनुमान लगा रहे हैं,

हालिया एग्जिट पोल्स ने विशेषकर तमिलनाडु और बंगाल के संदर्भ में यह बताने के बजाय कि वोट किस प्रकार पड़े होंगे, उलटे दुविधा और चिंता को और बढ़ाया है। इस बार एग्जिट पोल की संख्या भी अपेक्षाकृत कम है।

हालांकि यहां भी एक एग्जिट पोल ऐसा है जो इस प्रवृत्ति से अलग, एक अपवाद के रूप में सामने आता है।

इस समय यह कहना कठिन है कि ये अनुमान 4 मई को आने वाले वास्तविक परिणामों की तुलना में कितने सटीक साबित होंगे। लेकिन मेरा मानना है कि यदि चुनाव-विश्लेषक गलत साबित होते हैं, तो इसका कारण मुख्यतः वोट-शेयर के अनुमान में त्रुटि हो सकता है। वोट-प्रतिशत में मामूली बदलाव भी सीटों की संख्या में बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। हमने ऐसे चुनाव देखे हैं, जहां किसी दल ने अपने प्रतिद्वंद्वी की तुलना में कम वोट-प्रतिशत होने के बावजूद अधिक सीटें जीत ली हैं। हमारी चुनावी व्यवस्था- फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली- में यह जटिलता और बढ़ जाती है। इसमें कोई उम्मीदवार एक वोट से जीते या एक लाख वोटों से, दोनों ही स्थितियों में उसे केवल एक सीट ही मिलती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

इस लेख को मोबाइल पर सुनने के लिए **QR कोड** को स्कैन करें।

ब्रांड से सबक सन फार्मा : भारतीय फार्मास्युटिकल कंपनी

अमेरिकी नियमों से घटा था 65% मार्केट कैप, उसी बाजार में पांच कंपनियां खरीदीं

सन फार्मा, देश की नंबर-1 फार्मा कंपनी। अमेरिका में भी यह स्किन से जुड़ी जेनेरिक दवाओं की बिक्री के मामले में दूसरे नंबर पर है। दुनियाभर में हर मिनट करीब 1000 डॉक्टर इसकी दवाएं मरीजों के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। यही नहीं, भारत में मेडिकल स्टोर पर बिकने वाली हर 11वीं-12वीं दवा सन फार्मा की होती है।

हालांकि एक समय ऐसा था जब अमेरिकी संस्था एफडीए के प्रतिबंधों के कारण इसका बाजार मूल्य करीब 65% तक घट गया था। दरअसल सन फार्मा ने 2014 में करीब 24,000 करोड़ रुपए में रैनबैक्सी का अधिग्रहण किया। रेनबैक्सी के प्लांट अमेरिकी रेगुलेटर के गंभीर समस्याएं झेल रहे थे, जिससे सन फार्मा भी निशाने पर आ गई। तब कंपनी का शेयर करीब 1200 रुपए था जो चार वर्षों में 420 रु. के करीब पहुंच गया। कंपनी के संस्थापक और सीईओ दिलीप सांघवी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि रैनबैक्सी की रेगुलेटरी समस्याओं और 'कचरे' को साफ करना उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन रहा। सन फार्मा ने हाल ही में अमेरिकी फार्मा कंपनी 'ऑर्गेनॉन' को 1.10 लाख करोड़ रुपए में खरीदा है।

सबक... सन फार्मा की कहानी बताती है कि कमजोरियों को इस तरह सुधारें कि वे ताकत बन जाएं।

6 महाद्वीपों में करीब 43 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं

41,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं कंपनी के दुनियाभर में

100 से अधिक देशों में व्यापार कर रही है सन फार्मा

21% कार्बन उत्सर्जन घटाया है कंपनी ने

• वर्तमान स्थिति

4.35 लाख करोड़ की कंपनी, 8.3% हिस्सेदारी

वर्तमान में यह न केवल देश की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है, बल्कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी स्पेशियलिटी जेनेरिक दवा कंपनी बन चुकी है। दुनिया के 100 से अधिक देशों में व्यापार कर रही है। सन फार्मा का मार्केट कैप करीब 4.35 लाख करोड़ रुपए है। वित्त वर्ष 2024-25 में कंपनी का कुल रेवेन्यू लगभग 54,729 करोड़ रहा है। इसमें सबसे रोचक डेटा यह है कि कंपनी की कुल बिक्री का लगभग 20% हिस्सा अब इसके इनोवेटिव 'स्पेशियलिटी पोर्टफोलियो' से आता है। कंपनी की वित्तीय वर्ष 2025 की रिपोर्ट के अनुसार देश के फार्मा बाजार में इसकी हिस्सेदारी करीब 8.3 प्रतिशत के करीब है।

यूं संकट में फंसी थी...

- **रैनबैक्सी का बोझ:** अधिग्रहण के बाद, सन फार्मा को रैनबैक्सी के विवादित प्लांट्स के कारण अमेरिका से मिलने वाला बड़ा रेवेन्यू रुक गया। एफडीए की निगरानी से नए ड्रग अप्रूवल ठप हो गए।
- **भारी कर्ज :** रैनबैक्सी को उस समय अमेरिका में करीब 3,000 करोड़ रुपए जुर्माने के रूप में देने थे। सन फार्मा को यह वित्तीय बोझ और कानूनी उलझनें भी अधिग्रहण के साथ मिलीं।
- **एफडीए की सख्ती:** गुजरात के हालोल प्लांट्स पर 2015 में अमेरिकी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) के प्रतिबंधों से रेवेन्यू रुक गया।
- **कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर सवाल:** 2018 में एक व्हिसलब्लोअर ने वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगाए। इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग, फंड का गलत तरीके से एडजस्टमेंट करने जैसे गंभीर आरोप थे।

इस तरह की वापसी...

- **ऑपरेशनल क्लीन-अप :** सांघवी ने रेनबैक्सी के विवादित प्लांट्स या तो बेच दिए या पूरी तरह ऑटोमेटेड करके अमेरिकी एफडीए की मंजूरी दिलाई। 2020 तक 100% प्लांट ऑटोमेटड किए।
- **वित्तीय अनुशासन :** 2019-25 तक करीब 11 हजार करोड़ रुपए का कर्ज चुकाया। ऑटोमेशन और आउटसोर्सिंग से बिक्री एवं प्रशासनिक खर्च 20 प्रतिशत तक कम किया।
- **नए बाजार खोजे :** अमेरिका पर निर्भरता कम कर भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे देशों में विस्तार किया। अमेरिकी हिस्सेदारी 40% रह गई।
- **लीडरशिप में बदलाव :** बोर्ड में मैकेंजी के पूर्व सीईओ से लेकर अमेरिकी एफडीए के विशेषज्ञ जैसे अंतरराष्ट्रीय एक्सपर्ट शामिल किए। इससे निवेशकों का विश्वास बढ़ा।

शुरुआत : पिता से 10,000 रुपए उधार लेकर रखी थी नींव

सन फार्मा की नींव 1983 में गुजरात के वापी में रखी गई। दिलीप सांघवी ने दवाओं के थोक विक्रेता पिता शांतिलाल से 10,000 रु. उधार लेकर मनोरोगों से जुड़ी सिर्फ 5 दवाओं से इसकी शुरुआत की थी। टीम में सिर्फ दो लोग थे। सांघवी ने शुरू में जेनेरिक दवाओं के बजाय खास दवाओं पर फोकस कर खुद को भीड़ से अलग किया।

अधिग्रहणों से बनी दिग्गज : 1997 से 2026 तक 6 कंपनियां खरीदीं

सन फार्मा ने कई अधिग्रहण कर खुद को फार्मा का दिग्गज बनाया है। सबसे पहले 1997 में अमेरिका की 'कैरको फार्मा' को खरीदा। 2010 में इजराइली कंपनी 'टैरो', 2014-15 में अमेरिका की रैनबैक्सी लैबोरेटरीज, 2023 में कॉन्सर्ट फार्मा और मार्च 2025 में चेकपॉइंट थेरेप्यूटिक को खरीदा। 2026 में ऑर्गेनान फार्मा का अधिग्रहण किया।

ऐसे पड़ा नाम : दिलीप सांघवी ऐसा नाम चाहते थे जो सकारात्मकता, ऊर्जा और निरंतरता का प्रतीक हो। इसलिए उन्होंने सूरज पर 'सन फार्मा' नाम रखा।

सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी : भारत में डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, ल्यूपिन और सिप्ला व अमेरिकी और वैश्विक जेनेरिक मार्केट में टेवा फार्मास्यूटिकल्स और सैंडोज प्रमुख हैं।

पीपुल भास्कर अब्बास अरागची, ईरान के विदेश मंत्री

ईरान के 'डील मेकर', लेटेस्ट गैजेट और फारसी संगीत के शौकीन हैं अरागची

चर्चा में क्यों : ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे सीजफायर में समझौतों पर एकमत होने के लिए मुख्य भूमिका निभा रहे हैं।

जुलाई 2015, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन के साथ जर्मनी के लीडर उपस्थित थे। ईरान और इन देशों के बीच परमाणु समझौते की वार्ता अंतिम दौर में थी। अमेरिकी प्रमुख वार्ताकार वेंडी शेरमन और अरागची आमने-सामने थे। संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव की भाषा पर सहमति बन चुकी थी, तभी अरागची ने एक बार फिर पहले से तय मुद्दा उठाने के लिए कहा 'बस एक और बात।' शेरमन, जो कई रातों से ठीक से सोई नहीं थीं, ऊंची आवाज में लगभग चींख पड़ीं, 'अब्बास बहुत हुआ, तुम्हारी मांगें खत्म ही नहीं होती हैं, और उनकी आंखों में आंसू आ गए।

अरागची दस्तावेजों में लिखे कॉमा और फुलस्टॉप के लिए भी घंटों बहस कर सकते हैं।
-वेंडी शेरमन, पूर्व अमेरिकी डिप्लोमैट

शेरमन अपनी किताब 'Not for the Faint of Heart' में लिखती हैं कि 'वह बहुत स्मार्ट और बहुत कठोर हैं।' पश्चिमी देश उनके लिए 'डील मेकर', 'प्रैग्मैनिटिक निगोशिएटर' जैसे विशेषणों का इस्तेमाल करते हैं यानी उनमें परिस्थिति के हिसाब से व्यावहारिक समाधान खोजने की अद्भुत क्षमता है।

अरागची को फारसी संगीत का बेहद शौक है। वे जापान की सादगी से बहुत प्रभावित हैं। वे लेटेस्ट गैजेट इस्तेमाल करने के शौकीन हैं। वे अक्सर अपनी बात रखने के लिए सोशल मीडिया का खूब इस्तेमाल करते हैं। लंबी वॉक उनकी दिनचर्या का हिस्सा है।

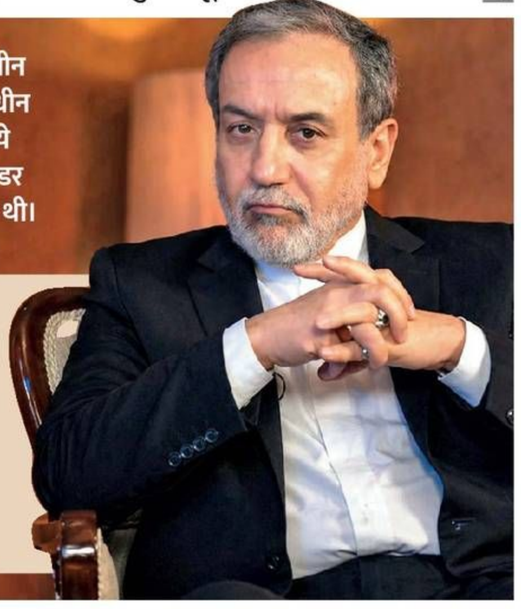

2007-13 के दौरान ईरान के तत्कालीन मुख्य वार्ताकार सईद जलीली के अधीन काम करते हुए उनके कूटनीतिक रवैये से असहमति के बाद सीधे सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई से शिकायत की थी।

जन्म : 5 दिसंबर 1962, तेहरान।

शिक्षा : इंग्लैंड की केंट यूनिवर्सिटी से पीएचडी।

परिवार : पत्नी- अरेजू अहमवंद (दूसरी पत्नी, पहली से तलाक, तीन बच्चे- पहली पत्नी से दो, दूसरी से एक बेटी)

• परिवार

17 की उम्र में उठ गया था पिता का साया

अब्बास का परिवार कालीन का व्यापार करता था। अब्बास जब 17 साल के थे तभी पिता का निधन हो गया। 1996 में इंग्लैंड की केंट यूनि. से पीएचडी की। उनके शोध का विषय था '20वीं सदी के इस्लामी राजनीतिक विचार में राजनीतिक भागीदारी की अवधारणा का विकास' यानी पश्चिमी लोकतंत्र और इस्लामी शासन के बीच का संबंध।

• विवाह

दो शादियां की, तीन बच्चे

अरागची की पहली शादी बहारे अब्दुल्लाही से हुई थी। वे प्रतिष्ठित परिवार से थीं। बाद में तलाक हो गया। उन्होंने करीब 6 साल पहले दूसरी शादी अरेजू अहमदवंद से की। दोनों की करीब 4 साल की बेटी है। मार्च 2025 में नवरोज के दिन एक टेलीविजन कार्यक्रम में वे नई पत्नी और बेटी के साथ नजर आए थे, जिससे उनकी पहली शादी टूटने की जानकारी मिली।

• करियर

आईआरजीसी से विदेश मंत्री तक

1989 में अरागची ने ईरानी विदेश मंत्रालय के अंतरराष्ट्रीय मामलों के विभाग में काम शुरू किया, इसके पहले नौ वर्षों तक इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) में रहे। फिनलैंड और जापान में ईरान के राजदूत रहे। 2003-04 में पश्चिमी यूरोप विभाग के प्रमुख बने। 2024 में राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने उन्हें विदेश मंत्री मनोनीत किया।

खास : फिनलैंड में अक्सर साइकिल से ऑफिस जाते थे

- अब्बास अंग्रेजी और अरबी दोनों ही भाषाएं धाराप्रवाह बोल लेते हैं, जो ईरान में मुश्किल है।
- ईरान में 'स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन' के डीन रह चुके हैं।
- ईरान और अमेरिका के बीच जब भी तनाव होता है अरागची वर्ताओं में शामिल रहते हैं।

उपलब्धि : जापान का 'ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन' सम्मान

- अब्बास राजनेता होने के साथ ही लेखक भी हैं। दो पुस्तकें 'ईरान तैशी' और 'निगोसिएशन : द पावर ऑफ डिप्लोमेसी' लिख चुके हैं।
- ईरान सरकार ने 2015 में हुए परमाणु समझौते में उनकी भूमिका के लिए 'ऑर्डर ऑफ मेरिट एंड मैनेजमेंट' सम्मान प्रदान किया था।

विवाद : पारिवारिक बिजनेस को फायदा पहुंचाने के आरोप

- भतीजे अहमद अरागची पर विदेशी मुद्रा भंडार में हेराफेरी और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे थे। भतीजा सेंट्रल बैंक का डिप्टी गवर्नर था।
- 2015 के परमाणु समझौते के दौरान कालीन व्यवसाय में छूट की मांग पर पारिवारिक बिजनेस को फायदा पहुंचाने के आरोप लग चुके हैं।

बिज़नेस भास्कर
Business Standard और TheEconomist की ख़बरों के साथ
नई दिल्ली, शुक्रवार 1 मई , 2026

देश का लोन पोर्टफोलियो • बीते साल 4.4 करोड़ भारतीयों ने पहली बार लोन लिया, इनमें महिलाओं और 25 वर्ष से कम उम्र के लोगों का दबदबा: क्रिफ हाई मार्क

पहली बार लोन... दक्षिण की महिलाएं गोल्ड तो उत्तर भारत की बिजनेस लोन ले रहीं

भास्कर न्यूज | मुंबई

भारतीय लोन मार्केट का चेहरा बदल रहा है। पहली बार लोन लेने वालों (न्यू टू क्रेडिट) की दौड़ में महिलाएं पुरुषों को टक्कर दे रही हैं। क्रेडिट एजेंसी क्रिफ हाई मार्क की 'ब्रिजिंग द गैप' रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी 2026 तक 12 माह में महिलाओं की हिस्सेदारी 41% हो गई, जो फरवरी 2022 तक 33% थी। यानी 10 में से 4 नई कर्जदार महिलाएं हैं। खास बात यह है कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन बढ़ने के बीच यूपी, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में महिलाएं उद्यमी बनने के लिए बिजनेस लोन ले रही हैं, वहीं, दक्षिण में गोल्ड लोन का दबदबा है।

पहले लोन में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का दबदबा...

पहली बार लोन लेने वालों में से 32% वॉशिंग मशीन, फ्रिज या टीवी खरीदने के लिए लोन लेते हैं। यही एंट्री पॉइंट बनता है। और एक बार जो रिश्ता बनता है, वह आगे भी बना रहता है। गोल्ड लोन लेने वालों में से 84.5% अगला लोन भी गोल्ड पर ही लेते हैं।

पहली बार लोन लेन वाले लोगों की प्राथमिकता ?

कंज्यूमर लोन	31.6%
गोल्ड लोन	20.2%
दो पहिया	16.9%
पर्सनल लोन	11.0%
बिजनेस लोन	9.5%

एनबीएफसी नए लोगों को लोन का बड़ा सहारा

आमतौर पर माना जाता है कि वित्तीय समावेशन का बोझ सरकारी बैंकों पर होता है, लेकिन डेटा इसके विपरीत कहानी कह रहा है। बैंक पहली बार कर्ज लेने वालों को लोन देने से बचते हैं।

- एनबीएफसी का हिस्सा 50% से बढ़कर 61% हो गया
- सरकारी बैंकों का हिस्सा 16% से घटकर 13.6%
- निजी बैंकों का 22% से घटकर 15%

यूपी, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में महिला कर्जदारों की संख्या सबसे ज्यादा

क्रेडिट मार्केट

4.4 करोड़ लोगों ने इस साल पहली बार लोन लिया। 1 साल पहले यह संख्या 3.6 करोड़ थी। यानी 5.1% ग्रोथ।

29 देश में करोड़ लोग अब 'क्रेडिट-एक्टिव' हैं। यानी हर 5 में से एक शख्स ने लोन ले रखा है।

महिलाओं की पसंद अब बदल रही है। वे केवल गहने गिरवी रखकर लोन नहीं ले रहीं, बल्कि अपना काम शुरू करने के लिए बिजनेस लोन भी ले रही हैं। शीर्ष 10 में से 5 राज्यों में महिलाओं के बीच बिजनेस लोन प्रमुख प्रोडक्ट बन गया है।

महिलाओं की पसंद

1. कंज्यूमर ड्यूरेबल	25.2%
2. गोल्ड लोन	21.8%
3. बिजनेस लोन	17.9%
4. पर्सनल लोन	8.3%

यूपी, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में महिला कर्जदारों की संख्या सबसे ज्यादा है। दक्षिण भारत की महिलाएं गोल्ड लोन ज्यादा ले रही हैं, तो उत्तर और पूर्वी भारत (यूपी, बंगाल, बिहार) की महिलाएं बिजनेस लोन में आगे हैं।

- नए कर्जदार उम्मीद से ज्यादा सुरक्षित साबित हो रहे। इनकी सफलता दर बेहतर है। 67% ग्राहक एक साल में सुरक्षित रिस्क कैटेगरी में शामिल हुए।

युवा: दोपहिया और पर्सनल लोन से शुरुआत

25 साल से कम उम्र के युवाओं के लिए 'मोबिलिटी' और 'लिक्विडिटी' सबसे अहम है, यही वजह है कि टू-व्हीलर और पर्सनल लोन सेगमेंट में इनका दबदबा है। वहीं, 26 से 35 साल के युवा कंज्यूमर ड्यूरेबल, गोल्ड लोन और बिजनेस लोन में दबदबा रखते हैं।

25 साल से कम के युवा

दो पहिया लोन 33.1% | पर्सनल लोन 50.3%

26-35 साल के युवा

सीडी* 35.4% | गोल्ड लोन 29.4% | बिजनेस लोन 30.7%

*कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, उस प्रोडक्ट में उस आयु वर्ग (12 माह, फरवरी 26 को खत्म)

- कंज्यूमर ड्यूरेबलः 80.4% ग्राहकों का रिस्क प्रोफाइल बेहतर हुआ।
- टू-व्हीलरः 75.3% ग्राहकों ने दिखाया बेहतरीन अनुशासन।
- दो पहिया लोन में छोटे-मझोले शहरों की हिस्सेदारी 71 फीसदी और कंज्यूमेर ड्यूरेबल लोन में करीब 67 फीसदी है।

बिजनेस ब्रीफ

₹8.5 लाख करोड़ पार पहुंचेगा विदेशी निवेश

नई दिल्ली| भारत के प्रति वैश्विक निवेशकों का भरोसा नई ऊंचाई पर है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया के अनुसार, बेहतर नीतिगत सुधारों, एफटीए व मजबूत आर्थिक विकास के चलते वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) 8.5 लाख करोड़ रुपए पार करने के लिए तैयार है। फरवरी 2026 तक यह 8.37 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है।

फ्लैट के दाम 20% तक बढ़े, महंगे घरों की डिमांड

नई दिल्ली| दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे समेत देश के सात बड़े शहरों में जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान अपार्टमेंट की कीमतें सालाना आधार पर 8% से लेकर 20% तक बढ़ गईं। जेएलएल के मुताबिक, निर्माण लागत और प्रीमियम प्रोजेक्ट्स की बढ़ती हिस्सेदारी से कीमतों में तेजी आई। इसके बावजूद बीती तिमाही 1 करोड़ रुपए से महंगे घरों की बिक्री 30% बढ़ गई।

रिलायंस ने प्रियंका चोपड़ा का ब्यूटी ब्रांड खरीदा

मुंबई | रिलायंस रिटेल ने अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा जोनस के हेयरकेयर ब्रांड 'एनोमली' को

खरीद लिया है। डील की रकम नहीं बताई गई है। कंपनी भारत के तेजी से बढ़ते ब्यूटी और पर्सनल केयर बाजार में अपनी मौजूदगी मजबूत करना चाहती है। रिलायंस पहले से टीरा प्लेटफॉर्म के जरिये ब्यूटी कारोबार बढ़ा रही है। एनोमली को साफ-सुथरे और इको-फ्रेंडली ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है।

अप्रैल में सोना आयात 30 साल में सबसे कम 15 टन

नई दिल्ली| अप्रैल में देश का सोना आयात 30 साल के निचले स्तर 15 टन पर आ गया। अप्रैल 2025 में 35 टन सोना आयात किया गया था। ऊंची कीमतों पर कमजोर मांग को देखते हुए इस महीने ज्वेलर्स ने आयात घटा दिए। सरकारी अधिकारियों ने बताया कि अप्रैल में सोने का आयात पिछले साल के मुकाबले कम रहा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें रिकॉर्ड ऊंचाई पर रहने से उपभोक्ता खरीदारी भी प्रभावित हुई है।

तिमाही नतीजे • लाभ 21% बढ़ा, वजह- न्यूट्रिशनलैब बेचने से ₹307 करोड़ मिले

एचयूएलः 11 तिमाही के बाद गांवों में लौटी रौनक; होम केयर में 9% की रिकॉर्ड ग्रोथ

भास्कर न्यूज | मुंबई

भारत का कंज्यूमर बदल रहा है। इसकी झलक एफएमसीजी दिग्गज हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) के नतीजों में दिखती है। कंपनी ने मार्च तिमाही में 8% ग्रोथ दर्ज की, जिसमें 6% वॉल्यूम ग्रोथ है। यानी खपत बढ़ रही है। लेकिन इस ग्रोथ की असल कहानी आंकड़ों से ज्यादा कंज्यूमर बिहेवियर में छिपी है। स्किन केयर में मास सेगमेंट का प्रदर्शन सुस्त रहा, वहीं प्रीमियम स्किन केयर, ब्यूटी-वेलबीइंग में 8% उछाल रही। कंपनी का जनवरी मार्च तिमाही में मुनाफा 21% बढ़कर 2,992 करोड़ रहा। इस लाभ में से न्यूट्रिशनलैब की बिक्री से आए 307 करोड़ हटा दें तो असल ऑपरेशनल मुनाफा 8% ही बढ़ा, जो एफएमसीजी सेक्टर में दबाव को दर्शाता है। पूरे साल का देखें तो 41% बढ़कर 15,040 करोड़ रहा, जिसमें आइसक्रीम डीमर्जर का 4,485 करोड़ लाभ शामिल है। इसे हटा दें तो पूरे साल लाभ -0.8% रहा।

एचयूएल के नतीजे बताते हैं कि ग्राहक अब हेल्थ-कॉन्शियस और प्रीमियम-ओरिएंटेड हो गया है। वैसलीन और सनसिल्क जैसे ब्रांड्स का 1,000 करोड़ रुपए और सर्फ एक्सेल लिक्विड का 4,000 करोड़ का ब्रांड बनना यह दर्शाता है कि उपभोक्ता अब प्रीमियमाइजेशन की ओर शिफ्ट हो रहा है।

एचयूएलः जनवरी-मार्च तिमाही, पूरे साल का रिजल्ट (कन्सॉलिडेटेड) एक नजर में

मापदंड	Q4 FY26	Q4 FY25	अंतर	FY25-26	FY24-25	अंतर
ऑपरेटिंग रेवेन्यू	16,351	15,190	7.6%	64,468	61,328	5.1%
टैक्स पूर्व लाभ	3,924	3,398	15.5%	13,812	14,428	-4.3%
ऑपरेटिंग मार्जिन	26.6%	25.0%	6.5pp	24.1%	26.2%	-7.9pp
टैक्स बाद लाभ	2,992	2,464	21.4%	15,040	10,649	41.2%

आंकड़े करोड़ रुपए में, स्रोतः कंपनी फाइलिंग

मार्केट कैप | एचयूएल का मार्केट कैप 31 मार्च 2026 तक 4.83 लाख करोड़ रुपए था।

22 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड की घोषणा की। पूरे साल का डिविडेंड 41 रु. प्रति शेयर हो गया है।

एफएमसीजी कंपनी के हेल्थ और हाइजीन प्रोडक्ट बने नए ग्रोथ इंजन

न्यूट्रिशन पर फोकस, कॉफी की ग्रोथ तेज

हॉर्लिक्स और बूस्ट जैसे ब्रांड्स की डबल डिजिट ग्रोथ और प्रोटीन ड्रिंक्स में एंट्री यह दिखाती है कि अब कंज्यूमर की प्राथमिकता में हेल्थ सबसे ऊपर है। इसके अलावा, चाय के मुकाबले कॉफी की तेज ग्रोथ यह संकेत देती है कि शहरी भारत में लाइफस्टाइल आधारित खपत बढ़ रही है।

रूरल रिकवरी और 'होम केयर' का दबदबा

इस एफएमसीजी कंपनी की होम केयर सेगमेंट में 9% की वृद्धि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में मजबूत मांग का संकेत है, जो पिछले 11 तिमाहियों में सबसे अधिक है, विशेष रूप से लिक्विड (जैसे सर्फ एक्सेल मेटिक) पोर्टफोलियो ने 4,000 करोड़ का मील का पत्थर पार किया है।

क्विक कॉमर्स से टर्नओवर दोगुना बढ़ा

नतीजे में चौंकाने वाला आंकड़ा ब्लिंकिट, जेप्टो, इंस्टामार्ट जैसे क्विक कॉमर्स का है, जिसने वित्त वर्ष 2026 में टर्नओवर को दोगुना कर दिया। ई-कॉमर्स में 25% से अधिक की वृद्धि और क्यू-कॉमर्स का दोगुना होना यह बताता है कि सुविधा अब कीमत से ज्यादा अहम होती जा रही है।

यदि संकट बढ़ा तो बढ़ानी पड़ेगी कीमतें...

चाय कीमतों में वृद्धि देखी गई, जिसके कारण उपभोक्ताओं ने डाउनग्रेड करना शुरू कर दिया। बड़े देशों में तनाव के कारण कच्चे तेल, पाम ऑयल की आपूर्ति प्रभावित हुई। कंपनी ने संकेत दिया है कि यदि कीमतें बढ़ती रहीं, तो मार्जिन बचाने के लिए कीमतों में वृद्धि करनी पड़ सकती है।

हमारा डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच और बाजार में पैठ बढ़ाने पर जोर: प्रिया नायर

हमने वित्त वर्ष 2026 में मजबूत और प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन किया। लगातार पांचवीं तिमाही में वॉल्यूम ग्रोथ में सुधार दर्ज किया। एचयूएल अब एक 'डिजिटल-फर्स्ट' और 'डेटा-संचालित' कंपनी बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रही है, जहां हम क्विक-कॉमर्स जैसे नए माध्यमों को प्राथमिकता दे रहे हैं ताकि ग्राहकों को आधुनिक अनुभव दिया जा सके।
-प्रिया नायर, एमडी और सीईओ, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड

घबराहट • महंगाई, आयात बिल बढ़ने की चिंता हावी

क्रूड 116 डॉलर, ₹95 पार... सेंसेक्स 583 अंक गिरा

भास्कर न्यूज | मुंबई

ब्रेंट क्रूड 3% तेजी के साथ 126 डॉलर प्रति बैरल हो गया। इस बीच रुपया 95.20 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया। इससे गुरुवार को शेयर बाजार में घबराहट दिखी। ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स 1,237 अंक टूटकर 76,259 के निचले स्तर तक आ गया। हालांकि आखिरी घंटों में क्रूड 116 पर आने से रिकवरी आई और सेंसेक्स की गिरावट 583 अंकों पर सिमट गई।

सेंसेक्स 583 अंक गिरकर 76,913 पर और निफ्टी 180 अंक टूटकर 23,997 पर बंद हुआ। कच्चे तेल में उछाल से महंगाई और आयात बिल बढ़ने व विदेशी निवेश निकलने की चिंता गहरा गई। रुपया भी डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड निचले स्तर पर गया। इस बीच एशियाई और अमेरिकी बाजारों में कमजोरी से निवेशकों का भरोसा और डगमगाया। एफएंडएओ (वायदा बाजार) एक्सपायरी, विदेशी निवेशकों की बिकवाली और होर्मुज जल मार्ग से जुड़े तनाव ने बाजार का उतार-चढ़ाव बढ़ाया। हालांकि निचले स्तरों पर खरीदारी होने से बाजार ने कुछ नुकसान की भरपाई कर ली।

कच्चा तेल 126 डॉलर तक पहुंचने से प्रभावित होगी अर्थव्यवस्था

ब्रेंट क्रूड 126 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंचने से महंगाई बढ़ने की आशंका गहरा गई। हालांकि बाद में यह 116 डॉलर पर आ गया। भारत जरूरत का करीब 75% क्रूड आयात करता है। इसलिए इसके महंगा होने से सरकार का आयात बिल और कंपनियों का खर्च, दोनों बढ़ सकते हैं। इसका सीधा असर बाजार के सेंटिमेंट पर नजर आया।

60% शेयरों में गिरावट, सिर्फ 36% चढ़े

बीएसई पर कुल ट्रेडिंगः 4,337 शेयर

बढ़त	गिरावट	स्थिरता
1,581 शेयर	2,606 शेयर	150 शेयर

स्मॉलकैप-मिडकैप में 12 साल की सबसे बड़ी मासिक तेजी

बीएसई के स्मॉलकैप और मिडकैप इंडेक्स अप्रैल में 12 साल की सबसे तेज मासिक रैली की ओर बढ़ रहे हैं। अप्रैल में अब तक स्मॉलकैप इंडेक्स 20% और मिडकैप इंडेक्स 15% चढ़ चुके हैं, जबकि सेंसेक्स में 7.5% ही बढ़त रही। अब इस महीने सिर्फ एक दिन की ट्रेडिंग (शुक्रवार को) बची है। इससे पहले मई 2014 में स्मॉलकैप 20.4% और मिडकैप 15.6% उछले थे।

बेहतर नतीजे, आईपीओ मार्केट में कम मौकों का असर

- विश्लेषकों के मुताबिक, चौथी तिमाही के नतीजों को लेकर उम्मीद, आईपीओ बाजार में सीमित मौके और 2025 की गिरावट के बाद आकर्षक वैल्युएशन से निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी।
- बीएसई स्मॉलकैप इंडेक्स के 1,262 शेयरों में से 734 ने अप्रैल में 20% से ज्यादा रिटर्न दिया। हालांकि विशेषज्ञों ने कहा कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतें, होर्मुज जल मार्ग संकट और कमजोर रुपया आगे बाजार में उतार-चढ़ाव बढ़ा सकते हैं।

राहत • आधार वेरिफिकेशन से सीधे खाते में आएगा अटका फंड

बिना यूएएन भी कर सकेंगे पुराने पीएफ पर क्लेम, ई-प्राप्ति पोर्टल से ट्रैक होंगे अकाउंट

अहोना मुखर्जी | नई दिल्ली

नौकरी बदलने या कंपनी बंद होने से अटका पीएफ निकालना आसान होगा। केंद्र जल्द 'ई-प्राप्ति' पोर्टल लॉन्च करेगा। इससे उन निष्क्रिय खातों तक पहुंचा जा सकेगा, जो यूएएन से लिंक नहीं हैं। यह पोर्टल आधार वेरिफिकेशन से काम करेगा। देश में अभी 21.5 लाख निष्क्रिय खातों में ₹8,505 करोड़ जमा हैं। नया सिस्टम सदस्यों को खुद फंड खोजने की सुविधा देगा। पहले चरण में यह सुविधा उन्हें मिलेगी जिन्हें पुरानी मेंबर आईडी याद है। बाद में इसे 'कागजी रिकॉर्ड' वाले खातों के लिए भी शुरू किया जाएगा।

सुविधा: बिना कागजी झंझट पुराने रिकॉर्ड की पहचान

आधार आधारित मैकेनिज्म से पुराने रिकॉर्ड की पहचान बिना भागदौड़ के होगी। यह उन सब्सक्राइबर्स के लिए मददगार होगा जो तकनीकी जानकारी के अभाव में पैसा नहीं निकाल पाए थे। पूरी व्यवस्था डिजिटल होने से यह सुरक्षित और सुव्यवस्थित होगी।

सिस्टम: एम्प्लॉयर के बिना एक्टिव होंगे अकाउंट

पुराना खाता दोबारा चालू करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके बाद पुराना फंड ऑटोमैटिक तरीके से मौजूदा यूएएन से जुड़ जाएगा। इससे वर्षों से पड़ा पैसा कर्मचारी के खाते में आ जाएगा। पुरानी कंपनी के चक्कर नहीं काटने होंगे।

चुनौतीः 6 साल में 5 गुना बढ़ी निष्क्रिय फंड की राशि

लोकसभा की जानकारी के अनुसार, 2018-19 से 2023-24 के बीच निष्क्रिय खातों की रकम 5 गुना बढ़ी है। हालांकि, रिकवरी की प्रक्रिया भी तेज हुई है। अकेले इस साल लाभार्थियों को 2,632 करोड़ रुपए लौटाए जा चुके हैं। अब शेष राशि लौटाने की तैयारी है।

जापान एयरलाइंस के ग्राउंड ऑपरेशन्स संभालेंगे रोबोट, दो साल का ट्रॉयल शुरू

टोक्यो | जापान एयरलाइंस ने रोबोट के जरिये ग्राउंड ऑपरेशन्स का परीक्षण शुरू किया है। ये इंसानी रोबोट न केवल भारी सामान उठाने और रखने में सक्षम हैं, बल्कि केबिन के संकरे रास्तों में सफाई और मेंटेनेंस जैसे बारीक काम भी कर सकते हैं। इनमें लगे एडवांस सेंसर और कंप्यूटर विजन तकनीक इन्हें इंसानों के बीच सुरक्षित रूप से काम करने में मदद करती है। ▪ ब्रिटिश एयरवेज और एमिरेट्स ने चेक-इन या नेविगेशन के लिए रोबोट का उपयोग किया है, लेकिन शारीरिक श्रम वाले 'ग्राउंड हैंडलिंग' कार्यों में जापान एयरलाइंस का यह 2 साल का ट्रायल एक ग्लोबल बेंचमार्क सेट कर रहा है।

रिजल्ट • एयरपोर्ट बिजनेस का मुनाफा 75% बढ़ा

अदाणी एंटरप्राइजेज को मार्च तिमाही में 221 करोड़ का घाटा

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

अदाणी समूह की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज को जनवरी-मार्च तिमाही में 220 करोड़ का घाटा हुआ। बीते साल इसी तिमाही में 3,845 करोड़ का मुनाफा हुआ था। दरअसल, कंपनी को बीते साल समान तिमाही में अदाणी विल्मर में हिस्सेदारी बेचने से 3,945 करोड़ का लाभ मिला था। बीती तिमाही कंपनी के खर्चे रेवेन्यू के मुकाबले 23.5% बढ़कर 32,458 करोड़ रुपए पर पहुंच गए हैं। हालांकि पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में मुनाफा 31% बढ़कर 9,339 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। मुनाफे में इस उछाल की मुख्य वजह कोर इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल की ओर सफल ट्रांजिशन है। अदाणी एयरपोर्ट होल्डिंग्स की आय मार्च तिमाही में 21% बढ़ी। इसके एबिटा में 75% की ग्रोथ हुई।

अदाणी पोर्ट्सः तिमाही लाभ 9% बढ़कर 3,308 करोड़

अदाणी पोर्ट्स एंड एसईजेड का जनवरी-मार्च की तिमाही में मुनाफा 9.4% बढ़कर 3,308 करोड़ रुपए हो गया। यह पिछले साल समान तिमाही में 3,023 करोड़ था। बीती तिमाही में कुल आय में 31% की भारी बढ़ोतरी होने के कारण कंपनी के मुनाफे में यह उछाल आया है।

फेडरल बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड का क्रेडिट कार्ड फोलियो खरीदेगा

बिजनेस संवाददाता | मुंबई

प्राइवेट सेक्टर का फेडरल बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के रिटेल क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो से करीब 4.50 लाख कार्ड खरीदेगा। दोनों बैंक इसके लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले हैं। लेनदेन पूरा होने के बाद फेडरल बैंक को अपना क्रेडिट कार्ड आधार बढ़ाने और टियर-1 शहरों में पैठ मजबूत करने में मदद मिलेगी।

ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड अब भारत में स्टैंडअलोन क्रेडिट कार्ड के बजाय केवल वेल्थ और एफ्लुएंट सेगमेंट पर फोकस करेगा। दोनों के बीच हुए सौदे की कीमत का अभी खुलासा नहीं किया गया है लेकिन बैंक का अनुमान है कि यह अपनी असल वैल्यू से करीब डेढ़ गुना ज्यादा हो सकती है। इस सौदे से फेडरल बैंक की पहुंच देश के टॉप 8 शहरों में काफी बढ़ जाएगी। अधिग्रहीत किए जाने वाले पोर्टफोलियो का 75% हिस्सा इन्हीं बड़े महानगरों में केंद्रित है। इससे बैंक की टियर-1 शहरों में मौजूदगी दोगुनी से ज्यादा हो जाएगी। मार्च 2026 तक फेडरल बैंक के पास 22.4 लाख क्रेडिट कार्ड थे।

नए 4.5 लाख कार्ड जुड़ने से बैंक के नॉन को-ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स में करीब 90% की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वर्तमान में बैंक के पास 8 लाख नॉन को-ब्रांडेड और 13 लाख को-ब्रांडेड कार्ड हैं।

बिजनेस एंकर फेड प्रमुख जेरोम पॉवेल की विदाई, कभी कहा था-ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती

सामान पर लेबल चिपकाने वाले युवक से वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे अहम चेहरा बनने तक...पॉवेल ने जीवन के हर रंग देखे

भास्कर न्यूज | न्यूयॉर्क

आठ साल...तीन अमेरिकी राष्ट्रपति... 66 रेट सेटिंग मीटिंग...महामारी, महंगाई, राजनीतिक हमले आपराधिक जांच। इन सबके बीच जेरोम पॉवेल ने अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व की कमान संभाली। 29 अप्रैल को उन्होंने फेड चेयर के तौर पर आखिरी पॉलिसी मीटिंग ली। उनकी कहानी भरोसे, दबाव और ईमानदारी की मिशाल बन गई।

15 मई को चेयरमैन के तौर पर कार्यकाल खत्म होने के बाद भी पॉवेल फेड के गवर्नर और रेट-सेटिंग कमेटी के सदस्य बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि न्याय विभाग की जांच पूरी पारदर्शिता और अंतिम नतीजे पर पहुंचने तक उनका बने रहना जरूरी है। यह फैसला असामान्य जरूर है, लेकिन शायद पॉवेल हमेशा से ऐसे ही रहे- नियमों से ज्यादा संस्थान की साख को अहमियत देने वाले।

कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों में दुनिया की अर्थव्यवस्था जैसे अचानक थम गई थी। बाजार टूट रहे थे, सप्लाई चेन बिखर रही थी और करोड़ों लोग भविष्य को लेकर डरे हुए थे। मार्च 2020 में पॉवेल ने आपात बैठक बुलाकर ब्याज दरों में कटौती की। कुछ ही दिनों बाद रविवार को दूसरी इमरजेंसी बैठक बुलाई और दरें लगभग शून्य कर दी गईं। महामारी के बाद जब महंगाई 40 साल के ऊंचे स्तर पर पहुंची, तब भी पॉवेल आलोचनाओं के घेरे में रहे। फेड ने आक्रामक तरीके से ब्याज दरें बढ़ाईं। पॉवेल ने चेतावनी दी थी कि लोगों और कॉरपोरेट्स को कुछ दर्द झेलना पड़ेगा, लेकिन कीमतों को काबू में लाना जरूरी है। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी लड़ाई राजनीति से रही। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी उन्हें 'स्मार्ट' और मजबूत कहा था, लेकिन बाद में वही ट्रंप उन्हें 'फूल', 'नंबस्कल' और 'मेजर लूजर' जैसे शब्दों से निशाना बनाने लगे। इसके बावजूद पॉवेल ने शायद ही कभी सार्वजनिक जवाब दिया। जब फेड की स्वतंत्रता पर सवाल उठे, तब उन्होंने खुलकर कहा कि यह लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि इस बात की है कि अमेरिका में ब्याज दरें आंकड़ों से तय होंगी या राजनीतिक दबाव से।

पॉवेल की निजी कहानी भी उतनी ही मानवीय है। वह शुरुआत में गोदाम में सामान पर लेबल लगाने का काम करते थे। उन्होंने कभी अर्थशास्त्र को उबाऊ समझकर छोड़ दिया था, पर वही व्यक्ति वैश्विक अर्थव्यवस्था का सबसे अहम चेहरा बन गया।

सिर्फ एक पद का अंत नहीं, संस्थागत भरोसे की पूरी दास्तान है पावेल का करिअर

जेरोम पॉवेल ने 2024 में एक इंटरव्यू में कहा था, 'ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती। आखिर में आपके पास सिर्फ वही बचती है।' यही उनके पूरे कार्यकाल का सार बन गया। महामारी हो, महंगाई या राजनीतिक दबाव- पॉवेल ने कई फैसलों पर आलोचना झेली, पर फेड की स्वतंत्रता और अपनी साख से समझौता नहीं किया। उनकी विदाई सिर्फ एक पद का अंत नहीं, बल्कि संस्थागत भरोसे की कहानी बन गई।

वोडाफोन-आइडिया को 23,649 करोड़ की राहत

बिजनेस संवाददाता | नई दिल्ली

नकदी की किल्लत से जूझ रही कंपनी वोडाफोन-आइडिया के लिए सरकार ने एजीआर बकाया में 23,649 करोड़ रुपए की कटौती की है। दूरसंचार विभाग ने अब कंपनी की कुल देनदारी को 87,695 करोड़ से घटाकर 64,046 करोड़ रुपए तय किया। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बकाया के पुनर्मूल्यांकन के बाद लिया गया। इस राहत से कर्ज में डूबी कंपनी के कैश फ्लो में बड़ा सुधार होगा। संशोधित कार्यक्रम के तहत एजीआर भुगतान को लेकर दी गई मोहलत वित्त वर्ष 2031 तक जारी रहेगी। कंपनी को 2032 से 2035 के बीच हर साल केवल 100 करोड़ रुपए चुकाने होंगे। शेष राशि का भुगतान 2036 से 2041 के बीच 10,608 करोड़ रुपए की छह बराबर किस्तों में किया जाएगा।

हर देश अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा करने के लिए प्रयासरत है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। -जॉन बोल्टन

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की ओर

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मंगलवार देर रात वाहनों के ईंधन में इथेनॉल मिश्रण की सीमा 85 फीसदी या पूरे सौ फीसदी करने संबंधी जो मसौदा जारी किया है, उससे न केवल देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सकता है, बल्कि आयातित तेल पर निर्भरता भी घटेगी। गौरतलब है कि यह मसौदा ऐसे समय में आया है, जब वैश्विक ऊर्जा बाजार पश्चिम एशिया में चल रहे लंबे संघर्ष से जूझ रहा है, जिसने पारंपरिक तेल आपूर्ति शृंखला को बहुत हद तक बाधित करने के साथ आयात बिलों को बढ़ा दिया है। असल में, पिछले ही हफ्ते केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संकेत दिया था कि भारत को जल्द ही 100 फीसदी इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य रखना चाहिए। वास्तव में, भारत अपनी जरूरत का करीब 85 फीसदी तेल आयात करता है, जिससे आर्थिक बोझ और प्रदूषण बढ़ता है। एक अप्रैल से पूरे देश में 20 फीसदी इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल (ई-20) को लागू करने के बाद इस मसौदे को जारी करने से यह संकेत मिलता है कि सरकार अब अगले लक्ष्य की ओर देख रही है। पर, जहां ई-20 का उपयोग मौजूदा इंटरनल कम्बशन इंजन में मामूली बदलावों के साथ किया जा सकता है, वहीं ई-85 या ई-100 की ओर बढ़ने के लिए फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल की तरफ एक मजबूत बदलाव की आवश्यकता होगी। वैसे, 20 फीसदी इथेनॉल मिले पेट्रोल का इस्तेमाल करने वाले लोग माइलेज में गिरावट, इंजन की खड़खड़ाहट, धीमा पिकअप, और गाड़ी की सामान्य गति पर बुरा असर पड़ने की शिकायत करते हैं। लिहाजा, 85 या 100 फीसदी इथेनॉल इस्तेमाल करने के लिए वाहनों में तकनीकी बदलाव की जरूरत होगी, जिसके लिए वाहन निर्माता कंपनियों को निवेश बढ़ाना होगा। साथ ही, इथेनॉल हवा से नमी खींचता है, जिससे ईंधन टैंक में जंग लगने और कई पार्ट्स के तेजी से खराब होने का खतरा बढ़ जाता है। बेशक 85 फीसदी या सौ फीसदी इथेनॉल मॉडल को अपनाकर देश के विशाल कृषि अधिशेष का लाभ उठाया जा सकता है, पर इसके लिए गन्ने की खेती को बढ़ावा देना होगा, जिसके उत्पादन में पानी की खपत ज्यादा होती है। अलबत्ता, यदि ब्राजील की तरह इसे सफलतापूर्वक लागू करना संभव हो पाया, तो किसानों को भी फायदा होगा। वैसे मसौदा जारी करने का मतलब यह नहीं है कि ज्यादा इथेनॉल वाले ईंधन को तुरंत लागू कर दिया जाएगा; इस पर विचार-विमर्श होगा, फिर परीक्षण एवं मूल्यांकन के नियम बनाए जाएंगे। यदि ऐसा संभव होता है, तो इससे न केवल पर्यावरण स्वच्छ होगा, ऊर्जा सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि आयात बिल भी नियंत्रित होगा।

क्या यह ओपेक के अंत की शुरुआत है

यूएई का ओपेक से बाहर निकलने का फैसला इस बड़े बदलाव का संकेत है कि वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था अब पहले जैसी नहीं रही और आने वाले समय में अधिक प्रतिस्पर्धी, लचीली और अनिश्चित हो सकती है। अब यह देखना बाकी है कि अन्य देश इस दिशा में कब और कैसे कदम बढ़ाते हैं।

आनंद कुमार
एसोसिएट फेलो
एमपीआईडीएसए

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का ओपेक से बाहर निकलने का निर्णय केवल एक संगठनात्मक बदलाव नहीं, बल्कि यह वैश्विक ऊर्जा राजनीति में एक गहरे परिवर्तन का संकेत देता है। लगभग छह दशकों से ओपेक तेल उत्पादक देशों के बीच समन्वय स्थापित करने, उत्पादन को नियंत्रित करने और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतों को स्थिर रखने का काम करता रहा है। इस व्यवस्था ने सदस्य देशों को सामूहिक शक्ति प्रदान की, जिससे वे वैश्विक तेल बाजार में अपनी पकड़ बनाए रख सके, पर अब यूएई का यह कदम इस सामूहिक मॉडल की सीमाओं को उजागर करता है, जो बदलती आर्थिक प्राथमिकताओं, भू-राजनीतिक तनावों और ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे संरचनात्मक बदलावों के साथ तालमेल बिठाने में संघर्ष कर रहा है।

इस निर्णय के पीछे तात्कालिक व दीर्घकालिक, दोनों कारण हैं। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, विशेषकर ईरान से जुड़े संघर्षों और होर्मुज जलडमरूमध्य में उत्पन्न अस्थिरता ने तेल निर्यात पर निर्भर देशों के लिए जोखिम बढ़ा दिया है। होर्मुज जलडमरूमध्य वैश्विक तेल आपूर्ति का एक प्रमुख मार्ग है, और यहां किसी तरह का व्यवधान सीधे तौर पर तेल बाजार को प्रभावित करता है। यूएई के लिए, जिसकी अर्थव्यवस्था तेल निर्यात पर काफी हद तक निर्भर रही है, इस तरह के संकटों ने यह स्पष्ट कर दिया कि केवल सामूहिक निर्णयों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं है। ओपेक की सहमति-आधारित प्रणाली में किसी भी निर्णय तक पहुंचने में समय लगता है और कई बार राष्ट्रीय हित पीछे छूट जाते हैं। ऐसे में, तेजी से बदलते हालात में स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की जरूरत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

हालांकि, इस निर्णय को केवल युद्ध या सुरक्षा चिंताओं से जोड़कर देखना अधूरा होगा। इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक दृष्टिकोण भी काम कर रहा है। संयुक्त अरब अमीरात लंबे समय से अपनी अर्थव्यवस्था को तेल पर निर्भरता से बाहर निकालकर एक ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की दिशा में काम कर रहा है। तकनीक, शिक्षा, पर्यटन और वित्त जैसे क्षेत्रों में निवेश इस रणनीति का हिस्सा है। लेकिन इस परिवर्तन को संभव बनाने के लिए उसे वर्तमान में अधिक राजस्व की आवश्यकता है, और इसके लिए तेल उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। यही वह बिंदु है, जहां ओपेक की उत्पादन सीमाएं बाधा बनती हैं। यूएई ने अपनी तेल उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए भारी निवेश किया है, पर ओपेक के नियमों के कारण वह अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा था। ऐसे में, संगठन से बाहर निकलना उसे अपनी उत्पादन नीति पर पूर्ण नियंत्रण देता है।

यह समस्या केवल यूएई तक सीमित नहीं है। ओपेक के भीतर लंबे समय से उत्पादन को लेकर असमानता और असंतोष रहा है। कुछ देश, जैसे इराक और कजाकिस्तान अक्सर निर्धारित सीमा से अधिक उत्पादन करते रहे हैं, जबकि अन्य देश नियमों का पालन करते हैं। इस असमानता ने संगठन के भीतर विश्वास को कमजोर किया और कई देशों को यह महसूस कराया है कि वे एक ऐसी व्यवस्था में बंधे हुए हैं, जो सभी के लिए समान रूप से काम नहीं कर रही। यूएई का बाहर निकलना इस असंतोष का परिणाम तो है ही, भविष्य में होने वाले संभावित बदलावों का संकेत भी है।

इतिहास बताता है कि ओपेक से बाहर निकलना कोई नई बात नहीं है। कतर, इक्वाडोर और अंगोला जैसे देश पहले ही संगठन छोड़ चुके हैं। लेकिन यूएई का महत्व और उसकी आर्थिक क्षमता इसे एक अलग स्तर पर ले जाती है। यह कदम अन्य देशों के लिए भी एक उदाहरण बन सकता है, खासकर उन देशों के लिए, जो अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा रहे हैं या अपनी आर्थिक नीतियों में बदलाव कर रहे हैं। संभावित रूप से ओपेक छोड़ने वाले देशों में नाइजीरिया का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। नाइजीरिया अब केवल कच्चा तेल निर्यात करने के बजाय देश में ही तेल को परिष्कृत करने पर ध्यान दे रहा है। डांगोटे रिफाइनरी जैसे प्रोजेक्ट इस बदलाव का प्रतीक हैं। इससे नाइजीरिया को वैश्विक बाजार पर कम निर्भर रहना पड़ेगा और वह अपने तेल से अधिक मूल्य प्राप्त कर सकेगा। इसी तरह कजाकिस्तान भी संगठन से बाहर निकलने पर विचार कर सकता है। वेनेजुएला भी एक संभावित उम्मीदवार है, जहां उत्पादन में सुधार और राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव उसे अधिक स्वतंत्र नीति अपनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। अगर ऐसे और देश ओपेक से बाहर निकलते हैं, तो इसका वैश्विक तेल बाजार पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।

ओपेक की ताकत उसकी सामूहिकता में निहित है। अगर यह सामूहिकता कमजोर होती है, तो कीमतों को नियंत्रित करने की संगठन की क्षमता घटेगी। इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और तेल की कीमतों में गिरावट आ सकती है। अल्पकाल में यह तेल आयातक देशों के लिए लाभकारी हो सकता है। भारत जैसे देश, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर हैं, को इससे राहत मिल सकती है। कम कीमतों का मतलब है कम आयात बिल और महंगाई पर नियंत्रण। पर, दीर्घकालिक प्रभाव इतने सरल नहीं हैं। ओपेक की भूमिका केवल कीमतों को नियंत्रित करने तक सीमित नहीं रही है, बल्कि उसने बाजार को स्थिर रखने में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यदि संगठन कमजोर होता है, तो बाजार में अस्थिरता बढ़ सकती है। कीमतों में उतार-चढ़ाव हो सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। ऐसे में, भारत जैसे देशों के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण हो सकती है, क्योंकि उन्हें न केवल सस्ते तेल की जरूरत है, बल्कि स्थिर आपूर्ति और पूर्वानुमेय कीमतों की भी आवश्यकता है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि ओपेक पूरी तरह खत्म नहीं होगा। इसने अतीत में कई संकटों का सामना करने के बाद भी अपनी प्रासंगिकता बनाए रखी है। कोविड-19 महामारी के दौरान, जब तेल की मांग में भारी गिरावट आई थी, ओपेक और उसके सहयोगी देशों ने मिलकर उत्पादन में कटौती की तथा बाजार को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भविष्य में, सऊदी अरब जैसे प्रमुख देश संगठन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यूएई का यह निर्णय एक बड़े बदलाव का संकेत है, जहां देश अब सामूहिक हितों के बजाय अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दे रहे हैं। ऊर्जा क्षेत्र में हो रहे तकनीकी विकास, नवीकरणीय ऊर्जा की बढ़ती मांग और वैश्विक आर्थिक परिवर्तनों ने इस बदलाव को और तेज कर दिया है। आने वाले वक्त में तेल का महत्व बना रहेगा, पर इसकी भूमिका और इसे नियंत्रित करने के तरीके बदल सकते हैं।

अंततः, यह निर्णय केवल एक देश का नहीं, बल्कि एक युग के अंत और नए युग की शुरुआत का संकेत है। यह दिखाता है कि वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था अब पहले जैसी नहीं रही और आने वाले समय में अधिक प्रतिस्पर्धी, लचीली और अनिश्चित हो सकती है। यूएई ने इस बदलाव को अपनाने का फैसला किया है, और अब यह देखना बाकी है कि अन्य देश इस दिशा में कब और कैसे कदम बढ़ाते हैं।

edit@amarujala.com

मजदूरों का दिन

कानून से बढ़कर भरोसे की जरूरत

श्रम कानूनों और योजनाओं के बावजूद, भारत के असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक आज भी न्यूनतम वेतन, भरोसे और सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों से वंचित हैं।

ऋतुपर्ण दवे

श्रमिक दिवस के मूल में मजदूरों की आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा निहित है। 1884 में अमेरिका व कनाडा की ट्रेड यूनियनों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ट्रेड्स एंड लेबर यूनियन के आह्वान पर सुनिश्चित हुआ कि एक मई, 1886 के बाद कोई भी श्रमिक आठ घंटे से ज्यादा काम नहीं करेगा। 1889 के जुलाई महीने में यूरोप में 'इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ सोशलिस्ट पार्टीज' ने एक मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस (मई दिवस) के रूप में मनाने की घोषणा की। एक मई, 1890 को पहली बार मनाए गए मई दिवस को अब 80 से ज्यादा देशों में सार्वजनिक अवकाश के रूप में मनाया जाता है।

भारत में इस दिन को मनाने की शुरुआत चेन्नई में एक मई, 1923 को हुई। श्रमिक हितों को लेकर अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) की स्थापना भी वर्ष 1919 में हुई, जो कि संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है। भारत में श्रमिकों की बेहतरी के लिए काफी काम किए गए, फिर भी अपेक्षित उपलब्धि नहीं मिल सकी है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि देश के कुल श्रमिकों में से 93 फीसदी अब भी असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं। इसके मायने कि अब भी उनके लिए न्यूनतम वेतन व सामाजिक सुरक्षा के हक के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है। भारत में करोड़ों शहरी असंगठित श्रमिक और खेतिहर कामगार हैं, जो किसी भी कानून के दायरे में नहीं आते। इनके लिए भी एक केंद्रीय कानून की जरूरत है। यह विडंबना ही कही जाएगी कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 जैसे कानून के बावजूद, कई क्षेत्रों में अब भी शोषणकारी और दमनकारी परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। कमोबेश महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर, यानी एफएलएफपीआर 37 प्रतिशत तो है, पर चिंताजनक यह है कि इसका बड़ा हिस्सा अवैतनिक सहायक के रूप में है। सरकार ने 'अटल बीमा योजना' और सामाजिक सुरक्षा कोड के जरिये सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के प्रयास किए हैं। इसके बावजूद, अब भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना शेष है। कार्यदशा संहिता 2020 में 13 श्रम कानूनों को एकीकृत किया गया। इससे कार्यस्थल पर अच्छा माहौल बना। हालांकि, महिला कामगारों की सुरक्षा, गरिमा, समानता और आर्थिक सशक्तीकरण के मौलिक अधिकारों के लिए प्रेरणा और जागरूकता की दरकार है। संविधान के अनुच्छेद 14-15 में अधिकार भी मिला है, फिर भी एक सुरक्षित और भरोसेमंद माहौल की आवश्यकता व भरोसा जरूरी है। शी-बॉक्स पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत प्रणाली व्यवस्था को और सुरक्षित करती है। श्रमिकों को सशक्त बनाने के लिए, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) शुरू हुआ, ताकि भविष्य निधि को एक नौकरी से दूसरी नौकरी में ले जाया जा सके। श्रम निरीक्षकों की भूमिका बदली गई और उन्हें सलाहकार व सुविधादाता बनाया गया, जिससे शोषणकारी निरीक्षक राज खत्म हुआ। उद्योग रिटर्न को पारदर्शी व आसान तरीके से जमा करने के लिए श्रम सुविधा पोर्टल शुरू हुआ।

एम्स्टर्डम स्थित परामर्श फर्म आर्केडिस के अनुसार, भारतीय कर्मचारी औसतन प्रतिवर्ष 2,195 घंटे काम करते हैं, जबकि जर्मनी के हैम्बर्ग जैसे शहरों में यह औसत 1,473 घंटे है। एक भारतीय कर्मचारी 700 से अधिक घंटे काम करता है। स्पष्ट है कि श्रमिकों के लिए काफी कुछ किया जाना बाकी है, जिसके मूल में उत्पादकता से अधिक मानवता को प्राथमिकता देनी होगी। श्रमिक दिवस की मूल भावना के लिए ऐसे भागीरथ प्रयास जरूरी हैं।

नई उड़ान भरने का समय

बुजुर्ग अपने अनुभवों के आधार पर एक अनोखी आध्यात्मिक यात्रा रचते हैं, जो तब महसूस होती है, जब हम गहराई से जीते हैं और बिना दिखावे के अपने भीतर उतरते हैं। दरअसल, वृद्धावस्था एक नई उड़ान है, जहां आत्मा पंख फैलाकर ऊंचाइयों की ओर बढ़ती है।

थॉमस मूर

मुड़-मुड़ के देख

बढ़ती उम्र केवल शरीर का बदलना नहीं है, यह भीतर की दुनिया के धीरे-धीरे खुलने की प्रक्रिया भी है। जैसे-जैसे हम जीवन के लंबे सफर को पीछे मुड़कर देखते हैं, वैसे-वैसे बाहरी उपलब्धियों का आकर्षण कम होने लगता है और भीतर की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। इस पड़ाव पर पहुंचकर गैर-जरूरी चीजों के पीछे भागना व दुनिया में अपनी जगह तय करने की होड़ धीमी पड़ जाती है, और उसकी जगह लेती है-शांति, चिंतन और आत्मिक खोज।

जीवन के इस पड़ाव पर व्यक्ति स्वाभाविक रूप से उन प्रश्नों की ओर आकर्षित होता है, जो पहले कभी समय के अभाव या व्यस्तता के कारण अनदेखे रह गए थे। 'मैं कौन हूं?', 'मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है?', जैसे प्रश्न मन में गहराई से उठने लगते हैं। यह वह समय होता है, जब व्यक्ति बाहरी दुनिया से थोड़ा हटकर अपनी आत्मा के करीब आता है। जब जीवन की रफ्तार धीमी होती है, तब हम उन बातों को महसूस कर पाते हैं, जो पहले अनदेखी रह गई थीं। यह वह समय होता है, जब व्यक्ति भीतर से मजबूत बनता है, अपनी आत्मा को समझता है और जीवन के रहस्यों को स्वीकार कर सकता है।

कई बुजुर्ग धार्मिक मार्गों पर चलते रहते हैं, और उनमें उन्हें सुकून मिलता है। यह उनके लिए केवल परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का सहारा होता है। इसलिए परिवार और देखभाल करने वालों के लिए यह समझना जरूरी है कि उनकी आस्था का सम्मान करना, उन्हें मानसिक और भावनात्मक शक्ति देता है। बुजुर्ग केवल परंपराओं तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उन्होंने जीवन में खोज की है, प्रयोग किए हैं। उनके लिए आध्यात्मिकता प्रकृति, कला, सेवा, ध्यान और योग में भी मिलती है। वे अपने अनुभवों के आधार पर एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा रचते हैं, जो उनके लिए व्यक्तिगत और सजीव होती है। सच्ची आध्यात्मिकता जीवन से अलग नहीं होती, बल्कि हर अनुभव में मौजूद होती है। यह तब महसूस होती है, जब हम गहराई से जीते हैं, जब हम बिना किसी दिखावे के अपने भीतर उतरते हैं। दरअसल, वृद्धावस्था एक नई उड़ान है, जहां आत्मा अपने पंख फैलाए ऊंचाइयों की ओर बढ़ती है।

इस उम्र में अक्सर ऐसा होता है

अपनी मां की भूलने की समस्या से चिंतित बरेली के अवधेश को मनोवैज्ञानिक नीलकंठ ने कुछ यों सलाह दी :

मेरी मां चीजें भूलने लगी हैं, जो उम्र बढ़ने पर स्वाभाविक है। वह घर पर अकेली होती हैं। ऐसे में, मैं उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करूं?

यह वाकई गंभीर चिंता की बात है। जिन बुजुर्गों पर हमने अपनी पूरी जिंदगी भरोसा किया है, उन्हें इस तरह बेबस और असहाय हालत में देखना बहुत ही दुखी और परेशान करने वाला होता है। उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त कमजोर होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह उम्र बढ़ने के साथ होने वाले संज्ञानात्मक परिवर्तनों का उदाहरण है। विशेष रूप से ताजा बातें याद नहीं रहना कुछ ज्यादा ही गंभीर और चिंताजनक है। लेकिन अपने मस्तिष्क को स्वस्थ और उच्च कार्यक्षमता वाला बनाए रखा जा सकता है।

भूलने की आदत हर इन्सान में अलग-अलग होती है। याददाश्त का कमजोर होना डिमेंशिया या यहां तक कि डिप्रेशन (अवसाद) का भी शुरुआती संकेत हो सकता है। माता जी को जीवनशैली में बदलाव लाने, मानसिक रूप से सक्रिय रहने, नियमित व्यायाम (सप्ताह में 150 मिनट) करने और पौष्टिक आहार (फल, मेवे आदि) लेने के लिए प्रेरित करें। मस्तिष्क को व्यस्त रखने के लिए पहेलियां सुलझाना, नई चीजें सीखना और नियमित सामाजिक मेलजोल बढ़ाना लाभप्रद हो सकता है। उन्हें पर्याप्त नींद (7-8 घंटे) लेने के लिए कहें और तनावमुक्त रहने के लिए योगाभ्यास करने की सलाह दें।

घर पर अकेली रहने वाली अपनी मां की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आप कुछ खास सावधानीपूर्ण कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले आप कोई ऐसा देखभाल करने वाला व्यक्ति (केयरटेकर) खोजें, जो हमेशा उनके साथ रह सके, ताकि वह पूरे दिन घर पर अकेली न रहें। लेकिन देखभाल करने के लिए केयरटेकर रखना भी आजकल चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसलिए, देखभाल करने वाले व्यक्ति को किसी जाने-माने सुविधा केंद्र से या उचित पुलिस सत्यापन के बाद ही रखना चाहिए। अगर, कोई परिचित एवं भरोसेमंद व्यक्ति उनकी देखभाल करने के लिए साथ में रह सके, तो और बेहतर होगा।

दूसरा, रसोई का दरवाजा बंद रखें, या हो सके तो उसमें ताला लगा दें। असल में, अपनी मां को रसोई का इस्तेमाल न या तब करने के लिए कहें, जब कोई व्यक्ति उनके साथ हो। अगर वह खाना बनाने की जिद करती हैं, तो देखभाल करने वाले व्यक्ति को उन पर नजर रखने के लिए हिदायत दे दें। याददाश्त की कमी दैनिक कार्यों में भी बाधा डालती है, लोग जगहें भूलने लगते हैं, या भ्रम की स्थिति बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में योग्य चिकित्सक की सलाह जरूरी है।

माता जी की याददाश्त कमजोर होने के मामले में भी किसी जनरल फिजिशियन (योग्य चिकित्सक) से सलाह लेना बेहतर होगा। जनरल फिजिशियन को ही तय करने दें कि माता जी को किसी न्यूरोलॉजिस्ट से जांच करवाने की जरूरत है या नहीं।

हो सकता है डॉक्टर ऐसा करने का सुझाव दें, क्योंकि कुछ मामलों में, याददाश्त कमजोर होने की वजह जानने के लिए मस्तिष्क की एमआरआई जांच करवाने की सलाह दी जाती है।

*जिंदगी की **दूसरी पारी** बहुत महत्वपूर्ण होती है। हर शुक्रवार इस पर आपको नया पढ़ने को मिलेगा। आप अपने विचार, अनुभव या समस्याएं edit@amarujala.com पर भेज सकते हैं, विशेषज्ञों की मदद से हम कोशिश करेंगे कि संवाद का पुल बन सके।*

102 वर्ष की उम्र और पॉटरी का जुनून

अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाले जॉर्ज स्ट्रॉसमैन 102 वर्ष के हैं, लेकिन उनकी दिनचर्या किसी युवा से कम नहीं है। 90 साल की उम्र तक टेनिस खेलने वाले जॉर्ज पिछले 10 वर्षों से मिट्टी के नए-नए बर्तन बनाने की कला, यानी पॉटरी सीख रहे हैं।

आज भी वह हर हफ्ते क्लास जाते हैं, नए डिजाइन बनाते हैं और हर बार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जॉर्ज न केवल कला में सक्रिय हैं, बल्कि अपने घरेलू व्यवसाय में सप्ताह के चार दिन सक्रिय रूप से काम भी करते हैं। मिट्टी को आकार देते समय वह केवल बर्तन नहीं बनाते, बल्कि यह साबित करते है कि इन्सान का मन कभी वृद्ध नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि इस उम्र में भी उनका मानसिक और शारीरिक संतुलन बेहद मजबूत है। उनका मानना है कि रिटायरमेंट दिमाग की एक स्थिति है; जब तक शरीर और मन साथ दे रहे हैं, तब तक सक्रिय रहना ही जीवन है। सादगी और निरंतर चलते रहने को वह लंबी उम्र का राज बताते हैं।

वरिष्ठ नागरिकों के काम की संस्थाएं

- *ज्ञान दृष्टि फाउंडेशन एनजीओ* बुजुर्गों, महिलाओं और कमजोर वर्ग के लोगों के बेहतर भविष्य से जुड़े कार्यों में संलग्न है। यह भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी अभियान चलाकर एक खुशहाल भारत के सपने को साकार करने की दिशा में तत्पर है। एनजीओ लोगों को फिट रहने के लिए समय-समय पर मैराथन, जुम्बा, एरोबिक्स और डांस प्रतियोगिताओं के माध्यम से प्रेरित करती है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट gdfngo.org.in या Help@gdfngo.org.in पर ई-मेल कर सकते है।
- *एक कदम जिंदगी की ओर* संस्था विशेष रूप से बुजुर्गों व समाज के गरीब तबके के लोगों को सहायता प्रदान करके उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त बनाने का काम करती है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम भी किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.ekkadamzindagikiaur.org.in या ekkadamzindagikiaur@gmail.com पर ई-मेल के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है।

अमेरिका-ईरान संघर्ष बढ़ने की आशंका से 126 डॉलर के पार पहुंच गया था तेल

युद्ध ठंडा फिर भी उबाल मार रहा क्रूड चार साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। ईरान युद्ध जब चरम पर था, तब क्रूड ने इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाई थी। अब जब बातचीत की कोशिशें दिख रही हैं और युद्ध की रफ्तार धीमी हुई है, तब ब्रेंट क्रूड उछलकर चार साल के उच्च स्तर 126 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया। यह विरोधाभास नहीं है। तेल बाजार युद्ध की आवाज नहीं, आपूर्ति की सांस सुनता है।

दरअसल, एक्सिओस की एक रिपोर्ट आने के बाद बृहस्पतिवार को कारोबार के दौरान ब्रेंट क्रूड 126.41 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया, जो 9 मार्च, 2022 के बाद इसका उच्चतम स्तर है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बृहस्पतिवार को ईरान पर सैन्य हमलों की एक श्रृंखला की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जानी है। ऐसा इस उम्मीद में किया जा रहा है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए वापस लौट आएगा। ऊर्जा विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका के इस रुख से संघर्ष और बढ़ सकता है, जिससे क्रूड आपूर्ति में लंबे समय तक रुकावट आ सकती है।

बाद में बिना किसी स्पष्ट कारण के ब्रेंट क्रूड में गिरावट आई और कीमतें 3.5 फीसदी गिरकर 113.89 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गईं। तेल ब्रोकर पीवीएम के तमास वर्गा ने कहा, क्रूड में यह गिरावट किसी खास घटना से जुड़ी नहीं लगती, बल्कि ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से बाजार में बढ़ी अस्थिरता को दर्शाती है। यह बस ट्रंप की दुनिया में ट्रेडिंग के अप्रत्याशित स्वभाव को संक्षेप में बताती है।

डर ही नहीं बैरल भी कम

बाजार में सिर्फ डर नहीं, असल में बैरल भी कम हैं। आईईए के आंकड़े बताते हैं, मार्च में वैश्विक तेल भंडार 8.5 करोड़ बैरल घटा है। खाड़ी के बाहर भंडार में 20.5 करोड़ बैरल की गिरावट आई। समुद्र में चल रहा तेल भी घटा है। ऑयल ऑन वाटर 10.7 करोड़ बैरल कम हुआ, क्योंकि होर्मुज के बंद होने से ट्रांजिट में मौजूद तेल 18.1 करोड़ बैरल घट गया।

उबाल की असली वजह होर्मुज

तेल में उबाल की असल वजह है होर्मुज। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मुताबिक, युद्ध से पहले होर्मुज से रोज 2 करोड़ बैरल से ज्यादा कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और रिफाइंड उत्पाद निकलते थे। अप्रैल के शुरू में यह घटकर सिर्फ 38 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया। वैकल्पिक रास्तों से निर्यात जरूर बढ़कर 72 लाख बैरल प्रतिदिन पहुंचा, लेकिन कुल निर्यात नुकसान अब भी 1.3 करोड़ बैरल प्रतिदिन से ज्यादा है।

■ **केडिया कमोडिटी के प्रमुख अजय केडिया कहते हैं,** यही वह आंकड़ा है, जिसने बाजार को बेचैन किया है। युद्ध रुक भी जाए, तो जहाज तुरंत नहीं चलेंगे। बीमा, रूट, बंदरगाह, लोडिंग और रिफाइनरी आपूर्ति को सामान्य होने में समय लगेगा। यही बात तेल के बाजार को परेशान कर रही है।

आपूर्ति का प्रभावित होना भी बड़ी वजह

अर्थवृक्ष फाइनेंशियल सर्विसेज के संस्थापक रविंद्र राव ने बताया, आपूर्ति प्रभावित होने से भी क्रूड में मजबूती दिख रही है। उनका कहना है कि ट्रंप ने साफ कहा है कि जब तक ईरान परमाणु समझौता नहीं करता, जब तक उस पर नाकेबंदी जारी रहेगी, जिससे तेल आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित हो रही है।

■ *जब बाजार को पता है कि तेल अभी नहीं मिल रहा, तो जो कॉन्ट्रैक्ट आज डिलीवरी का है, वो सबसे ज्यादा महंगा हो जाता है। रिफाइनरी और ट्रेडर्स किसी भी दाम पर खरीदने को तैयार हो जाते हैं।*

खाने का तेल होगा महंगा, बिगाड़ सकता है रसोई का बजट

उच्च आयात लागत, कमजोर रुपये और घरेलू तिलहनों की मजबूत कीमतों से कंपनियों के मार्जिन पर असर

नई दिल्ली। खाद्य तेल की कीमतें एक बार फिर आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ सकती हैं। इसकी वजह यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों के दाम तेजी से बढ़े हैं, लेकिन भारतीय खुदरा बाजार में कीमतें उसी अनुपात में नहीं बढ़ी हैं। यानी कंपनियों ने अब तक बढ़ी हुई लागत का पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाला है। अब ऊंची आयात लागत, महंगी ढुलाई, रुपये की कमजोरी और घरेलू तिलहनों की मजबूत कीमतों ने उनके मार्जिन पर दबाव बढ़ा दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में खाद्य तेल कंपनियां फिर दाम बढ़ाने की तैयारी कर सकती हैं। उद्योग सूत्रों के मुताबिक, खाद्य तेलों की कीमतों में 5-6 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इससे पहले मार्च में अमेरिका-ईरान युद्ध से पैदा हुए संकट के बाद कंपनियों ने थोक कीमतों में 3-5 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। उसके बाद पाम तेल की खुदरा कीमतों में 10-12 रुपये प्रति लीटर तक का इजाफा देखा गया था। ■ टीम बोनस

एक साल में 17.30 फीसदी तक बढ़े दाम

तेल/कीमत	31, मार्च 2026	31 मार्च 2025	वृद्धि फीसदी में
क्रूड पाम	1,241	1,184	4.81
क्रूड सोयाबीन	1,286	1,097	17.23
क्रूड सूरजमुखी	1,431	1,220	17.30

(सोर्स : एसईए, कीमत : डॉलर प्रति टन में)

■ ***कई वजहों से बढ़ रहा दबाव :*** *महंगाई का यह दूसरा दौर कई कारणों से बन रहा है। पश्चिम एशिया और लाल सागर में तनाव के चलते जहाज भाड़ा बढ़ गया है। समुद्री रास्तों में बाधा से आपूर्ति शृंखला पर असर पड़ा है। कई देश खाद्य तेल सुरक्षा मजबूत करने के लिए अपने-अपने भंडार में बढ़ोतरी कर रहे हैं। इससे खाद्य तेल की वैश्विक कीमतों को और सहारा मिल रहा है।*

इसलिए भी बढ़ी कंपनियों की मुश्किल

कच्चे तेल की तेजी ने भी खाद्य तेल कंपनियों की मुश्किल बढ़ाई है। कच्चा तेल महंगा होने से पेट्रोल-डीजल महंगा होता है और कई देश पाम तेल का इस्तेमाल बायोडीजल बनाने में बढ़ा देते हैं। इससे पाम तेल की उपलब्धता घटती है और कीमतों पर दबाव बढ़ता है।

■ भारत खाद्य तेल जरूरतों का 57 फीसदी आयात करता है। देश में पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी तेल कुल 2.5-2.6 करोड़ टन खपत का बड़ा हिस्सा हैं। एक साल में पाम ऑयल की लैंडेड लागत 14 फीसदी, सोयाबीन तेल की 20% और सूरजमुखी तेल की 17% बढ़ी है।

■ अंतरराष्ट्रीय और घरेलू खुदरा कीमतों के बीच अंतर बढ़ रहा है। क्रूड सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के अंतरराष्ट्रीय भाव 17 फीसदी से ज्यादा बढ़े हैं, जबकि घरेलू बाजार में सूरजमुखी तेल में 7 फीसदी की बढ़ोतरी दिखी। यही अंतर कीमत बढ़ने का कारण बन सकता है।

तेल में उछाल और पूंजी निकासी से रुपये पर दबाव

कारोबार के दौरान 95.34 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा रुपया

नई दिल्ली। रुपया एक बार फिर दबाव में है। बृहस्पतिवार को कारोबार के दौरान डॉलर के मुकाबले रुपया टूटकर 95.34 के रिकॉर्ड निचले स्तर तक पहुंच गया। हालांकि, बाद में रिजर्व बैंक के दखल से यह संभला और चार पैसे की बढ़त के साथ 94.84 के स्तर पर बंद हुआ।

दरअसल, रुपये पर सबसे बड़ा दबाव कच्चे तेल से आ रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव और होर्मुज खुलने को लेकर अनिश्चितता के कारण कच्चा तेल 126 डॉलर प्रति बैरल के ऊपर चला गया था। भारत तेल का बड़ा आयातक है। इसलिए तेल महंगा होता है तो डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपया कमजोर पड़ता है। दूसरा दबाव विदेशी निवेशकों की बिकवाली से पड़ रहा है। 2026 में अब तक विदेशी निवेशक भारतीय बाजारों से 19.46 अरब डॉलर निकाल चुके हैं। यह पूरे 2025 के आउटफ्लो से भी ज्यादा है। राहत यह रही कि आरबीआई ने बाजार में डॉलर बेचकर रुपये को 95 के ऊपर बंद नहीं होने दिया। निर्यातकों ने भी ऊंचे स्तर पर डॉलर बेचे, जिससे थोड़ी मदद मिली। आगे रुपये की चाल तेल की कीमतों और डॉलर इंडेक्स पर निर्भर करेगी। ■ टीम बोनस

सोने की कीमत 2,000 रुपये बढ़ी, चांदी में 1,800 गिरावट

नई दिल्ली। मजबूत वैश्विक संकेतों और अमेरिकी डॉलर में कमजोरी से बृहस्पतिवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 2,000 रुपये महंगा होकर 1,54,800 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बंद हुआ। हालांकि, चांदी की कीमतों में 1,800 रुपये की गिरावट आई और यह 2,42,700 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव बंद हुई। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना 91.80 डॉलर की बढ़त के साथ 4,635.52 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया। एजेंसी

न्यूज डायरी

सेंसेक्स 583 अंक टूटा 5.33 लाख करोड़ डूबे

नई दिल्ली। कच्चे तेल में उबाल, कमजोर वैश्विक रुख और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से घरेलू शेयर बाजार बृहस्पतिवार को गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स 582.86 अंक टूटकर 76,913.50 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 1,237.5 अंक तक लुढ़क गया था, लेकिन दोपहर के सत्र में कुछ संभल गया। निफ्टी 180.10 अंक की गिरावट के साथ 23,997.55 पर बंद हुआ। सूचीबद्ध कंपनियों की पूंजी 5.33 लाख करोड़ घटकर 463.29 लाख करोड़ रह गई। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयर गिरावट में बंद हुए। ब्यूरो

अदाणी इंटरप्राइजेज को 17 तिमाही में पहली बार घाटा

नई दिल्ली। गौतम अदाणी के नेतृत्व वाले समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी इंटरप्राइजेज ने 17 तिमाहियों में पहली बार घाटा दर्ज किया है। इसका मुख्य कारण नवी मुंबई एयरपोर्ट जैसी नई परियोजनाओं में नुकसान और लागत में तेज उछाल रहा। जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी को 221 करोड़ रुपये का घाटा हुआ, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में उसे 3,845 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। पूरे वित्त वर्ष में कंपनी का शुद्ध लाभ 31 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 9,339 करोड़ हो गया। एजेंसी

वोडा आइडिया को राहत, एजीआर बकाया देनदारी में 27 फीसदी कटौती

नई दिल्ली। सरकार ने कर्ज में फंसी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया को राहत देते हुए उसके समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) बकाये में करीब 27 फीसदी की कटौती कर दी है। इससे उसकी देनदारी कम होकर 64,046 करोड़ रुपये रह गई है।

कंपनी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, दूरसंचार विभाग ने 30 अप्रैल, 2026 को सूचित किया है कि इस उद्देश्य के लिए गठित समिति ने 31 दिसंबर, 2025 तक एजीआर बकाये को 64,046 करोड़ रुपये पर अंतिम रूप दे दिया है। इससे पहले दूरसंचार विभाग ने 31 दिसंबर, 2025 तक एजीआर देनदारी 87,695 करोड़ रुपये तय की थी। हालांकि, इस देनदारी को बाद में पुनर्मूल्यांकन के अधीन रखा गया था।

नियामकीय सूचना के मुताबिक, वोडाफोन आइडिया को अंतिम बकाया राशि कुल 10 वर्षों की अवधि में दो चरणों में चुकानी होगी। इसके तहत वित्त वर्ष 2031-32 से 2034-35 तक चार वर्षों में हर साल न्यूनतम 100 करोड़ रुपये का भुगतान करना होगा। शेष बकाया राशि का भुगतान कंपनी को वित्त वर्ष 2035-36 से 2040-41 के बीच छह समान वार्षिक किस्तों में करना होगा। एजेंसी

एचयूएल बढ़ाएगी चुनिंदा उत्पादों के दाम, लाभ 21%बढ़ा

नई दिल्ली। एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) बढ़ती लागत के दबाव से निपटने के लिए चुनिंदा उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी करेगी। कंपनी की सीईओ-एमडी प्रिया नायर ने बृहस्पतिवार को कहा, कच्चे माल और क्रूड से जुड़े पैकेजिंग खर्च में बढ़ोतरी से लागत दबाव बना हुआ है।

उधर, कंपनी का शुद्ध लाभ वित्त वर्ष 2025-26 की मार्च तिमाही में 21 फीसदी वृद्धि के साथ 2,994 करोड़ पहुंच गया। कुल आय करीब पांच फीसदी बढ़कर 16,580 करोड़ रुपये हो गई। यह पिछले 12 तिमाहियों में सबसे तेज बढ़ोतरी है। एजेंसी

सुधारों के दम पर 90 अरब डॉलर के पार पहुंचेगा एफडीआई

डीपीआईआईटी सचिव ने कहा, तेज आर्थिक वृद्धि से भारत पर विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत

नई दिल्ली। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 90 अरब डॉलर के पार पहुंच सकता है। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने कहा, अप्रैल, 2025 से फरवरी, 2026 के दौरान देश में कुल 88 अरब डॉलर से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आया है। इससे पूरे वित्त वर्ष के लिए सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। इस अवधि में देश में शुद्ध एफडीआई बढ़कर 6.26 अरब डॉलर हो गया है, जबकि 2024-25 में यह 80.61 अरब डॉलर था। भाटिया ने कहा, सरकार की ओर से निवेश आकर्षित करने के लिए किए गए नीतिगत सुधारों, विभिन्न देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों और तेज आर्थिक वृद्धि ने भारत पर विदेशी निवेशकों का भरोसा मजबूत किया है। इन कारकों के चलते भारत वैश्विक निवेश के लिए आकर्षक गंतव्य के रूप में उभरा है। ब्यूरो

इन्वेस्ट इंडिया से 6.1 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट

राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन एजेंसी इन्वेस्ट इंडिया ने 2025-26 में 6.1 अरब डॉलर से अधिक के 60 प्रोजेक्ट हासिल करने में मदद की है। ये निवेश 14 राज्यों में फैले हैं और इससे 31,000 से ज्यादा रोजगार सृजन की संभावना है। कुल निवेश का करीब 42 फीसदी यूरोपीय देशों से आया है, जबकि अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया से भी निवेश बढ़ा है।

एफडीआई नियमों में ढील पर जल्द आएगी अधिसूचना

सरकार चीनी कंपनियों में 10 फीसदी तक हिस्सेदारी रखने वाली विदेशी कंपनियों के लिए एफडीआई नियमों में ढील से जुड़े फैसले को जल्द अधिसूचित करेगी। अधिसूचना विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत जारी होगी। सरकार ने मार्च में प्रेस नोट-3 (2020) में संशोधन को मंजूरी दी थी। हालांकि, यह छूट चीन, हांगकांग या भारत से सटे अन्य देशों में पंजीकृत कंपनियों पर लागू नहीं होगी।

अमर उजाला **Job Alert**
Real-time job alerts
amarujala.com/jobs

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
असिस्टेंट फोरमैन व अन्य पदों पर रिक्तियां

1055 पद

आवेदन की अंतिम तिथि : 14 मई, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष
यहां आवेदन करें : secl-cil.in

बिहार तकनीकी सेवा आयोग ■ 726 पद
अनुदेशक के पदों पर निकली भर्ती
आवेदन की अंतिम तिथि : 15 मई, 2026
आयु-सीमा : न्यूनतम 18 वर्ष व अधिकतम उम्र 37 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : btsc.bihar.gov.in

एनटीपीसी में करें आवेदन ■ 250 पद
सहायक कार्यकारी के पदों पर निकली भर्ती
आवेदन की अंतिम तिथि : 07 मई, 2026
योग्यताएं : बीई, बीटेक व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : ntpc.co.in

राष्ट्रीय खनिज विकास निगम ■ 59 पद
जूनियर इंजीनियर के पद खाली
आवेदन की अंतिम तिथि : 06 मई, 2026
आयु-सीमा : अधिकतम आयु 50 वर्ष निर्धारित
यहां आवेदन करें : nmdc.co.in

आईजीआईएमएस में मौके ■ 18 पद
जूनियर रेजिडेंट के पदों पर निकली भर्ती
वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि : 06 मई, 2026
वेतनमान : रुपये 56,100 प्रतिमाह
यहां आवेदन करें : igims.org

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ■ 15 पद
असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पदों पर नौकरी के मौके
आवेदन की अंतिम तिथि : 17 मई, 2026
योग्यताएं : बीई/बीटेक/बीएससी व अन्य निर्धारित पात्रताएं
यहां आवेदन करें : centralbank.bank.in

आवेदन आमंत्रित...
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली : चेयर प्रोफेसर के पदों पर निकली भर्ती।
■ आवेदन की अंतिम तिथि : 17 मई, 2026
■ jnu.ac.in/career
गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड : महाप्रबंधक, प्रबंधक व अन्य पद खाली।
■ आवेदन की अंतिम तिथि : 07 मई, 2026
■ gmrl.org.in

अपनी प्रतिक्रियाओं और सुझावों के लिए हमें udaan@amarujala.com पर ई-मेल करें।

एजुकेशन & कॅरिअर

जिसने कभी कोई गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की।

सीखें भी, कमाएं भी

डीआरडीओ की यह इंटर्नशिप छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने के साथ उनके कॅरिअर को नई दिशा भी देगी

गौरव सचदेवा
कॅरिअर सलाहकार

प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान से शिक्षा व व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के इच्छुक छात्रों के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के अंतर्गत आने वाली प्रमुख प्रयोगशाला, सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज, हैदराबाद (सीएचईएसएस) की पेड इंटर्नशिप-2026 एक सुनहरा अवसर है। इस इंटर्नशिप के माध्यम से इंजीनियरिंग और विज्ञान के मेधावी छात्रों को न केवल ट्रेनिंग का अवसर मिलेगा, बल्कि उन्हें देश के रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में काम करने का भी अनुभव प्राप्त होगा। यह कार्यक्रम उन छात्रों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है, जो भविष्य में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उच्च शिक्षा या उन्नत तकनीकी क्षेत्रों में कॅरिअर बनाना चाहते हैं।

■ कौन कर सकता है आवेदन

इस इंटर्नशिप कार्यक्रम के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार का एआईसीटीई/यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग अथवा विज्ञान में स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक को अपने पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता की दृष्टि से भी छात्र का प्रदर्शन उत्कृष्ट होना चाहिए। उम्मीदवार के पिछले सेमेस्टर में न्यूनतम 75 प्रतिशत अंक या 10 के स्केल पर 7.5 सीजीपीए होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त, आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की अधिकतम आयु 28 वर्ष निर्धारित की गई है।

■ इंटर्नशिप की अवधि और लाभ

इंटर्नशिप प्रशिक्षण की कुल अवधि छह माह निर्धारित की गई है, जिसे हैदराबाद स्थित सीएचईएसएस में ऑफलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। चयनित छात्र यदि निर्धारित अवधि को सफलतापूर्वक पूरा करते हैं, तो उन्हें पूर्णता प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा। इसके साथ ही छात्रों को कुल 30,000 रुपये का स्टाइपेंड दो किस्तों में दिया जाएगा। हालांकि, स्टाइपेंड प्राप्त करने के लिए छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है और उन्हें प्रत्येक माह कम से कम 15 दिन उपस्थित रहना होगा।

■ आवेदन की प्रक्रिया

इच्छुक उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट drdo.gov.in/drdo/careers से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करें। इसके बाद फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेजों की सूची संलग्न करें। पूरा आवेदन पत्र स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना होगा। लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से "Application for Paid Internship" लिखना अनिवार्य है, साथ ही संबंधित "ब्रांच कोड" भी उल्लिखित करना होगा, जिससे आवेदन की छंटनी में सुविधा हो सके।

- *इंजीनियरिंग और विज्ञान के मेधावी छात्रों को मिलेगा ट्रेनिंग का मौका।*
- *इंटर्नशिप प्रोग्राम की अवधि छह माह निर्धारित की गई है।*
- *छात्रों को कुल 30,000 रुपये का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा।*

■ महत्वपूर्ण तिथियां

इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 11 मई, 2026 निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवारों को 20 मई, 2026 तक सूचित कर दिया जाएगा, जबकि इंटर्नशिप कार्यक्रम की शुरुआत 03 जून, 2026 से होगी।

फेलोशिप प्रोग्राम

डब्ल्यूएचएस स्टाइपेंड एंड फेलोशिप

- संस्थान : वेलकॉम ट्रस्ट
- पात्रताएं : निम्न या मध्यम आय वाले देश के नागरिक
- भाषा : अंग्रेजी
- लाभ : बर्लिन आने-जाने के लिए इकोनॉमी क्लास फ्लाइट की टिकट व अन्य लाभ
- आधिकारिक वेबसाइट : tinyurl.com/3sszc33t

आवेदन आमंत्रित

ग्लोबल पीस फोटो अवॉर्ड-2026

- संस्थान : एडिशन लैमरहुबर
- कौन हैं पात्र : दुनिया भर के सभी फोटोग्राफर
- 15 वर्ष से कम उम्र के आवेदक : चिल्ड्रन पीस इमेज ऑफ द ईयर कैटेगरी में फोटोसबमिट करें।
- 'पीस इमेज ऑफ द ईयर' पुरस्कार- 7,000 यूरो नकद
- कुल पुरस्कार राशि : 11,000 यूरो नकद
- आवेदन की अंतिम तिथि : 24 मई, 2026
- आधिकारिक वेबसाइट : tinyurl.com/2pc6e3bh

एग्जाम अलर्ट

जेएसएससी स्नातक शिक्षक परीक्षा

- परीक्षा की तिथि : 05-07 मई, 2026
- यह परीक्षा चार पत्रों के लिए आयोजित की जाएगी। प्रश्न-पत्र-I में मातृभाषा, प्रश्न-पत्र-II में प्रशासनिक सुधार आदि, प्रश्न-पत्र-III में सामान्य ज्ञान आदि व प्रश्न-पत्र-IV में वैकल्पिक विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे।
- यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें jssc.jharkhand.gov.in

आरएसएसबी लैब असिस्टेंट परीक्षा (भूगोल)

- परीक्षा की तिथि : 09 मई, 2026
- इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान से 100 अंकों के प्रश्न व भूगोल से 200 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यर्थी को तीन घंटे का समय दिया जाएगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक-तिहाई नकारात्मक अंकन किया जाएगा।
- यहां से प्रवेश-पत्र डाउनलोड करें rssb.rajasthan.gov.in

खुद को परखें

1. सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है?
   (a) अरुणाचल प्रदेश (b) असम
   (c) सिक्किम (d) मणिपुर
2. हाल ही में किस राज्य में यूलोफिया पिक्टा नामक एक दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति की खोज की गई थी?
   (a) केरल (b) कर्नाटक
   (c) महाराष्ट्र (d) आंध्र प्रदेश
3. सहयोग पोर्टल के लिए नोडल प्राधिकरण कौन-सा मंत्रालय है?
   (a) इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
   (b) गृह मंत्रालय
   (c) विधि और न्याय मंत्रालय
   (d) रक्षा मंत्रालय
4. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जाता है?
   (a) शिक्षा मंत्रालय
   (b) युवा मामले और खेल मंत्रालय
   (c) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
   (d) संस्कृति मंत्रालय

उत्तर : 1.a, 2.d, 3.b, 4.c

आज का दिन

01 मई, 1840

सर रोलैंड हिल द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला डाक टिकट इंग्लैंड में जारी किया गया था। यह पेनी ब्लैक के नाम से प्रचलित हुआ था।

- ■ 1897 : स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी।
- ■ 1924 : आयोडीन युक्त नमक की बिक्री सबसे पहले अमेरिका में शुरू हुई थी।
- ■ 1960 : बॉम्बे राज्य से अलग होकर महाराष्ट्र और गुजरात अलग राज्य बने थे।
- ■ 2009 : स्वीडन ने समलैंगिक विवाह को मंजूरी दी थी।

व्रत त्योहार

आज : वैशाख पूर्णिमा।
कल : ग्रीष्म ऋतु, सूर्य उत्तरायणे, उत्तर गोले।
राहुकाल : प्रातः 09.00 से 10.30 तक

■ सूर्योदय : 05.44
■ सूर्यास्त : 18.52
(भारतीय मानक समयानुसार)

कल का पंचांग

विक्रमी संवत 2083, 12 वैशाख मास शक 1948, वैशाख मास 19 प्रविष्टे, 14 जिल्काद हिजरी 1447, प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा 24.49 तक उपरांत द्वितीया, विशाखा नक्षत्र दिन रात, व्यतिपात योग 21.44 तक उपरांत वरियान योग, बालव करण 11.50 तक उपरांत कौलव करण, चंद्रमा वृश्चिक राशि में 24.30 बजे।

amarujala.com/astrology

राशिफल

■ पं. विनोद त्यागी

मेष : भाग्य सहायक रहेगा। नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी।

वृष : आरोग्य सुख में कमी रहेगी। नौकरी में वर्चस्व बना रहेगा। विरोधी से सावधानी बरतें।

मिथुन : मानसिक तनाव पर नियंत्रण रखें। नौकरी में सहकर्मियों से निराशा होगी। मित्र से भेंट संभव है।

कर्क : नए कार्य में व्यस्त रहेंगे। सरकारी क्षेत्र में सफलता मिलेगी। नौकरी में श्रम की अधिकता रहेगी।

सिंह : आत्मबल बना रहेगा। नौकरी में प्रमोशन के संकेत मिल सकते हैं। पूर्व नियोजित कार्य सफल होगा।

कन्या : मनोत्साह बना रहेगा। नौकरी में अधिकारी अनुकूल रहेंगे। व्यवसाय में लाभ के अवसर मिलेंगे।

तुला : सकारात्मक सोच बनाए रखें। नौकरी में कार्य भार बढ़ सकता है। विरोधी परास्त होंगे।

वृश्चिक : मानसिक अस्थिरता बनी रहेगी। नौकरी में जबाबदेही बढ़ेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

धनु : दिनमान सहायक रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलेगी। राजनीतिक क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा।

मकर : अटकी योजना सफल होगी। संतान से सुख मिलेगा। नौकरी में दबदबा बना रहेगा।

कुंभ : स्वजन सहयोग मिलेगा। नई नौकरी का अवसर मिल सकता है। परिवार में आनंद रहेगा।

मीन : दिनमान सामान्य रहेगा। नौकरी में सम्मान बना रहेगा। नए कार्य में पूंजी निवेश से बचें।

सुडोकू

	6				4			
							9	2
9		5			8		4	
7		9	1					
		2				5		
					2	7		9
	8		7			3		1
3	5							
			4				5	

1	6	3	9	2	4	8	7	5
4	7	8	5	3	1	6	9	2
9	2	5	6	7	8	1	4	3
7	3	9	1	6	5	4	2	8
8	4	2	3	9	7	5	1	6
5	1	6	8	4	2	7	3	9
2	8	4	7	5	9	3	6	1
3	5	7	2	1	6	9	8	4
6	9	1	4	8	3	2	5	7

उत्तर

सुडोकू 81 वर्गों का ग्रिड है, जो 9 वर्गों के ब्लॉक में बंटा हुआ होता है। कुछ वर्गों के अंक लिखे हैं और खाली वर्गों में 1 से लेकर 9 तक के अंक लिखने होते हैं। कोई नंबर 1 पंक्ति, कॉलम या 9 वर्ग वाले छोटे ब्लॉक में दोबारा नहीं आ सकता है।

आर्थिक आशंकाएं

भारतीय शेयर बाजार में गुरुवार को आई गिरावट चिंता और चिंतन की बात है। एक समय मुंबई शेयर बाजार का सूचकांक 1,200 अंक टूट गया था और ऐसा लगा था कि एक ही दिन में निवेशकों के नौ लाख करोड़ रुपये डूब जाएंगे, लेकिन बाद में कुछ सुधार हुआ। 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 583 अंक या 0.75% गिरकर 76,913.50 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 कुल 180 अंक या 0.74% गिरकर 23,997.55 पर बंद हुआ। गिरावट कुछ संभल गई, फिर भी गुरुवार निवेशकों को पांच लाख करोड़ रुपये की चोट दे गया। पहली नजर में इसकी वजह यह है कि हमारे शेयर बाजारों में जमकर बिकवाली हो रही है। मतलब, निवेशक अपने शेयर बेचकर निकल रहे हैं। आमतौर पर जब परिवेश निवेश के अनुकूल होता है, तब शेयर खरीद ज्यादा होती है और प्रतिकूल होते ही शेयर ब्रिकी बढ़ जाती है। खरीदते समय शेयर मूल्य बढ़ता है और बेचते समय घटता है।

वैसे, भारतीय शेयर बाजार में बढ़त और गिरावट का संतुलन बहुत हद तक कायम है। अप्रैल महीने को समग्रता में अगर देखें, तो सेंसेक्स और निफ्टी-50 में अप्रैल में क्रमशः 7 और 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिससे चार महीने से जारी गिरावट का सिलसिला टूटा है। 30 अप्रैल पर सबकी निगाह थी, अगर इस दिन बाजार न गिरा होता, तो यह बहुत सकारात्मक बात होती। बाजार से एक बेहतर संदेश जाता, पर लगता है, विदेशी निवेशकों ने साथ नहीं दिया।

भारतीय शेयर बाजार में बिकवाली की वजह से हुई भारी गिरावट बाद में कुछ संभल गई, फिर भी गुरुवार निवेशकों को पांच लाख करोड़ रुपये की चोट दे गया।

अमेरिकी टैरिफ के असर को तो हमने कमोबेश संभाल लिया है, मगर ईरान युद्ध से उपजे हालात पर हमारा ज्यादा वश नहीं चल रहा है। हमारे शेयर बाजार में ताजा गिरावट की यही सबसे बड़ी वजह है। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता अटक गई है। जैसे ही युद्ध-विराम की गुंजाइश बनती है, वैसे ही तनाव बढ़ाने वाली कोई खबर आ जाती है। अब अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरान से जुड़ी 344 मिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी को फ्रीज कर दिया है। ऐसे वित्तीय फैसले दुनिया में व्यापार या निवेश के माहौल को बिगाड़ते हैं। खैर, खराब माहौल की एक वजह कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भी हैं। अच्छी बात है कि अप्रैल महीने में कच्चे तेल की कीमत में करीब दो प्रतिशत की गिरावट आई है, मगर कीमत 115 डॉलर प्रति बैरल से नीचे नहीं आ रही है। तेल भारत की एक कमजोरी है, क्योंकि वह आयात पर निर्भर है। यह आशंका सतत बनी हुई है कि भारत में विकास दर घटेगी और महंगाई बढ़ेगी। कीमत बढ़ाने के लिए तेल कंपनियों का पूरा दबाव है, पर सरकार ने पेट्रोल, डीजल की कीमतों को किसी तरह से संभाल रखा है। हालांकि, अफसोस की बात है कि गैस सिलेंडर की आपूर्ति पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई है।

निर्यात के मोर्चे पर तनाव कायम है, तो रुपये में भी कमजोरी का क्रम बना हुआ है। गुरुवार को एक समय रुपया अपने रिकॉर्ड निचले स्तर 95.33 प्रति डॉलर पर पहुंच गया था, पर उसमें भी कुछ सुधार हुआ और कीमत 94.91 रुपये पर बंद हुई। शेयर बाजार में गिरावट से भी रुपया कमजोर पड़ रहा है। रुपये को बल देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ कदम उठाए थे, लेकिन अमेरिकी केंद्रीय बैंक के आक्रामक रुख की वजह से खास फायदा नहीं हुआ। इसका असर भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के शेयर बाजारों पर पड़ा है। भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य भारतीय वित्तीय नियामक संस्थाओं को बहुत सावधान व सक्रिय रहना चाहिए। हालात पर पूरी नजर रखने के साथ ही सुधार एवं विकास को बल देने के लिए नए-नए कदम उठाते रहने की जरूरत है।

बहुत सावधानी से बसाइए नए शहर

यहां स्कैन करें

के के पाण्डेय | नगर नियोजन विशेषज्ञ

मुंबई से दिल्ली और नोएडा तक जैसा व्यावसायिक माहौल दिखता है, वैसा ही बिहार में बन रहे 11 नए शहरों में न बन जाए, इसके लिए बहुत तैयारी से काम करना होगा।

हमारे शहर एक द्वैत को जीते हैं। एक तरफ, इनमें तमाम सहूलियतों से युक्त रिहायशी इलाके हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जहां बुनियादी सुविधाएं तक मयस्सर नहीं। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे तमाम महानगरों व बड़े शहरों का यही हाल है। इसी कारण, यहां तेज रफ्तार जिंदगी भी दिखती है, तो उस जीवन के कदम-कदम पर परीक्षा लेतीं कुव्यवस्थाएं भी। कभी-कभी इसकी कीमत इंसान अपनी जान देकर चुकाता है, जिसकी तस्दीक महानगरों से हर कुछ अंतराल पर 'मौत के गड्ढे' या 'मौत के नाले' शीर्षक खबरों से होती रहती है।

बिहार में 11 शहरों में 'सैटेलाइट टाउन' बनाने की नई घोषणा को भी हमें इसी नजर से परखना चाहिए। एक बात स्पष्ट है कि आर्थिक विकास व शहरीकरण, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी जब किसी क्षेत्र का शहरीकरण होता है, तो उसका आर्थिक विकास भी साथ-साथ चलता रहता है। ये 11 उप-नगर भी इस मामले में अपवाद साबित नहीं होंगे। गैर-कृषि क्षेत्रों में आर्थिक विकास के अनुरूप मैन्युफैक्चरिंग व सेवा क्षेत्र के यहां विकसित होने की पूरी संभावना है।

वास्तव में, इन शहरों से बिहार ही नहीं, पूरे देश को लाभ मिलेगा। मसलन, बिहार की प्रतिव्यक्ति आय अभी बेहद कम है और शहरीकरण के मामले में भी इसकी गिनती निर्धारित मानकों में निचले पायदानों पर होती है। यहां के शहरों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का स्तर भी काफी नीचे है और मैनहोल, सड़क, नाली, स्थानीय निकाय की आर्थिक स्थिति आदि तमाम मानकों में वे अब भी बहुत ऊपर नहीं आ सके हैं। ऐसे में, अगर यहां 'लैंड पूलिंग नीति' के अनुसार 11 ऐसे उप-नगर विकसित किए जा रहे हैं, जहां हाइटेक उद्योग स्थापित हो सकेंगे या सूचना-प्रौद्योगिकी, अनुसंधान व विकास, फार्मास्यूटिकल्स और फिनटेक (आर्थिक सेवाएं देने वाली संस्थाएं) से जुड़ी कंपनियां काम कर सकेंगी, तो लाभ यहां के बाशिंदों को भी होगा।

इन कंपनियों के लिए यहां आना आसान है, क्योंकि यहां न सिर्फ उनको कामकाज का अनुकूल माहौल मिल सकता है, बल्कि उन्हें बिहार की जनसांख्यिकी का लाभ भी मिल सकेगा। नतीजतन, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, दिल्ली, नोएडा आदि इलाकों में जिस तरह का व्यावसायिक माहौल है, उसमें बिहार भी शुमार हो सकता है। इससे यहां से श्रम का पलायन कुछ हद तक रुक सकता है।

ऐसा देश के तमाम राज्यों में किया जाना चाहिए। हालांकि, इसके साथ चुनौतियां भी कम नहीं हैं। जैसे- नए उप-नगर या शहर बसाने में सबसे बड़ी बाधा आती है भूमि अधिग्रहण करने में। अच्छी प्रक्रिया तो यही है कि इसे सहभागिता के आधार पर अंजाम दिया जाए। बुनियादी ढांचों को विकसित करने के बाद यदि भू-स्वामियों को विकास-कार्यों में भागीदार बनाया जाता है, तो उसका दोतरफा लाभ मिलता है। एक- व्यवस्था पर लोगों का भरोसा मजबूत होता है, और दूसरा- भूमि अधिग्रहण से होने वाला असंतोष कम हो जाता है।

बिहार इस तरह की सहभागिता को खासा महत्व दे रहा है। इन 11 उप-नगरों में बुनियादी ढांचों के विकास के बाद 55 प्रतिशत विकसित भूमि भू-स्वामियों को वापस कर दी जाएगी। भू-स्वामियों को लाभ में 'शेयर-होल्डर' बनने का फायदा भी मिलेगा। गौरतलब है कि गुजरात, महाराष्ट्र में यह नीति सफलतापूर्वक लागू की जा चुकी है। गुरुग्राम, नोएडा और नवी मुंबई में भी हम उप-नगर बनाने की नीति के लाभ देख चुके हैं। इसे बनाते समय गुजरात, नोएडा और गुरुग्राम के अनुभवों से भी सीख लेनी चाहिए, ताकि योजना का तेजी से अनुपालन हो।

इसमें दोराय नहीं कि शहरों के सुनियोजित विकास और आर्थिक गतिविधियों के नए केंद्रों के निर्माण से राज्य की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक बदलाव आता है। इनसे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। दरअसल, कोई भी नगर अपने-आप रोजगार पैदा नहीं करता, वहां इस बाबत माहौल बनाना पड़ता है। हाईटेक शहरों में आईटी उद्योग स्थापित होते हैं, जिससे संगठित क्षेत्र में रोजगार तो बढ़ता ही है, असंगठित क्षेत्र में भी तरह-तरह के कामकाज का विस्तार होता है। माना जाता है कि विनिर्माण-केंद्र का एक कर्मचारी परोक्ष रूप से आठ आदमियों के लिए काम पैदा करता है। विनिर्माण क्षेत्र में 99 प्रतिशत श्रमिक असंगठित क्षेत्र से आते हैं। इस तरह संगठित क्षेत्र में रोजगार से असंगठित क्षेत्र को भी लाभ पहुंचता है, जो एक बड़ी आबादी के रोजगार की अभी धुरी है।

नए शहरों के साथ नई आपूर्ति-शृंखलाओं की भी शुरुआत होती है। जैसे-जैसे शहर विकसित होते रहते हैं, इन शृंखलाओं में शामिल मानव संसाधनों का भी विकास होता रहता है। इससे भी छोटे शहरों में रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं। चूंकि सैटेलाइट शहरों के बसने से मौजूदा बड़े शहरों पर आबादी और संसाधनों का बोझ कम होता है, इसलिए इन उप-नगरों को सरकारों व नागरिकों, दोनों के मुफीद माना जाता है। नए शहरों या उप-नगरों के लिए जल-संसाधन की उपलब्धता एक बड़ा पहलू है। किसी भी नगर को बसाने से पहले इसका सर्वे किया जाता है कि वहां बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता में किस तरह की मुश्किलें आ सकती हैं। इन सब कामों के लिए विशेष एजेंसी बनाई जाती है, जैसे नोएडा या नवी मुंबई में हमने देखा है। यह उस शहर के स्थानीय निकाय से अलग होकर काम करती है। हालांकि, बाद में उचित वक्त आने पर उनमें बदलाव किया जाता है या फिर स्थानीय निकाय में विलय।

एक बात और। इस तरह के उप-नगर इस संकल्पना के साथ बनाए जाते हैं कि उस उप-नगर के भीतर काम पर आने-जाने में 15 मिनट से अधिक का वक्त नहीं लगे। इसीलिए, इनमें आवाजाही के बेहतर साधन उपलब्ध कराए जाते हैं और सड़कों का निर्माण मानकों के अनुरूप किया जाता है। इन सबसे न सिर्फ यहां 'मोबिलिटी' अच्छी होती है, बल्कि बेहतर गुणवत्ता वाली शहरी सुविधाएं भी विकसित होती हैं। इनसे निजी व संस्थागत निवेश के द्वार खुलते हैं।

जाहिर है, हमें ऐसे नए शहरों की आज सख्त जरूरत है। इनसे हम उन त्रासदियों से भी बच सकते हैं, जो मौजूदा शहरों में वक्त-बेवक्त दिख जाते हैं। भला नोएडा के उस युवराज मेहता की क्या गलती थी, जिनकी जनवरी में एक निर्माणाधीन साइट के गहरे खुले नाले में गिरने से मौत हो गई? या फिर, दिल्ली के रोहिणी इलाके के उस प्रवासी मजदूर की मौत को किस रूप में लें, जिसकी खुले मैनहोल में गिरने जान चली गई? ये सब व्यवस्थागत नाकामी के परिणाम हैं। सैटेलाइट शहरों में इन सबकी गुंजाइश नाममात्र की होती है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

आधी आबादी से अधिकार छीनने का दौर बीत गया

यहां स्कैन करें

पुष्कर सिंह धामी | मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

आजाद भारत के इतिहास में 17 अप्रैल, 2026 की तारीख स्वर्ण अक्षरों में लिखी जानी थी, क्योंकि उस दिन हम 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' में संशोधनों के माध्यम से एक युगांतकारी परिवर्तन के साक्षी बनने जा रहे थे। यह एक वैधानिक दस्तावेज से अधिक भारत की नियति बदलने वाला महा-संकल्प था, पर पीड़ा का विषय है कि महिला सशक्तीकरण का यह ऐतिहासिक प्रस्ताव कांग्रेस और उसके सहयोगियों की संकीर्ण राजनीति के चलते अपेक्षित समर्थन के अभाव में दम तोड़ गया।

यह कितनी बड़ी विडंबना है कि रवांडा (विश्व में सर्वाधिक 61.3 प्रतिशत), क्यूबा (55.7 फीसदी) और मैक्सिको (50 प्रतिशत) जैसे देशों ने अपनी संसद में महिलाओं को 50 प्रतिशत से अधिक की भागीदारी दी है, वहीं हमारा विपक्ष आज भी 33 प्रतिशत के विचार से डरा हुआ है। विपक्षी दल चाहते हैं कि महिलाएं केवल रैलियों में भीड़ बढ़ाएं, न कि संसद और विधानसभाओं में बैठकर कानून बनाएं। इस विधेयक को पारित होने से रोकने के पीछे की मानसिकता तब और स्पष्ट हुई, जब विपक्ष ने नारी शक्ति का उपहास उड़ाने के लिए अभद्र शब्द तक का प्रयोग किया।

विपक्ष देश में महिला सशक्तीकरण की राह में बहुत समय तक अड़ंगे नहीं डाल सकेगा। इसका खामियाजा उसे भुगतना ही पड़ेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी सशक्तीकरण को लेकर कितने प्रतिबद्ध हैं, इसका अंदाज सिर्फ इस एक तथ्य से लग जाना चाहिए कि उन्होंने देश के सर्वोच्च पद के लिए उस समुदाय की द्रौपदी मुर्मु को चुना, जो सदियों से समाज में हाशिये पर रहा है। यही नहीं, केंद्र सरकार ने वर्ष 2026-27 के बजट में महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए 5.01 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 12 प्रतिशत अधिक है। उत्तराखंड सरकार का जेंडर बजट भी 19,692 करोड़ रुपये का है। यह राज्य के कुल बजट का लगभग 18 प्रतिशत है।

हमारी बहन-बेटियां पीछे न रहें, इसीलिए इतिहास रचते हुए मोदी सरकार ने पहली बार बेटियों को सेना में स्थायी कमीशन दिया, ताकि वे सरहदों की रक्षा के साथ-साथ सैन्य नेतृत्व भी करें। ऑपरेशन सिंदूर के समय व्योमिका सिंह और सोफिया कुरैशी जैसी बेटियों का गर्वोन्नत माथा पूरी दुनिया देख चुकी है, तो वहीं सेना की अग्रिम पंक्तियों में कैप्टन शिवा चौहान की तैनाती और राफेल उड़ाती शिवांगी सिंह बदलते भारत की ऐसी भव्य तस्वीरें हैं, जिन पर पूरी स्त्री जाति गर्व कर सकती है।

प्रधानमंत्री आवास योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, मुद्रा योजना और उज्ज्वला योजना जैसी अनेक योजनाओं से देश की महिलाओं, बेटियों के जीवन-स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वहीं, उत्तराखंड सरकार ने महिलाओं को राज्य में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का कानूनी सुरक्षा कवच प्रदान किया है, जो देश के लिए एक नजीर है। नंदा गौरा योजना के तहत हमने बेटियों को 51,000 रुपये तथा सशक्त बहना उत्सव योजना व मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तीकरण योजना के जरिये उनकी आर्थिक सहायता सुनिश्चित की है।

लोहाघाट में प्रदेश का प्रथम महिला स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री की लखपति दीदी योजना को देवभूमि उत्तराखंड के गांव-गांव तक पहुंचाया गया है, जिसकी बदौलत आज प्रदेश की 2 लाख, 65 हजार से अधिक बहनें न केवल अपने परिवार का संबल बनी हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी हैं। हमारी सरकार मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत महिला समूहों द्वारा निर्मित उत्पादों को ब्रांड के रूप में विकसित करने पर भी ध्यान दे रही है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना के जरिये हमने बेटी के जन्म को एक उत्सव में बदलकर लैंगिक समानता का परिचय दिया है, क्योंकि हम उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने को संकल्पबद्ध है।

आज की नारी मिट्टी से सोना उगाने वाली अन्नपूर्णा भी है और नई अर्थव्यवस्था रचने वाली उद्यमी भी। गांव के विकास का खाका खींचने वाली सरपंच से लेकर देश के हर कानून पर अंतिम मोहर लगाने वाली राष्ट्रपति तक, हर भूमिका में वह नेतृत्व कर रही है। ऐसे में, वह समान अधिकार के साथ नेतृत्व में भी बराबरी चाहती है। महिलाओं के हक के लिए हमारा न्याय-युद्ध जारी रहेगा, क्योंकि युद्ध भारत के उस कल का है, जब हर बेटी सुरक्षित होगी और शक्तिशाली भी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा

बुद्ध का जन्म अति दुर्लभ

बुद्ध का दूसरा नाम तथागत है, जो 'तथ्य' से बना है। जो अंधी श्रद्धा के आधार पर बात नहीं करता, बल्कि जो बात कहता है, वह तथ्यगत, वैज्ञानिक, सोची-विचारी हुई बात है। बुद्ध से पहले भारत में जो धर्म था, वह आस्था और विश्वास का धर्म था। बुद्ध के आने से धर्म ने वैज्ञानिक रूप लिया।

बुद्ध का एक अत्यंत प्रसिद्ध धम्मसूत्र है- मनुष्य का जीवित रहना भी दुर्लभ है, सद्धर्म का श्रवण करना भी दुर्लभ है और बुद्धों का उत्पन्न होना भी दुर्लभ है। मनुष्य होना दुर्लभ है, इसका अर्थ सिर्फ मानव शरीर प्राप्त करने से नहीं है, मनुष्य होने के बाद मैं अपनी मनुष्यता को समझ सकूं, पहचान सकूं, अपनी बुद्धि का उपयोग कर सकूं और चिंतन व विवेक द्वारा अपने जागरण में लग सकूं, यह दुर्लभ है। उसके बाद कह रहे हैं कि मनुष्य होकर जीवित रहना और दुर्लभ है। अगर तुम जीवित रह पाए, तो फिर जीवित रहते हुए सद्धर्म का पालन करने वाले बनो, यह और भी दुर्लभ बात है।

सत्य बोलना, दान देना, दया करना, क्षमा करना, प्रीति करना, विनम्र रहना, निरहंकार होना, मैत्री-भाव, मुदिता, ये सब सद्धर्म के गुण हैं। आपके मन में दया हो सकती है, सेवा भावना भी हो सकती है, पर मैत्री-भाव बड़ी कठिन बात है, क्योंकि हम मित्रता सिर्फ उन्हीं के साथ निभा पाते हैं, जिनसे हमें कुछ लाभ हो या लाभ होने की संभावना हो। बिना लाभ की इच्छा किए मैं दूसरों के प्रति प्रेम-भाव, मित्रता का भाव रखूं, यह बड़ा कठिन है।

सद्धर्म का पालन कोई तभी करेगा, जब सद्धर्म को श्रवण करेगा, धर्म का श्रवण तब करेगा, जब किसी जाग्रत व्यक्ति से मिलेगा। इसलिए बुद्ध सूत्र के आखिरी हिस्से में कहते हैं कि बुद्धों का उत्पन्न होना और भी दुर्लभ है। जिसको सुनकर, जिसको देखकर, जिससे मिलकर, मेरे चित्त में मनुष्य होने की इच्छा जगे और जीवन में धर्मपालन की इच्छा जगे, ऐसे बुद्धों का पृथ्वी पर पैदा होना और भी कठिन कार्य होता है। दुर्लभ से महान दुर्लभ बात है, किसी बुद्ध का जन्म होना।

बुद्ध पूर्णिमा वही दिन है, जब बुद्ध का जन्म हुआ था। एक बड़ी अद्भुत बात है कि पूर्णमासी के दिन बुद्ध का जन्म हुआ और पूर्णमासी के ही दिन उनको संबोधि भी प्राप्त हुई, फिर इसी पूर्णमासी पर उनका निर्वाण भी हुआ। यह एक बड़ी विलक्षण बात है कि जिस दिन जन्म हुआ, उसी दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई और पूर्णमासी को ही निर्वाण को प्राप्त हुए। मेरी दृष्टि में बुद्ध पूर्णिमा का दिन बहुत विशेष है। भले ही बुद्ध आज हमारे बीच नहीं हैं, भले ही तथागत चलते-फिरते हुए दिखते नहीं हैं, पच्चीस सौ वर्षों का अंतर पड़ गया है। पच्चीस सौ साल पहले बुद्ध चले गए, विदा हो गए, लेकिन इसके बावजूद बुद्धत्व की ऊर्जा का विस्फोट और वितरण अब भी होता है।

आज से लगभग पच्चीस सौ साल पहले बुद्ध इस नश्वर जगत से चले गए, लेकिन इसके बावजूद बुद्धत्व की ऊर्जा का विस्फोट और वितरण अब भी होता है।

आनंदमूर्ति गुरुमां

हिन्दुस्तान | 75 साल पहले 01 मई, 1951

हिंदू महासभा की राजनीति

देश में निकट भविष्य में आम चुनाव होने जा रहे हैं। अतः देश के विभिन्न दल- असाम्प्रदायिक और साम्प्रदायिक -उनमें हिस्सा लेने और कामयाब होने की चेष्टा में संलग्न हो गये हैं। भारतीय संविधान लोकतंत्र पर आधारित है और उसके अनुसार जो आम चुनाव होंगे, उनमें प्रत्येक दल को लोकमत को अपने पक्ष में बनाने की स्वतंत्रता होगी। वह अपने मन्तव्यों को मतदाताओं के सामने स्वतंत्रतापूर्वक रख सकेगा और उनके आधार पर उनका विश्वास संपादन करने का प्रयत्न कर सकेगा। भारतीय संविधान ने चुनावों की साम्प्रदायिक प्रणाली को खत्म कर दिया है। अब चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार को अमुक निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाले सभी जातियों के मतदाताओं का समर्थन प्राप्त करना होगा। किसी एक जाति विशेष के हितों की दुहाई देकर कोई उम्मीदवार कामयाब होने की आशा मुश्किल से ही कर सकेगा। जातिगत आधार पर पार्टियों का निर्माण भारतीय संविधान की भावना के विरुद्ध है; भले ही कानूनी रूप में इसमें कोई बाधा न हो।

देश स्वतंत्र हो गया और उसकी राजनीतिक भूमिका बदल चुकी, किन्तु हिन्दू महासभा का पुराना दृष्टिकोण अभी नहीं बदला है। यह हम अनुभव से जान चुके हैं कि साम्प्रदायिक संस्थाओं के राजनीति में टांग अड़ाने से बिगाड़ पैदा होता है। देश का जो विभाजन हुआ और विभाजन के पहले और बाद में जो मारकाट हुई, वह साम्प्रदायिक संस्थाओं के कुप्रचार का ही परिणाम थी। विभाजन के बाद मुस्लिम लीग मृतप्राय हो गयी है और जो मुसलमान भारत में रह गये हैं, उन्होंने अनुभव कर लिया है कि जातिगत आधार पर पृथक राजनीतिक मंच कायम रखना उनके लिए अहितकर होगा। हिन्दू महासभा यों कभी-प्राणवान संस्था नहीं रही। यदि उसने सामाजिक क्षेत्र में हिन्दुओं में रचनात्मक काम किया होता, तो उसका अस्तित्व कुछ तो सार्थक होता। हिन्दू समाज में छुआछूत, बाल-विवाह, पर्दा, जातिभेद आदि की सामाजिक बुराइयां फैली हुई हैं, उन्हें दूर करने में वह अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकती थी। किन्तु उसके नेता राजनीतिक मैदान में खेलने का लोभ संवरण नहीं कर पाये। राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का मोह हिन्दू महासभा को जीवित रखे हुए है और महासभाई नेता उसकी मुर्दा नसों में नया जीवन फूंकने की चेष्टा करते रहते हैं।

राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्री

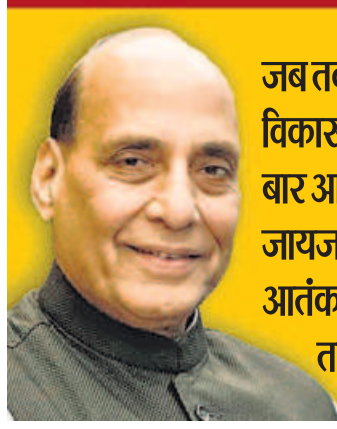

जब तक आतंकवाद है, यह सामूहिक शांति, विकास और समृद्धि को चुनौती देता रहेगा। कई बार आतंकवाद को मजहबी मुलम्मे में लपेटकर जायज ठहराने का प्रयास किया जाता है। यह आतंकवादियों को 'कवर फायर' देने जैसा है, ताकि वे धीरे-धीरे आगे बढ़ें।

श्रमिकों में असंतोष होना चिंताजनक

कहने को तो आज (1 मई) मजदूरों के सम्मान और उनके योगदान को याद करने का दिन है, किंतु राष्ट्र का विकास करने वाले मजदूरों की स्थिति आज भी बहुत अच्छी नहीं है। यह बहुत चिंता की बात है कि उनको अपनी मांगों, विशेषकर वेतन-वृद्धि के लिए आंदोलन करना पड़ता है और सब्र का बांध टूटने पर हिंसा का सहारा लेना पड़ता है। वे मजबूरीवश तोड़फोड़, चक्का-जाम, आगजनी या पुलिस से टकराव जैसी हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं। यह याद रखना चाहिए कि सब्र का बांध कोई एक-दो दिन में नहीं टूटता। यह लंबे समय तक बर्दाश्त करने के बाद ही टूटता है, जिसके लिए ठेकेदारों का शोषण, सुविधाओं की कमी, काम के घंटे अधिक होना, कम मजदूरी और बेलगाम बढ़ती महंगाई की मार प्रमुख रूप से जिम्मेदार हैं। 13 अप्रैल की ही बात है, नोएडा की घटना हमें यह सोचने पर विवश करती है कि श्रमिकों का वेतन आखिर इतना कम क्यों है कि वे सम्मानजनक जीवन भी न जी सकें या अपने दायित्वों का निर्वहन न कर सकें?

आज का यही सच है कि श्रमिकों को तय मानकों के अनुसार ठेकेदार भुगतान नहीं करते और ओवरटाइम का पैसा देने से कतराते हैं। श्रमिकों के लिए जरूरी सुविधाओं की कोई बात ही नहीं करता। देश के सभी राज्यों में श्रमिकों के लिए असमान मजदूरी दर असंतोष को जन्म देती है। ऐसे में, स्वाभाविक है कि वे अन्य राज्यों से अपनी मजदूरी की तुलना करते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि उनकी मजदूरी से पेट पालना भी मुश्किल है, तो वे पहले विरोध करते हैं और फिर प्रदर्शन करने को मजबूर होते हैं।

न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि का असर स्पष्ट रूप से उद्यमियों पर पड़ता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी में की गई 21 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा के बाद उद्यमियों का तर्क है कि टैरिफ, ईरान युद्ध और अब न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की मार से कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा और संभव है कि कइयों को बंद करना पड़ सकता है। इसका विपरीत प्रभाव उपभोक्ताओं पर होगा। उत्पादन लागत बढ़ने से उत्पादों के दाम बढ़ जाएंगे। ऐसे में, सरकारों को चाहिए कि वह न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि के लिए श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले आंदोलनों का रास्ता न देखे, बल्कि महंगाई बढ़ने के साथ समय-समय पर मजदूरी दर का मूल्यांकन कर उसमें वृद्धि करे। सरकार का लक्ष्य सिर्फ वेतन-वृद्धि तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि श्रमिकों के जीवनस्तर में सुधार लाना भी होना चाहिए। मजदूर दिवस की सार्थकता भी तभी है।

रामबाबू सोनी, टिप्पणीकार

अनुलोम-विलोम

मजदूर दिवस

मजदूरों के हित में हो रहे कई काम

यह सभी चाहते हैं कि मजदूरों की दशा सुधरनी चाहिए। इस दिशा में काम हो भी रहा है। मजदूरों के जीवन से दो पहलू जुड़े हुए हैं। पहला- रोजगार की उपलब्धता और दूसरा- उचित मजदूरी। पहले, रोजगार की बात। भारत में रोजगार में लगातार वृद्धि हो रही है। 2017-18 में 47.5 करोड़ लोगों के पास रोजगार था, जो 2023-24 में बढ़कर 64.3 करोड़ हो चुका है। यानी, छह वर्षों में 16.83 करोड़ नए रोजगार का सृजन हुआ। इसका असर बेरोजगारी दर पर भी पड़ा है। जो बेरोजगारी दर साल 2017-18 में छह फीसदी थी, वह 2023-24 में घटकर 3.2 प्रतिशत रह गई। इसी तरह, पिछले सात वर्षों में 1.56 करोड़ महिलाएं औपचारिक कार्यबल में शामिल हुई हैं।

एक ऐतिहासिक फैसला चार श्रम संहिताओं को लागू करने का भी है। ये चारों संहिताएं हैं- वेतन संहिता-2019, औद्योगिक संबंध संहिता-2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता-2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य शर्त संहिता-2020। इनको पिछले साल 21 नवंबर को लागू किया गया। 29 मौजूदा श्रम कानूनों को हटाकर इनको बनाया गया है। श्रम नियमावली को आधुनिक बनाकर, मजदूरों की भलाई को बढ़ाकर और श्रम पारिस्थितिकी तंत्र को काम की बदलती दुनिया के साथ जोड़कर, यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया, ताकि भविष्य के लिए अच्छा और मजबूत कार्यबल तैयार हो सके। यह ऐसा कार्यबल हो, जो उद्योग-अनुकूल हो व आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में मदद करे। इसी तरह, पिछले एक दशक में देश में सामाजिक-सुरक्षा कवरेज का भी बड़े पैमाने पर विस्तार किया गया है। साल 2015 में कार्यबल के लगभग 19 प्रतिशत श्रमिकों को यह सुविधा हासिल थी, जिसका दायरा 2025 में बढ़कर 64 प्रतिशत से अधिक हो गया।

बीते कुछ वर्षों में महिला कामगारों पर भी खास तौर से ध्यान दिया गया है। इनको हाशिये से मुख्यधारा में लाने के ठोस प्रयास हो रहे हैं, जिनका असर भी दिख रहा है। चूंकि 2047 तक भारत को विकसित देश की कतार में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है, इसलिए सरकार की कोशिश महिला कार्यबल को अधिक से अधिक बढ़ाने की है। आज, प्रमुख वैश्विक संस्थान भारत की प्रशंसा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि यह उच्चतम समानता वाले शीर्ष देशों की सूची में शामिल होने वाला है। निस्संदेह, कुछ चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं, विशेषकर वेतन में सुधार को लेकर, पर इसका मतलब यह नहीं है कि श्रमिकों की बिल्कुल भी सुध नहीं ली जा रही। सरकार उनके हित में लगातार सक्रिय है।

दीप्ति, टिप्पणीकार

इन्हेलर का कैसे करें चुनाव

दमा, फेफड़ों से जुड़ी ऐसी बीमारी है, जिसमें इंसान ठीक से सांस नहीं ले पाता है। दमा को काबू में रखने के लिए इन्हेलर एक कारगर चिकित्सा-उपकरण है, जो दवा को सीधे फेफड़ों तक पहुंचाता है। इसके बावजूद, सही तकनीक न पता होने और कई गलतफहमियों के कारण लोग इसका पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। इन्हेलर का कैसे करें चुनाव और उपयोग, बता रही हैं अवंतिका सिंह

दुनियाभर में मई माह के पहले मंगलवार को अस्थमा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम रखी गई है-अस्थमा से पीड़ित हर व्यक्ति तक इन्हेलर्स की पहुंच। भारत में तकरीबन 35 लाख लोग दमा रोगी हैं। बड़ी संख्या में लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है। इनमें से ज्यादातर को नियमित या आपातकालीन स्थिति के लिए इन्हेलर की जरूरत पड़ती है।

इन्हेलर दवा को सीधे फेफड़ों और सांस की नली तक पहुंचाते हैं। गोलियों के मुकाबले इनके दो बड़े फायदे हैं- पहला, दवा सीधे वहां पहुंचती है, जहां उसकी जरूरत है। दूसरा, दवा पूरे शरीर में नहीं फैलती, इसलिए साइड इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। इन्हेलर दमा रोगियों की जिंदगी आसान बनाता है, उनकी जान बचाता है। हालांकि, ज्यादातर लोग इन्हेलर का सही इस्तेमाल नहीं करते। दवा की मात्रा में मनमर्जी करते हैं। 'द जर्नल ऑफ एलर्जी एंड क्लीनिकल इम्यूनोलॉजी' में छपे एक शोध के अनुसार, 40 फीसदी दमा रोगी इन्हेलर्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि सही नहीं।

तीन तरह के इन्हेलर

1. **रिलीवर (रिस्क्यू इन्हेलर) :** ये इमरजेंसी टूल की तरह काम करते हैं। अचानक सांस लेने में तकलीफ, खांसी होने पर, तुरंत सांस की नली से जुड़ी मांसपेशियों को आराम देते हैं। इसे दमा अटैक के दौरान या डॉक्टर की सलाह पर व्यायाम-खेलकूद से पहले लिया जाता है।
2. **प्रिवेंटर (कंट्रोलर इन्हेलर):** इन्हें रोज लेना होता है, भले ही लक्षण नियंत्रित रहें। इन इन्हेलर में कम मात्रा में कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होते हैं, जो वायुमार्ग की सूजन व जलन कम करते हैं। भावी अस्थमा अटैक रोकने में मदद मिलती है। इन्हें खुद से लेना बंद नहीं करना चाहिए।
3. **कॉम्बिनेशन इन्हेलर्स:** मध्यम से गंभीर दमा के लिए डॉक्टर ऐसे इन्हेलर देते हैं, जिनमें सूजन कम करने वाली दवा और वायुमार्ग को देर तक खुला रखने वाली दवा, दोनों शामिल होती हैं।

जरूरत और सही तरीका जानना जरूरी

- **मीटर्ड-डोज इन्हेलर (एमडीआई):** यह सबसे आम प्रकार है, जिसे पफ मशीन भी कहते हैं। इसमें एक स्प्रे कैनिस्टर होता है। इसे दबाने और उसी समय सांस खींचने में तालमेल की जरूरत होती है। इसके सही इस्तेमाल का तरीका ये है कि पहले इन्हेलर को 5 सेकंड तक अच्छी तरह हिलाएं। पहले पूरी सांस बाहर निकाल दें। माउथपीस दांतों के बीच रखें व होंठों से कसकर सील करें, फिर जैसे ही धीरे-धीरे सांस लेना शुरू करें, कैनिस्टर को दबाएं। दवा लेने के बाद 5-10 सेकंड तक सांस रोकें, ताकि दवा फेफड़ों में बैठ सके।
- **ड्राई पाउडर इन्हेलर (डीपीआई):** इसमें दवा पाउडर के रूप में होती है। आपको जोर से गहरी सांस खींचनी होती है, ताकि पाउडर फेफड़ों में जा सके।
- **सॉफ्ट मिस्ट इन्हेलर (एसएमआई):** यह दवा को हल्की धुंध की तरह छोड़ता है, जिससे इसे सांस के साथ अंदर लेना आसान हो जाता है।

इन्हेलर के चुनाव में ध्यान देने वाली बातें

- कैलाश अस्पताल में वरिष्ठ सांस रोग विशेषज्ञ डॉ. ललित मिश्रा के अनुसार, 'बच्चों के लिए अक्सर स्पेसर के साथ एमडीआई की सलाह दी जाती है। यह इन्हेलर दवा की एक तय मात्रा को फुहार के रूप में छोड़ता है। इसमें स्पेसर होता है, जो चैंबर की तरह काम करता है। बच्चे को पंप दबने के तुरंत बाद सांस खींचने की हड़बड़ी नहीं होती। बिना स्पेसर दवा का ज्यादातर हिस्सा गले के पिछले हिस्से या जीभ पर चिपक जाता है। स्टेरॉएड वाली दवाएं, अगर मुंह में रह जाएं, तो फंगल इन्फेक्शन का खतरा रहता है।
- बहुत कमजोर फेफड़ों वाले लोग शायद डीपीआई (ड्राई पाउडर इन्हेलर) का उपयोग न कर पाएं। दवा बाहर निकालने व फेफड़ों की गहराई तक पहुंचाने के लिए मरीज को तेज व गहरी सांस की जरूरत होती है। फेफड़े कमजोर होने पर इसमें दिक्कत आती है। बुजुर्गों के लिए दबाने में आसान सॉफ्ट मिस्ट इन्हेलर बेहतर माने जाते हैं।
- हमेशा डोज काउंटर वाला इन्हेलर लें, ताकि पता रहे कि दवा कब खत्म होने वाली है।

10
में से एक बच्चा दुनिया में दमा से जूझ रहा है।

13
करोड़ लोग विश्व में दमा से पीड़ित हैं। अकेले भारत में करीब 35 लाख लोग अस्थमा से जूझ रहे हैं।
स्रोत : ग्लोबल अस्थमा नेटवर्क

भ्रांतियां और सच

भ्रांति : इन्हेलर की लत लग जाती है
सच: अस्थमा इन्हेलर्स में ऐसी दवाएं होती हैं, जो वायुमार्ग खोलने और सूजन कम करने में मदद करती हैं, जिससे व्यक्ति आसानी से सांस ले पाता है। ये दवाएं नशीली नहीं होतीं और इनसे किसी भी तरह की लत पैदा नहीं होती।
भ्रांति : इन्हेलर यानी मामला गंभीर है
सच: दमा हल्का है या गंभीर, यह लंबे समय तक रहने वाली समस्या है। इन्हेलर से सामान्य जीवन जीने में मदद मिलती है। आपातकालीन दवाओं की जरूरत कम पड़ती है।
भ्रांति : दवा खुद से कम की जा सकती है।
सच : आपका अस्थमा पिछले तीन माह से नियंत्रित है, तो डॉक्टर दवा कम कर सकते हैं, लेकिन फैसला खुद से न लें।
भ्रांति : गर्भावस्था में इन्हेलर का इस्तेमाल न करें
सच: गर्भावस्था में दमा काबू रखना जरूरी है, ताकि बच्चे को ऑक्सीजन मिलती रहे। हालांकि, इस संबंध में अपने डॉक्टर से बात जरूर करें।
भ्रांति : बच्चों के लिए इन्हेलर सुरक्षित नहीं हैं
सच: अगर डॉक्टर ने बच्चे के लिए इसे कहा है, तो यकीन मानिए कि यह सुरक्षित है। बच्चे स्पेसर डिवाइस या मास्क की मदद से आसानी से इन्हेलर का उपयोग कर सकते हैं।
-**डॉ. वेद प्रकाश,** एचओडी, पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन, केजीएमयू, लखनऊ

रख-रखाव और सफाई का रखें ध्यान

इन्हेलर एक संवेदनशील उपकरण है। हफ्ते में एक बार प्लास्टिक होल्डर को निकालकर गुनगुने पानी से धोएं। दवा वाले मेटल कैनिस्टर को कभी पानी में न डालें। इसे सीधे धूप में भी न रखें। अत्यधिक गर्मी (जैसे कार के अंदर) से प्रोपेलेंट गैस का दबाव बढ़ सकता है और कैनिस्टर फट सकता है। एक्सपायरी डेट के बाद इनका इस्तेमाल न करें। अगर इन्हेलर कई दिनों तक इस्तेमाल नहीं किया है, तो उपयोग करने से पहले हवा में एक-दो बार टेस्ट पफ छोड़ें। दवा लेने के बाद कुल्ला जरूर करें। यह गले की खराश व संक्रमण को रोकता है।

विशेषज्ञ की राय

डॉ. वेद प्रकाश के अनुसार, 'अगर आप हफ्ते में दो बार से ज्यादा अपना रेस्क्यू इन्हेलर इस्तेमाल कर रहे हैं या एक दिन में चार बार से ज्यादा रेस्क्यू इन्हेलर लेने की नौबत पड़ जाती है, तो डॉक्टर से मिलें। खुराक के संबंध में कोई फैसला लेने से पहले यह सुनिश्चित करें कि आप इन्हेलर का इस्तेमाल सही ढंग से कर रहे हैं।'
दवाओं के बावजूद अस्थमा प्रबंधन में निम्न बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है-

दमा, एलर्जिक होता है। ट्रिगर करने वाले कारक जैसे, धूल, धुआं, पशु व जानवरों के फर आदि से बचें। बदलते मौसम में विशेष सावधानी बरतें।

दवाएं और इन्हेलर साथ रखें। प्रदूषण व ठंडी हवा से बचने के लिए मास्क पहनकर बाहर निकलें। दवा की मात्रा में कोई भी फेरबदल खुद से न करें।

नियमित रूप से हल्का व्यायाम करें। खासकर फेफड़ों को मजबूत बनाने वाले व्यायाम, श्वास अभ्यास करें। पर्याप्त पानी पिएं।

हफ्ते में दो बार से ज्यादा खांसी, घरघराहट या सीने में जकड़न लगे, बार-बार नींद टूटे व सामान्य काम करने में सांस फूलने लगे तो डॉक्टर से मिलें।

इन्हेलर का इतिहास

आधुनिक इन्हेलर का आविष्कार 1956 में अमेरिकी डॉक्टर जॉर्ज मैसन ने किया था। डॉ. मैसन की बेटी दमा से पीड़ित थी। एक दिन उसने झुंझलाकर अपने पिता से कहा, 'क्या मेरी दवा को 'परफ्यूम स्प्रे' की तरह नहीं बनाया सकता?' डॉ. मैसन तब लॉस एंजिल्स में राइकर लेबोरेटरीज के अध्यक्ष थे। उन्होंने टीम के साथ एक ऐसी डिवाइस तैयार की जो दबाव का उपयोग करके दवा की एक सटीक मात्रा बाहर छोड़ती थी। यह वह तकनीक थी, जो हेयरस्प्रे आदि में उपयोग की जाती थी।

नेबुलाइजर और रोटाहेलर भी उपयोगी

नेबुलाइजर : यह एक बिजली से चलने वाली मशीन है। इसमें तरल दवा डालते हैं, जो मास्क के जरिये भाप बनकर नाक और मुंह तक पहुंचती है। यह छोटे बच्चों के अलावा उन मरीजों के लिए है, जो बहुत ज्यादा कमजोर हैं या बेहोश हैं।
रोटाहेलर : इसे कैप्सूल वाली मशीन कहते हैं। मशीन ही कैप्सूल खोलती है और मरीज पाउडर को पफ के जरिये अंदर खींचता है। गैस वाले स्प्रे से खांसी जिन्हें होती है, उनके लिए यह बढ़िया है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रश्न: क्या सभी अस्थमा इन्हेलर एक जैसे होते हैं?
उत्तर: नहीं, कुछ इन्हेलर अस्थमा अटैक के दौरान तुरंत राहत देते हैं, जबकि प्रिवेंटर इन्हेलर का उपयोग लक्षण रोकने के लिए रोजाना किया जाता है। यदि डॉक्टर ने प्रिवेंटर इन्हेलर बताया है, तो लक्षण न होने पर भी इसे रोज लें।
प्रश्न: क्या मैं इन्हेलर दूसरों संग साझा कर सकता हूं?
उत्तर: नहीं। हर मरीज की हालत और जरूरत अलग होती है।
प्रश्न: इन्हेलर के साइड इफेक्ट्स क्या हैं?
उत्तर: कुछ लोगों को गले में खराश या हाथों में हल्का कंपन हो सकता है। आमतौर पर ये लक्षण अस्थायी होते हैं।
-**डॉ. जितेंद्र प्रियदर्शी,** वरिष्ठ पल्मोनोलॉजिस्ट, फेलिस्क अस्पताल नोएडा

सवाल-जवाब

न्यूरोफाइब्रोमा से घबराएं नहीं

डॉ. राजुल अग्रवाल
डायरेक्टर- न्यूरोलॉजी, श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट, दिल्ली

सवाल : मेरे बेटे को न्यूरोफाइब्रोमा है। पहले दाने छोटे थे, अब वे बड़े हो रहे हैं। ऐसा पूरे शरीर में है। हम क्या करें?
जवाब: ये लक्षण न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस टाइप-1 का संकेत करते हैं। यह एक आनुवंशिक बीमारी है, जिसमें त्वचा की नसों पर गांठें बढ़ती चली जाती हैं। सबसे पहले इन गांठों की बायोप्सी की जाती है कि यह न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस है या कुछ और। इसके साथ डर्मेटोलॉजिस्ट और जेनेटिक काउंसलर की भी जरूरत पड़ती है। अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी है, जिससे इसे पूरी तरह ठीक किया जा सके। अगर ये गांठें समस्या नहीं कर रही हैं, तो बस नियमित निगरानी करते रहें।

अगर यह गांठें तेजी से बढ़ रही हों या उसकी वजह से नस पर दबाव पड़ने के कारण तेज दर्द हो, तो ऐसे में सर्जरी से इन्हें हटाया जा सकता है। जिन मरीजों की गांठों का ऑपरेशन संभव नहीं है या जिनमें प्लेक्सीफॉर्म न्यूरोफाइब्रोमा होता है, खासकर बच्चों में, वहां दवा का इस्तेमाल करते हैं। यह एक नई दवा है। अगर आंखों की नस, रीड की हड्डी या फिर कान की नस पर गांठ है, जिससे खतरा बढ़ सकता हो, तो सर्जरी जरूरी है।

सवाल : मेरी पत्नी की उम्र 55 वर्ष है। ऐसा लगता है कि उनकी याद्दाश्त कम हो रही है। वह हालिया बातें भूल जाती है। क्या यह अल्जाइमर्स की शुरुआत है? हमें करना चाहिए?
जवाब : याद रखें, हर भूलना अल्जाइमर्स नहीं होता। कई बार मेटाबॉलिक कारणों में भी भूलने की समस्या होती है। थायरॉइड की कमी, विटामिन बी-12, फोलिक एसिड की कमी, नींद न आना, तनाव, डिप्रेशन या माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट का भी मेमोरी पर असर पड़ सकता है। ऐसे में जांच जरूरी है।

याददाश्त कम होना, दो तरह से होता है। रिवर्सिबल मेमोरी लॉस, जिसमें मेमोरी लॉस के कारण की पहचान होने पर उसके उपचार से उसे रिवर्स कर दिया जाता है। कुछ डिजनरेटिव डिजीज होती हैं, जिन्हें रिवर्स नहीं कर सकते हैं, पर आगे बढ़ने से रोक सकते हैं।

आप किसी डॉक्टर व न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें। वे एमआरआई व मेटाबॉलिक डिसॉर्डर संबंधी जांच करा सकते हैं। फिलहाल, बचाव के तौर पर ठीक टाइम पर सोएं। संतुलित भोजन करें। दूसरों से मिलें-जुलें। बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें।

हीमोग्लोबिन बढ़ाने के आसान तरीके

आहार व पोषण विशेषज्ञ रुजुता दिवाकर अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट पर आयरन की कुदरती ढंग से पूर्ति करने के लिए निम्न सुझाव देती हैं-

1. मौसमी फल खाएं। जैसे, गर्मियों में आम, इनमें विटामिन सी होता है, जो आयरन सोखने में मदद करता है। इसके अलावा अमरूद व खुबानी खाएं।
2. दालें व फलियां खाएं। मूंग, अरहर, चना, मटकी आदि दालें अमीनो एसिड, विटामिन बी व फाइबर से भरपूर होती हैं। इन्हें चावल या चपाती के साथ खाएं।
3. दही और लस्सी का सेवन करें। विटामिन बी-12 बढ़ाने के लिए इन्हें नाश्ते या दोपहर के भोजन में खाएं।
4. गुड़ और चना मिलाकर खाएं।
5. खाना लोहे की कड़ाही व बर्तनों में बनाएं। हीमोग्लोबिन बेहतर होने से थायरॉइड व ओवरी की कार्यक्षमता भी बेहतर हो जाती है।

किन चीजों से बचें?
- **शराब :** आयरन सोखने की क्षमता कम करती है।
- **ब्लैक कॉफी :** अधिक कैफीन युक्त चीजों से बचें।
- **जूस और स्मूदी :** रोजाना अधिक जूस, स्मूदी या लैक्सेटिव्स का सेवन आयरन के अवशोषण में बाधा पहुंचाता है। इसी तरह केवल सलाद पर निर्भर न रहें।

भेजें अपने सवाल

सेहत से जुड़े सवाल
tanmanhindustan@gmail.com पर मेल करें। आप इस पते पर भी सवाल भेज सकते हैं-
तन-मन, हिन्दुस्तान, 11वां तल, द आइकॉन टॉवर, एफ सी-24 सी, फिल्म सिटी, सेक्टर-16ए, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर-201301

नरम और सख्त पेट का फर्क समझें

पेट की चर्बी केवल मोटापे का संकेत नहीं है। खासकर, विसरल फैट का जमा होना सेहत से जुड़े खतरों की आशंका बढ़ा सकता है।

पेट नरम है या सख्त, इससे हमारी सेहत से जुड़े खतरों के बारे में पता है। आईएसआईसी अस्पताल के गेस्ट्रोएंटेरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शुभम वत्स की इंस्टाग्राम पोस्ट के अनुसार, 'अगर पेट छूने या हल्का दबाने पर नरम महसूस होता है, तो यह सतही वसा है, जिसे सबक्यूटेनियस फैट भी कहते हैं। यह वसा त्वचा के ठीक नीचे जमा होती है, आसानी से पकड़ में आ जाती है। सबक्यूटेनियस फैट से मेटाबॉलिक रोगों का खतरा कम होता है। इस चर्बी को नियमित व्यायाम, टहलना, दौड़ना व संतुलित आहार से कम किया जा सकता है।

जिद्दी चर्बी से बचें

डॉ. शुभम के अनुसार, 'सख्त पेट यानी विसरल फैट। यह वसा अधिक गहराई में, अंदरूनी अंगों के चारों ओर जमा होती है। विसरल फैट से शरीर में सूजन पैदा करने वाले रसायन व तनाव का स्राव बढ़ता है, जिससे इंसुलिन प्रतिरोध, फैटी लिवर, उच्च रक्तचाप व हृदय रोग हो सकते हैं। इस वसा को कम करने के लिए जीवनशैली से लेकर खानपान में सुधार करना जरूरी हो जाता है।

- सक्रिय जीवनशैली अपनाएं। सप्ताह में कम से कम 5 दिन, आधा घंटा व्यायाम करें। इसमें कार्डियो, वेट ट्रेनिंग, तैराकी व पैदल चलना शामिल है। बेहतर है कि तेज गति से चलें।
- प्रोटीन, विटामिन व मिनरल से भरपूर भोजन करें। जंक फूड, अधिक तेल व चीनी कम खाएं। विसरल फैट के जमा होने में जंक फूड की बड़ी भूमिका है।
- रोज कम से कम 7-8 घंटे सोएं। नींद में हमारा शरीर कैलोरी की खपत करता है। तनाव कम करने के लिए योग व ध्यान करें।

रोजनामचा

पं. राघवेन्द्र शर्मा
ज्योतिषाचार्य

मेष : किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में वृद्धि हो सकती है। भागदौड़ अधिक रहेगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। कारोबार के लिए विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं।

वृष : आत्मसंयत रहें। बेकार के क्रोध से बचें। बातचीत में संतुलित रहें। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। शैक्षिक कार्यों में बाधा आ सकती है।

मिथुन : आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कारोबार में सुधार होगा। लाभ के अवसर मिलेंगे। पिता का साथ मिलेगा। वाहन के रख-रखाव तथा वस्त्रों पर खर्च बढ़ेंगे।

कर्क : मन में शांति व प्रसन्नता रहेगी। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। किसी दूसरे स्थान पर जाने का योग।

सिंह : मन परेशान हो सकता है। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। भागदौड़ अधिक रहेगी। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। सेहत का ध्यान रखें।

कन्या : मन परेशान रहेगा। संयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखें। भागदौड़ अधिक रहेगी। कारोबार में वृद्धि होगी। लाभ के आवसर मिलेंगे। सेहत का ध्यान रखें।

तुला : आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। किसी मित्र के सहयोग से किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। लाभ के अवसर मिलेंगे।

वृश्चिक : मन परेशान हो सकता है। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान पर जा सकते हैं। पिता की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

धनु : आत्मविश्वास भरपूर रहेगा, परंतु मन में उतार-चढ़ाव भी हो सकते हैं। लेखनादि बौद्धिक कार्यों से मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें।

मकर : मन प्रसन्न रहेगा। दांपत्य सुख में वृद्धि होगी। किसी रुके धन की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिल सकती है। परिश्रम बढ़ेगा।

कुंभ : पठन-पाठन में रुचि रहेगी। बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। कारोबार से भागदौड़ अधिक रहेगी। पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है।

मीन : मन परेशान हो सकता है। आत्मसंयत रहें। धैर्यशीलता बनाए रखने का प्रयास करें। नौकरी में अफसरों का सहयोग मिलेगा। तरक्की के साथ बदलाव के योग हैं।

स्कैन करें
भविष्यफल और व्रत-त्योहार जानने के लिए

व्रत और त्योहार | पंचांग | पं. ऋभुकांत गोस्वामी

01 मई, शुक्रवार, **शक संवत्** : 11 वैशाख (सौर) 1948, **पंजाब पंचांग** : 18 वैशाख मास प्रविष्टे 2083, **इस्लाम** : 13 जिल्काद, 1447, **विक्रमी संवत्:** वैशाख शुक्ल पूर्णिमा तिथि रात्रि 10.53 बजे तक पश्चात प्रतिपदा तिथि, स्वाती नक्षत्र रात्रि 04.36 बजे तक विष्टि (भद्रा) करण प्रात: 10.03 बजे तक। चंद्रमा तुला राशि में (दिन-रात)।

सूर्य उत्तरायण। सूर्य उत्तर गोल। प्रात: 10.30 बजे से दोपहर 12 बजे तक राहुकालम्। वैशाख पूर्णिमा। श्री बुद्ध जयंती। श्री कूर्म जयंती। महर्षि भृगु जयंती।

वास्तु सलाह | आचार्य मुकुल रस्तोगी

हमारा एक छोटा सा व्यवसाय है। छोटी सी जगह है। समस्या यह है कि हमारा पैसा मार में बहुत जाता है। पार्टी पैसा रोक लेती है। -एकता, झारखंड

- आपका जो व्यावसायिक स्थान है, उसमें कुछ ऐसे दोष हैं, जिनके कारण समस्या आ रही है। आपके मुख्यद्वार के ठीक सामने दो द्वार और हैं, जो पीछे सड़क पर खुलते है। यह गलत है। इसके कारण धन आने के साथ जाने के रास्ते तेजी से बनते हैं।
- आपने सेप्टिक टैंक भी ब्रह्मस्थान से बहुत पास में बनवाया है, इसे तुरंत हटाएं। साथ ही कोई भी एक दरवाजा बंद कर दीजिए। पश्चिम दिशा में एक चमेली के तेल का दिया जलाया कीजिए। नित्य प्रति मंगलवार को बंदरों को गुड़-चना खिलाएं।

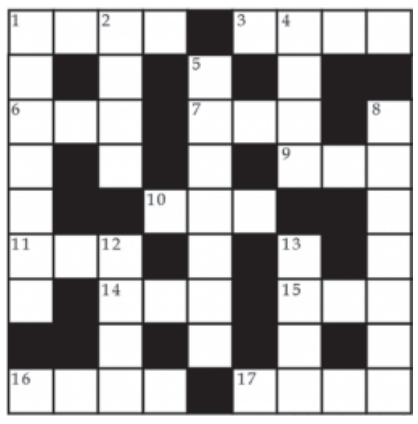

वर्ग पहेली : 8315

बाएं से दाएं
1. ऊपर से टपकना; पानी गिरना; वर्षा होना (4)
3. आलिंगन करना; चिपटना; लिपटना; सटना; जुड़ना; पकड़ना; लगना (4)
6. धनुष; मेहराब; आदेश; सेना का अंग (3)
7. खोद कर लगाना; छिपा कर रखना; दबाना; दफनाना (3)
9. केवट; नाव खेवने वाला; मांझी (3)
10. फैलाना; बिखेरना; मार कर गिरा देना (3)
11. गुंदे आटे में आया उभार; गुंदे आटे में आई खटास; किण्व; पॉस (3)
14. झोंका; बयार; बहती हवा; पवन (3)
15. तीन घंटे का समय; दिन का आठवां भाग (3)
16. दुरुस्त होना; दोष दूर होना; त्रुटि दूर होना; (4)
17. आज्ञा-पत्र; आदेश; पतंगा (4)

ऊपर से नीचे
1. अच्छे रिश्ते बना कर रहना; अच्छे संबंध बनाना (2,2,3)
2. तुल्यता; बराबरी (4)
4. किसी अधिकारी के पद का सूचक (4)
5. बहानेबाजी करना; हिचकना (2,2,3)
8. चर्चा करवाना; तर्क-वितर्क करवाना; वाद-विवाद करवाना (3,4)
12. जायकेदार; शोरबेदार; रसयुक्त; रसवाला; रसीला (4)
13. उद्धार; कल्याण; नेकी; भलाई (4)

हरीश चन्द्र सन्सी, विविधा विधा, दिल्ली
(उत्तर अगले अंक में)

वर्ग पहेली : 8314

हा	ल	त		ति	ल	मि	ला	ना
थ		म	शा	ल		ता		
से	व	क		ति	रा	हा		आ
नि		श		ल		री	झ	ना
क			झु	क	ना			का
ल	ह	र		र		पु		नी
ना		स	क्ष	म		का	र	क
		दा		र	प्ता	र		र
दू	र	र	ह	ना		ना	प	ना

सुडोकू : 8297

*आसान

	3					5		
8		7		5				
5			8		7	4	3	
	9	6	2					
			6		1			
					9	7	8	
	2	3	1		4			7
				8		9		1
		9					6	

खेलने का तरीका : दिमागी खेल और नंबरों की पहेली है यह। ऊपर नौ-नौ खानों के नौ खाने दिए गए हैं। आपको 1 से 9 की संख्याएं इस तरह लिखनी हैं कि खड़ी और पड़ी लाइनों के हरेक खाने में 1 से 9 की सभी संख्याएं आएं। साथ ही 3x3 के हरेक बक्से में भी 1 से 9 तक की संख्याएं हों। पहेली का हल हम कल देंगे।

सुडोकू : 8296

1	8	2	4	3	7	9	5	6
9	3	4	5	6	2	7	8	1
5	7	6	8	1	9	4	3	2
3	5	1	2	7	8	6	4	9
6	9	7	1	5	4	8	2	3
4	2	8	6	9	3	5	1	7
8	4	3	7	2	6	1	9	5
7	1	9	3	4	5	2	6	8
2	6	5	9	8	1	3	7	4